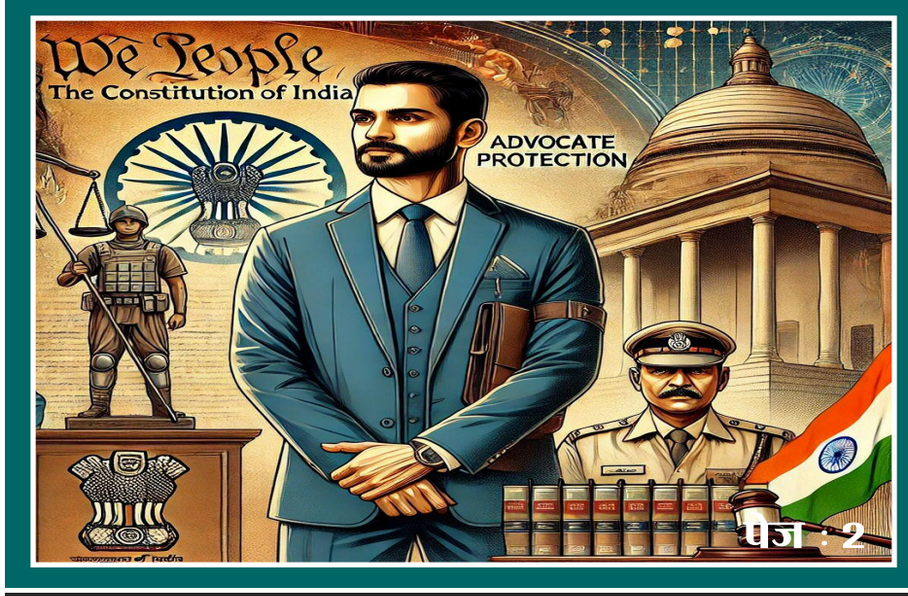

पेज : 2

पेज : 4

राष्ट्रीय हिंदी दैनिक

सबसे बड़ी खबर

भत्य खबर

RNI No.- DELHIN/2016/68043

नई दिल्ली संस्करण, नई दिल्ली, बुधवार, 26 मार्च 2025, वर्ष : 8, अंक : 360 पृष्ठ : 08, मूल्य : 02 रुपया

नई दिल्ली से प्रकाशित व दिल्ली, एनसीआर, यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, झारखण्ड, महाराष्ट्र, गुजरात में प्रसारित

हवाला के पैसों से सोना खरीदा, सोना तस्करी मामले में रान्या राव का बड़ा कबूलनामा

नई दिल्ली। इस महीने की शुरुआत में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर 14.8 किलोग्राम सोने के साथ गिरफ्तार कन्नड़ अभिनेता रान्या राव ने कबूल किया है कि सोने की खरीद के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा हवाला चैनलों के जरिए भेजा गया था, तस्करी रोधी एजेंसी डीआरआई ने मंगलवार को एक अदालत को बताया। रान्या राव की जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान, डीआरआई का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील मधु राव ने कहा कि अधिकारियों ने अभिनेता के खिलाफ न्यायिक जांच शुरू करने के लिए धारा 108 के तहत नोटिस जारी किया है। जांच का उद्देश्य वित्तीय अनियमितताओं की सीमा और कानून के किसी भी संभावित उल्लंघन का पता लगाना है। रान्या राव की जमानत याचिका अब तक दो बार खारिज हो चुकी है, एक बार निचली अदालत ने और दूसरी बार आर्थिक अपराधों के लिए विशेष अदालत ने। जमानत याचिका की ताजा सुनवाई में बहस पूरी हो चुकी है और अदालत ने 27 मार्च तक अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। 3 मार्च को 31 वर्षीय अभिनेत्री को बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया गया, जहाँ अधिकारियों ने अभिनेत्री से 12.56 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के बिस्कुट जब्त किए। उसके बाद उसके घर की तलाशी में कथित तौर पर 2.06 करोड़ रुपये मूल्य के सोने के आभूषण और 2.67 करोड़ रुपये की भारतीय मुद्रा जब्त की गई।

प्रयागराज में चले बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई लगाम, तोड़े गए घर फिर से बनेंगे!

प्रयागराज। बुलडोजन एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाम कसकर उन लोगों को राहत दी है जिनके घर तोड़ दिए गए थे। मामला प्रयागराज का है जहां जमीन के हिस्से को गैंगस्टर अतीक अहमद का मानकर राज्य सरकार की तरफ से घरों को ढहा दिया गया था। भारत के शीर्ष न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को न सिर्फ घर दोबारा बनाने की अनुमति देने का रास्ता दिखाया है, बल्कि राज्य सरकार को कड़े शब्दों में हिदायत दी है। दरअसल, याचिकाकर्ताओं की तरफ से अदालत को बताया गया था कि जमीन के हिस्से को गैंगस्टर अतीक अहमद का मानकर राज्य सरकार की तरफ से घरों को ढहा दिया गया था। इस मामले पर जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की बेंच सुनवाई की। बेंच का कहना है कि याचिकाकर्ताओं को ढहाए गए घरों को अपने खर्च पर दोबारा बनाने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इसमें कुछ शर्तें शामिल की गई हैं। जैसे तय समय में अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर करनी होगी। अदालत ने कहा कि अगर उनकी अपील खारिज हो जाती है तो याचिकाकर्ताओं को अपने खर्च पर घरों को ध्वस्त करना होगा। बेंच ने कहा, हम एक आदेश पास करेंगे कि वे अपने खर्च पर घर दोबारा बना सकते हैं और अगर अपील खारिज हो जाती है, तो उन्हें उसे अपने ही खर्च पर ढहाना भी होगा। इस मामले में याचिकाकर्ता एडवोकेट जुल्फिकार हैदर, प्रोफेसर अली अहमद, दो विधवाएं और एक अन्य शख्स था।

सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, तीन माओवादी ढेर

दंतेवाड़ा। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियान के तहत सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। दंतेवाड़ा और बीजापुर की सरहद पर सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें जवानों ने तीन नक्सलियों को मार गिराया। मौके से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया गया है। सूत्रों के अनुसार, 25 मार्च की सुबह करीब 8 बजे से ही यह मुठभेड़ जारी थी। सुरक्षाबल इलाके में नक्सल विरोधी अभियान चला रहे थे, तभी नक्सलियों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवानों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तीन नक्सलियों को ढेर कर दिया। सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके में सर्चिंग ऑपरेशन तेज कर दिया है ताकि अन्य नक्सलियों की मौजूदगी का पता लगाया जा सके। अधिकारियों का कहना है कि अभियान के तहत आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी ताकि क्षेत्र में शांति स्थापित की जा सके।

अमृतपाल सिंह आ सकता है पंजाब

अमृतसर। खालिस्तान समर्थक व सांसद अमृतपाल सिंह को अप्रैल में डिब्रूगढ़ से पंजाब लाया जा सकता है। 22 अप्रैल को अमृतपाल सिंह का एनएसए खत्म हो रहा है। डीएसपी गुरविंदर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए इसके संकेत दिए हैं। अमृतपाल के साथी पप्पलप्रीत सिंह की 10 अप्रैल के बाद वापसी संभव है। बीते चार दिनों में एक और साथी अमनप्रीत को कोटकपूरा से गिरफ्तार किया गया है। अमनप्रीत को भी आज पहले से हिरासत में लिए गए 7 साथियों के साथ अमृतसर की अजनाला कोर्ट में पेश किया गया। जहां पुलिस ने उनका तीन दिन का अतिरिक्त रिमांड हासिल किया है। आज की सुनवाई के दौरान पुलिस अधिकारियों ने अदालत में बताया कि इस केस में 19 नामजद और करीब 250 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था।

केंद्रीय गृहमंत्री शाह का दावा- कश्मीर में खत्म हुआ अलगाववाद

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को ट्वीट कर बड़ा दावा किया कि कश्मीर में अलगाववाद अब इतिहास की बात हो चुका है। पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की एकीकरण नीतियों ने जम्मू-कश्मीर से अलगाववाद को जड़ से खत्म कर दिया है।

केंद्रीय गृहमंत्री शाह ने अपने ट्वीट में लिखा, कि हुर्रियत के दो संगठनों, जम्मू-कश्मीर पीपुल्स मूवमेंट और डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट ने अलगाववाद से सभी संबंध तोड़ने की घोषणा की है। यह भारत की एकता को मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आगे कहा, कि मैं सभी ऐसे समूहों से आग्रह करता हूं कि वे आगे आएं और अलगाववाद को हमेशा के लिए समाप्त करें।

गौरतलब है कि गृहमंत्री शाह ने संसद में

भी इस मुद्दे को उठाया था और कहा था, कि कश्मीर में अलगाववादियों द्वारा किए जाने वाले पथराव और हड़ताल का दौर अब समाप्त हो चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को हटाए जाने के बाद से क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले हैं। सदन को शाह ने बताया कि 2019 में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद से जुड़ी घटनाओं में 70 फीसदी तक की गिरावट आई है। गृह मंत्रालय (एमएचए) के कामकाज पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि इस कदम ने राज्य में स्थिरता, आर्थिक प्रगति और सुरक्षा को बढ़ावा दिया है।

संविधान निर्माताओं का सपना हुआ साकार

शाह ने कहा कि अनुच्छेद 370 को समाप्त कर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने संविधान निर्माताओं के सपने को पूरा किया, जिन्होंने इसे अस्थायी प्रावधान कहा था। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि 34 वर्षों तक कश्मीर में सिनेमा हॉल बंद रहे और मुहर्रम के जुलूस निकालने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अब सिनेमा हॉल फिर से खुल गए हैं और लोग शांतिपूर्वक मुहर्रम के जुलूस निकाल रहे हैं।

कश्मीर को मिला वैश्विक मंच

गृहमंत्री शाह ने कश्मीर में सफलतापूर्वक आयोजित हुए जी-20 शिखर सम्मेलन का भी हवाला दिया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन ने कश्मीर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित कर दिया है और यह क्षेत्र अब दुनिया भर के पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है।

मुसलमानों को ईदी के रुप में सौगात-ए-मोदी किट गिफ्ट में देगी बीजेपी

-32 लाख गरीब मुसलमानों को गिफ्ट देने का अभियान शुरु

नई दिल्ली (एजेंसी)। सबका साथ, सबका विकास के नारे के साथ ईद से पहले भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) गरीब मुसलमानों को तोहफा बांटने का अभियान शुरू करने वाली है। बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा सौगात-ए-मोदी अभियान चलाकर 32 लाख गरीब मुसलमानों को गिफ्ट देगी। मंगलवार को अभियान दिल्ली के निजामुद्दीन से शुरू हुआ। अभियान की निगरानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कर रहे है। बीजेपी का कहना है कि गरीब मुसलमान भी शान से ईद मना सकें, इसके लिए उन्हें एक किट गिफ्ट में मिलेगी।

बीजेपी के 32 हजार कार्यकर्ताओं को यह काम सौंपा गया है। बीजेपी का हर कार्यकर्ता एक मस्जिद की जिम्मेदारी लेगा। इस तरह से देशभर में 32 हजार मस्जिदों को कवर करने का प्लान है। इसके बाद गरीब मुसलमानों को ईद से पहले ही गिफ्ट दिया जाएगा। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी ने कहा कि ईद, भारतीय नववर्ष, नौरूज, ईस्टर, गुड फाइडे को देखकर बीजेपी यह अभियान चला रही है।

उन्होंने कहा कि बहुत सारे अल्पसंख्यक हैं जो कि अपना त्यौहार भी ठीक से नहीं मना पाते हैं। इसके बाद उन्हें बीजेपी सौगात-ए-मोदी पेश करेगी। इसके अलावा जिला स्तर पर ईद मिलन कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा। अल्पसंख्यक मोर्चा में राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी यासिर जिलानी ने कहा कि यह अभियान मुस्लिम समुदाय के लिए योजनाओं को प्रमोट करने के लिए चलाया जा सके जिससे कि एनडीए को भी राजनीतिक समर्थन मिले।

पवित्र रमजान के महीने में ईद से पहले बीजेपी का यह अभियान बेहद अहम माना जा रहा है। अभियान से बीजेपी 32 लाख मुस्लिम परिवारों तक पहुंचना चाहती है। सौगात-ए-मोदी किट में कपड़े, सेंवइयां, खजूर, मेवे और चीनी होगी। इसके अलावा महिलाओं को दी जाने वाली किट में सूट का कपड़ा होगा और पुरुषों की किट में कुर्ता पायजामा का कपड़ा होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक किट की कीमत 500 से 600 रुपये होगी।

-सीएम रेखा गुप्ता ने बीजेपी सरकार का एक लाख करोड़ का पहला बजट किया पेश

यह बजट सरकारी लेखा-जोखा नहीं, बेहाल दिल्ली को विकसित करने का बजट

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 1,00,000 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। यह 27 सालों में दिल्ली में बीजेपी सरकार द्वारा प्रस्तुत किया पहला बजट है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपना बजट भाषण शुरू करते हुए कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है। यह साधारण बजट नहीं हैं। दिल्ली की नई सरकार जो ऐतिहासिक जनादेश के साथ सत्ता में आई है, वह अपना पहला बजट पेश कर रही है। पूरा देश आज दिल्ली का बजट देखना चाहता है। ये केवल सरकारी लेखा-जोखा नहीं है बल्कि 10 साल से बेहाल दिल्ली को विकसित बनाने का बजट है। बजट में बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और प्रदूषण नियंत्रण जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान दिया गया है। सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने बजट के लिए जनता से सुझाव मांगे थे, जिसमें ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए 10 हजार से ज्यादा सुझाव आए।

सीएम गुप्ता ने जेजे कॉलोनी झुग्गी बस्तियों का विकास के विकास के लिए 696 करोड़ रुरुपए आवंटित किए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं इसके आलावा सरकार 100 स्थानों पर अटल कैंटीन खोलेगी जिसके लिए बजट में 100 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा के लिए 50 हजार अतिरिक्त सीसीटीवी लगाए जाएंगे। दिल्ली के सड़क परिवहन और बुनियादी ढांचे के विकास और एनसीआर के साथ कनेक्टिविटी पर एक हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

पेश बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ ही 10 फोकस एरिया को चिह्नित किया गया है। इसमें बिजली, पानी, और सड़क का विकास का शामिल है। सीएम रेखा ने कहा कि 2025-26 के बजट में इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार ने एक हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया है। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली को नया रूप देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

सीएम ने कहा कि दिल्ली के बुनियादी ढांचे को हमारी सरकार मजबूत करके राष्ट्रीय राजधानी के तेज विकास की रफ्तार सुनिश्चित करेगी। उन्होंने कहा कि 28 हजार करोड़ के पूंजीगत व्यय से बीजेपी सरकार दिल्ली में सड़क, पुल, जल निकासी, ट्रांसपोर्ट और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में व्यापक सुधार कराएगी। यह बजट दिल्ली को एक स्मार्ट और आधुनिक शहर में बदलने की दिशा में मजबूत कदम है।

दिल्ली सरकार के बजट में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए 2,144 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इसके तहत दिल्ली में पात्र लोगों को 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा, इसमें 5 लाख रुपए केंद्र सरकार और 5 लाख रुपए दिल्ली सरकार देगी। सीएम रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में दिल्ली की महिलाओं के लिए महत्वकांक्षी योजना का ऐलान किया है। उन्होंने सदन को बताया कि महिला समृद्धि योजना के लिए बजट में 5100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। बता दें कि बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में दिल्ली के महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक मदद देने का वादा किया था।

सीएम रेखा ने कहा कि पिछली सरकार में सड़कों पर बहता सीवर का पानी दिल्ली की पहचान बन चुकी थी। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा कि यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट लेकर भी दिया जलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने बजट में आम आदमी पार्टी की सरकार के 15000 करोड़ रुपए की तुलना में 28000 करोड़ रुपए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए आवंटित किया है।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि पहली बार दिल्ली के इतिहास में ऐसा हुआ कि 2024

25 में बजट घटा। इस बार दिल्ली सरकार का बजट एक लाख करोड़ का है। पिछले साल की तुलना में 31.5 ज्यादा बजट है। दिल्ली में प्रति व्यक्ति आय पिछली सरकार में देश की तुलना में कम गति से बढ़ी। आप सरकार की इच्छा शक्ति काफी कम थी, वह ना खर्च कर पाई और ना लोगों की आय बढ़ा पाई। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में विकास के हर पैमाने पर दिल्ली फिसलती गई। यमुना की सफाई, स्वास्थ्य सुविधाओं और वायु प्रदूषण खत्म करने के लिए कोई काम नहीं हुआ। पिछली सरकार की नीतियों की वजह से जनता परेशान होती रही।

लोकसभा से फाइनेंस बिल पास, टीएमसी सांसद ने कृषि मंत्री को दलाल कहा

कांग्रेस ने रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया

नई दिल्ली (एजेंसी)। बजट सत्र के दौरान मंगलवार को लोकसभा से फाइनेंस बिल 35 संशोधनों के साथ पास हो गया। बिल पर 24 मार्च को बहस शुरू हुई थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने लोगों की आशाओं और 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के लक्ष्य के लिए काम करने की कोशिश की है। इससे पहले तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने संसद परिसर में प्रदर्शन किया। सांसद केंद्र पर पश्चिम बंगाल को मनरेगा के लिए मिलने वाला फंड रोकने का आरोप लगा रहे थे। इस दौरान ऋरूष्ट सांसद कल्याण बनर्जी ने कृषि मंत्री शिवराज चौहान को दलाल कहा।

बनर्जी ने कहा कि शिवराज बंगालियों के खिलाफ हैं। वे गरीबों के लिए कुछ नहीं कर रहे। शिवराज अमीरों के दलाल हैं। उन्होंने मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए काम नहीं किया इसलिए सीएम पद से हटा दिए गए। उधर कांग्रेस ने लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। पार्टी ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार पर गलत बयान देकर सदन को गुमराह करने का आरोप लगाया।

नए आयकर बिल पर मानसून सत्र में चर्चा होगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में बताया कि नए आयकर बिल पर मानसून सत्र में चर्चा होगी। बिल अभी सेलेक्ट कमेटी के पास है। कमेटी को अगले सत्र के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट देनी है। मौजूदा कानून में 819 धाराएं हैं जबकि नए कानून में सिर्फ 536 धाराएं होगीं। चैप्टर भी 47 से घटकर 23 रह जाएंगे। इसके अलावा 1200 प्रावधान और 900 स्पष्टीकरण हट जाएंगे। उधर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ न्यायपालिका से जुड़े मुद्दों पर मल्लिकार्जुन खडगे, जेपी नड्डा, जयराम रमेश समेत कई सांसदों के साथ बैठक की।

कर्नाटक में बिल्लियों में फैल रहा खतरनाक एफपीवी वायरस

99 प्रतिशत बिल्लियों की मौत

रायचूर। कर्नाटक के रायचूर जिले में एफपीवी नामक एक खतरनाक वायरस बिल्लियों में तेजी से फैल रहा है, जिससे सैकड़ों बिल्लियों की मौत हो चुकी है। इस वायरस से संक्रमित बिल्लियों के जीवित रहने की संभावना केवल 1 प्रतिशत है, और यह वायरस बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि, विशेषज्ञों का कहना है कि इस वायरस से इंसानों और कुत्तों को कोई खतरा नहीं है, लेकिन बिल्लियों के मालिकों को सावधानी बरतने की सलाह दी जा रही है। एफपीवी वायरस अब पूरे राज्य में फैल चुका है, और यह बहुत तेजी से बिल्लियों को संक्रमित करता है। रायचूर जिले में सौ से अधिक बिल्लियों में यह वायरस पाया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि एक समूह में 10 बिल्लियां हैं, और उनमें से एक संक्रमित है, तो यह वायरस कुछ ही सेकंड में बाकी सभी बिल्लियों में फैल सकता है। इस वायरस से बचने के लिए बिल्लियों के मालिकों को सावधानी बरतनी चाहिए।

बांग्लादेश को तीस्ता नदी का पानी छोड़ने पर कोई भी निर्णय लेने से पहले पश्चिम बंगाल से परामर्श करे केंद्र - तृणमूल

नई दिल्ली (एजेंसी)। तृणमूल कांग्रेस के सदस्य रीताब्रता बनर्जी ने राज्यसभा में केंद्र सरकार से आग्रह किया कि बांग्लादेश को तीस्ता नदी का पानी छोड़ने पर कोई भी निर्णय लेने से पहले वह पश्चिम बंगाल सरकार से परामर्श करे, क्योंकि इसका सीधा असर राज्य पर पड़ता है। उच्च सदन में शून्यकाल के दौरान यह मुद्दा उठाते हुए बनर्जी ने कहा कि तीस्ता राज्य की दूसरी सबसे बड़ी नदी है और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले कई जिलों से होकर गुजरती है। उन्होंने यह भी बताया कि सिक्किम में कई जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण, ऊपरी जलग्रहण क्षेत्रों में वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन के कारण पानी का प्रवाह प्रभावित हुआ है।

तृणमूल सांसद ने कहा, ''पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बात पर सख्त आपत्ति जताई थी कि पश्चिम बंगाल सरकार की भागीदारी के बिना बांग्लादेश के साथ तीस्ता जल बंटवारे और फरक्का संधि के बारे में कोई चर्चा नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के बीच जल बंटवारे पर समझौतों के कारण पश्चिम बंगाल के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कई वर्षों में भारत के पूर्वी हिस्से में नदियों के बहाव में बदलाव होने से पश्चिम बंगाल में पानी की उपलब्धता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार में भारत-बांग्लादेश फरक्का संधि को नवीनीकृत करने की प्रक्रिया चल रही है, जो 2026 में समाप्त होने वाली है।

बनर्जी ने कहा कि जहां तक लोगों की आजीविका का सवाल है, इससे उन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और फरक्का बैराज पर पानी का बहाव कोलकाता बंदरगाह के लिए नौवहन संबंधी समस्याएं पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को तीन बार पत्र लिखकर कहा है कि फरक्का बैराज के कारण पश्चिम बंगाल में बाढ़ के साथ ही बहुत बड़े पैमाने पर कटाव हुआ है। तृणमूल सदस्य ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में तीस्ता में पानी का प्रवाह कम हो गया है और अनुमान है कि अगर पानी बांग्लादेश के साथ साझा किया जाता है, तो पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में लाखों लोग

सिंचाई के पानी की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण गंभीर रूप से प्रभावित होंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य के उत्तरी हिस्से में रहने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी नदी के पानी की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत-भूटान नदी आयोग की भी जरूरत है, क्योंकि सीमा पार से आने वाली बाढ़ पश्चिम बंगाल के उत्तरी जिलों पर विनाशकारी प्रभाव डालती है।

टैरिफ वॉर से पहले भारत पहुंची ट्रंप की टीम, आज भारतीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक

नई दिल्ली (एजेंसी)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर टैरिफ को लेकर दी गई 2 अप्रैल की समय सीमा से पहले एक अमेरिकी टीम भारत आ गई है। यह टीम ट्रंप प्रशासन के साथ व्यापार समझौते के पहले चरण को अंतिम रूप देने के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ अहम बैठक करने वाली है। बैठक बुधवार, 26 मार्च से शुरू होने वाली है।

रिपोर्ट के अनुसार दोनों देशों के बीच सितंबर-अक्टूबर तक व्यापार समझौते के पहले हिस्से को पूरा करने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने हाल ही में भारत पर आयात शुल्क बढ़ाने की धमकी दी थी, इसके बाद यह कदम उठाया गया है। अमेरिकी टीम का लक्ष्य आपसी व्यापारिक मुद्दों को सुलझाना और टैरिफ विवाद को कम करना है। रिपोर्ट के मुताबिक, वार्ता में समझौते की रूपरेखा और समय-सीमा को तय किया जाएगा, जो दो चरणों में लागू होने की संभावना है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) के दक्षिण और मध्य एशिया मामलों के सहायक प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में एक टीम भारतीय वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल के साथ बैठक करेगी। इस वार्ता का उद्देश्य सितंबर-अक्टूबर तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना है।

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारतीय बाजार में लग्जरी कारों, इलेक्ट्रिक वाहनों, व्हिस्की और कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाने का दबाव बना रहे हैं। सप्ताह के अंत तक, जब तीन दिवसीय वार्ता समाप्त होगी, तब इस पर अधिक स्पष्टता आने की उम्मीद है। ट्रंप 2 अप्रैल से जवाबी टैरिफ लगाने की समयसीमा तय कर चुके हैं, इस वे अब मुक्ति दिवस कह रहे हैं। हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि अमेरिका वार्ता के दौरान टैरिफ बढ़ाएगा या नहीं।

अमेरिकी दूतावास के प्रवक्ता ने बताया कि भारत सरकार के साथ व्यापार और निवेश मामलों पर चल रही बातचीत को महत्व देते हैं और इन चर्चाओं को रचनात्मक, न्यायसंगत और दूरगामी दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाने की उम्मीद करते हैं। वहीं भारतीय अधिकारी समझौते से होने वाले लाभों पर चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन एक अधिकारी ने कहा कि यह व्यापार समझौता टैरिफ और नियमों में स्थिरता लाएगा और आर्थिक एकीकरण को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा, एक मजबूत व्यापार समझौता द्विपक्षीय व्यापार और निवेश के लिए नई संभावनाएं खोल सकता है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाशिंगटन यात्रा के दौरान भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय व्यापार वार्ता शुरू करने और 2030 तक व्यापार को 500 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य तय हुआ था।

बयान के मुताबिक दोनों देशों के नेताओं द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, भारत अमेरिका के साथ व्यापार और आर्थिक क्षेत्रों में सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। यह सहयोग दोनों देशों की समृद्धि और नवाचार को बढ़ावा देने और आपूर्ति श्रृंखला के एकीकरण को गहरा करने में सहायक होगा। हम अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल के साथ उपयोगी और रचनात्मक चर्चा की उम्मीद करते हैं, ताकि हमारे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक

संबंधों को पारस्परिक रूप से लाभकारी तरीके से बढ़ाया जा सके।

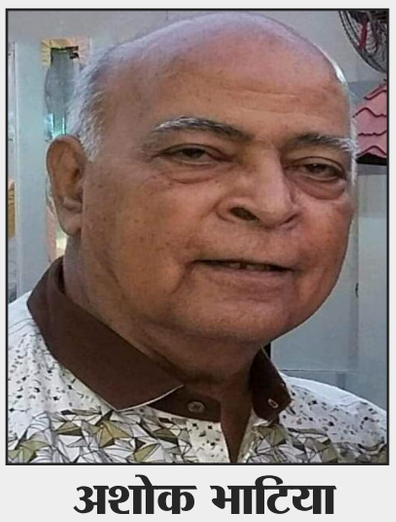

अशोक भाटिया

चुनावी माहौल के बीच रमजान का महीना चल रहा है, जिसके चलते रोजा इफ्तार दावत की बहार देखने को मिल रही। सियासी पार्टियां रोजा इफ्तार के बहाने मुस्लिम समुदाय वोट बैंक को साधने की है, जिसके लिए नमाज पढ़ने वाली टोपी लगाने से लेकर गमछे को पहनने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। इस तरह मुस्लिम रंग में रचे-बसे हुए नेता नजर आ रहे हैं, किसी की दावत में जाने से मुस्लिम तंजी में इनकार कर रही तो किसी की महफिल में जाने को बेकरार हैं। इस तरह बिहार में मुस्लिम पॉलिटिक्स होती दिख रही है ?

इफ्तार के बहाने पार्टियों ने किया अपनी ताकत का प्रदर्शन

बिहार में विधानसभा चुनाव की बिसात बिछाई जाने लगी है। चुनावी माहौल के बीच रमजान का महीना चल रहा है, जिसके चलते रोजा इफ्तार दावत की बहार देखने को मिल रही। सियासी पार्टियां रोजा इफ्तार के बहाने मुस्लिम समुदाय वोट बैंक को साधने की है, जिसके लिए नमाज पढ़ने वाली टोपी लगाने से लेकर गमछे को पहनने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। इस तरह मुस्लिम रंग में रचे-बसे हुए नेता नजर आ रहे हैं, किसी की दावत में जाने से मुस्लिम तंजी में इनकार कर रही तो किसी की महफिल में जाने को बेकरार हैं। इस तरह बिहार में मुस्लिम पॉलिटिक्स होती दिख रही है? आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की तरफ से इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। लालू प्रसाद के इफ्तार पार्टी में मुस्लिम संगठनों के लोग और वामपंथी दल और कांग्रेस के कुछ विधायक शामिल हुए। कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इफ्तार पार्टी से दूरी बनाई। यही नहीं वीआईपी के मुकेश भी नहीं पहुंचे। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता कह चुके है कि अबकी चुनाव में उन्हें बड़ा हिस्सा नहीं मिला तो वो अकेले चुनाव लड़ेगी । ज्ञात हो कि रमजान के महीने में हर साल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इफ्तार पार्टी का आयोजन करते हैं। लालू प्रसाद हर साल अपने सरकारी आवास 10 सर्कुलर रोड पर इफ्तार पार्टी का आयोजन करते थे। लेकिन आज लालू प्रसाद पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद के सदस्य अब्दुल बारी सिद्दीकी के सरकारी आवास 12 स्ट्रेंड रोड पर किया गया। इफ्तार पार्टी में लालू प्रसाद यादव खुद एक्टिव दिखे। इफ्तार पार्टी में लालू प्रसाद, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव, अब्दुल बारी सिद्दीकी, शिवानंद तिवारी सहित राजद के सभी विधायक महागठबंधन के सहयोगी वामपंथी दलों के नेता और कई विधायक इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुई। बिहार के वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडेय के अनुसार बिहार में महागठबंधन की सियासत लालू प्रसाद यादव के इर्द-गिर्द घूमती रहती थी। बिहार में कांग्रेस की राजनीति भी पिछले 25 वर्षों से राजद के सहारे ही चलती रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अब अपना संगठन विस्तार करने में लगी हुई है। यही कारण है कि नए प्रभारी एवं नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की गई है।लालू प्रसाद के द्वारा दी गई इफ्तार पार्टी में कांग्रेस के बड़े नेताओं की दूरी यह दिखा रही है कि महागठबंधन में सब कुछ सामान्य नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि कृष्णा अल्लावारु जब से बिहार के प्रभारी बने हैं एक

बार भी लालू प्रसाद से मुलाकात करने नहीं गए। लालू प्रसाद द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में महागठबंधन में नए राजनीतिक समीकरण भी देखने को मिला। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस, बिहार अध्यक्ष प्रिंस राज और पार्टी के वरिष्ठ नेता सूरजभान सिंह इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। मीडिया से बातचीत में पशुपति कुमार पारस ने बताया कि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है। इफ्तार पार्टी में शामिल हुए हैं। बिहार में नई राजनीतिक समीकरण के सवाल पर उन्होंने कहा कि "समय आने पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से मुख्यमंत्री आवास पर रविवार को इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। इफ्तार पार्टी में कई मुस्लिम नेताओं के साथ समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। हालांकि इससे पहले कई मुस्लिम संगठनों की ओर से इफ्तार पार्टी में जाने से इनकार किया गया था। जदयू के नेताओं ने कहा कि नीतीश कुमार मुस्लिम के साथ हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इफ्तार पार्टी में आधा दर्जन से ज्यादा मुस्लिम धार्मिक संगठनों के बॉयकॉट के बावजूद बड़ी संख्या में रोजेदार शामिल हुए। इफ्तार पार्टी में शामिल होने के लिए पूर्व मंत्री मोनाजिर हसन भी सीएम आवास पहुंचे। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार ने ही मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा काम किया। नीतीश कुमार ने जदयू के मुस्लिम नेताओं को पैचअप में लगाया है, लेकिन उसके बावजूद इफ्तार पार्टी पर असर इस बार दिखा है। हालांकि पार्टी में कैमरा और मोबाइल दोनों ले जाने की मनाही थी। इफ्तार पार्टी में जिन लोगों को मुख्यमंत्री आवास में एंट्री हुई उन्हें मोबाइल भी बाहर रखना पड़ा और कड़ी जांच के बाद जाने दिया गया है पास के माध्यम से ही एंट्री था। जदयू मुस्लिम नेताओं ने कहा यह राजद की साजिश है। चुनावी साल में लेकिन इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। नीतीश कुमार ने मुसलमान के लिए जितना काम किया है। मुस्लिम नीतीश कुमार के साथ हैं। मुख्यमंत्री आवास में हुए कर पार्टी में एनडीए के कई नेता भी शामिल हुए।ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इमारत-ए-शरिया, जमीयत उलेमा हिंद, जमीयत अहले हदीस, जमात-ए-इस्लामी हिंद, खानकाह मुजीबिया और खानकाह रहमानी ने वक्फ बिल को लेकर नीतीश कुमार और जदयू के फैसले पर नाराजगी जताते हुए इफ्तार पार्टी बायकाट किया था। बताया जाता है कि वक्फ बिल को लेकर जदयू ने लोकसभा में पुरजोर समर्थन किया था। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने समर्थन करते हुए इसे मुसलमान के हित में बताया था। उसके बाद से हैं मुस्लिम संगठन नीतीश कुमार से अपनी नाराजगी जताते रहे हैं नीतीश कुमार के साथ बैठक कर भी अपनी नाराजगी जताई है। बताया जाता है कि बिहार में सीमांचल सहित तीन दर्जन से अधिक सीट ऐसे हैं। जिसमें मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका निभाते हैं 243 सीटों में से तीन दर्जन सीटों में मुस्लिम वोटरों की आबादी 20 से 40% के करीब है 11 सीट तो ऐसे हैं जहां 40 फीसदी से भी अधिक वोट मुस्लिम के हैं।मुस्लिम वोटरों पर राजद और महागठबंधन की नजर तो है ही साथ ही एआईएमआईएम और प्रशांत किशोर की भी नजर है। सीमांचल में 2020 में एआईएमआईएम ने 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। मुस्लिम पहले से नीतीश कुमार से नाराज हैं और वक्फ बिल को लेकर उनकी नाराजगी और बढ़ी है। ऐसे में मुस्लिम संगठनों के बायकाट ने नीतीश कुमार की मुश्किलें और बढ़ा दी है। सुन्नी वक्फ बोर्ड बिहार के अध्यक्ष इशार्दुल्लाह के अनुसार ये सियासी स्टंट है। ये आरजेडी वालों का क्रिएट किया गया है। इफ्तार का कभी ठुकराया नहीं जाता है। ये पहली बार देख रहा हूं कि इफ्तार पार्टी का बॉयकॉट किया गया है। यह दुखद है।चुनाव में इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। 50 फीसदी नीतीश को वोट करने जा रहे हैं। यह सच भी है कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में मुसलमानों के हित में काफी काम हुए हैं। इसके बावजूद मुसलमानों के वोट जेडीयू को उस तरह नहीं मिलते, जितना उन्होंने उनके लिए काम किए हैं। इसका कारण शायद नीतीश कुमार का एनडीए में होना है। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तो जेडीयू के टिकट पर खड़े उम्मीदवारों में एक भी नहीं जीत पाया। जेडीयू ने 11 मुस्लिम उम्मीदवार उतारे थे। भला हो जमा खान का, जो जीते तो चिराग पासवान की पार्टी के टिकट पर, लेकिन सदन पहुंचते ही उन्होंने जेडीयू का दामन थाम लिया और नीतीश मंत्रिमंडल में उनके भरोसे के साथी बन गए। उधर जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर की भी मुस्लिम वोटों पर चौकस नजर है। उन्होंने 40 मुसलमानों को इस बार विधानसभा का टिकट देने की घोषणा की है। एआईएमआईएम वाले असदुद्दीन ओवैसी भी मुस्लिम वोटों के हिस्सेदार बनेंगे ही। मुस्लिम बहुल सीमांचल की पांच सीटें पिछली बार जीत कर और गोपालगंज विधानसभा के उपचुनाव में आरजेडी उम्मीदवार को हरा कर वे अपनी ताकत का एहसास करा चुके हैं। इसलिए महागठबंधन को अभी इतराने से परहेज करना ही श्रेयस्कर होगा।चाहे वह वर्मा हों या न्यायाधीश, साधारण अपराधी नहीं हैं, बल्कि न्यायिक प्रणाली में उच्च पदों पर काम करने वाले लोग हैं। उन्हें उचित रूप से दंडित किया जाना चाहिए। क्योंकि दिन के अंत में, सीजर को सबसे ऊपर होना चाहिए और उसका जीवन संदेह में होना चाहिए। यह न्याय प्रणाली में सीजर का काम है। ऊपर उल्लिखित न्यायाधीश को स्थानांतरित करना गलत है, भले ही उनकी बेगुनाही साबित नहीं हुई हो। इसलिए सभी भारतीयों का कहना है कि उनके बारे में सही फैसला उनकी पर्याप्त बेगुनाही साबित करने के बाद ही लिया जाना चाहिए। क्योंकि न्यायपालिका सर्वश्रेष्ठ है और इस अवसर पर न्यायपालिका की परीक्षा ली गई है।

अशोक भाटिया
(लेखक, स्वतंत्र पत्रकार)

संपादकीय

केंद्र का सही निर्णय

अमृता आर. पंडित

केंद्र सरकार ने एक महत्त्वपूर्ण फैसला के तहत एल्युमीनियम फॉयल सहित पांच चीनी वस्तुओं पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाया है। बताया जा रहा है कि यह निर्णय घरेलू उद्योगों को चीन से सस्ते आयात के निगेटिव असर से बचाने के लिए की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा डीजीटीआर (व्यापार उपचार महानिदेशालय) की सिफारिश के आधार पर व्यापार कार्रवाई की गई है। डीजीटीआर डंपिंग और सब्सिडी जैसे मामलों की जांच करती है। दरअसल, एंटी-डंपिंग ड्यूटी आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाले टैक्स हैं, जो उनके निर्यात मूल्य और उनके सामान्य मूल्य के बीच के अंतर की भरपाई के लिए लगाए जाते हैं, अगर डंपिंग के कारण आयात करने वाले देश में प्रतिस्पर्धी उत्पादों के उत्पादकों को नुकसान होता है। केंद्र सरकार के संज्ञान में यह बात लंबे अरसे से थी कि चीन भारत के घरेलू उद्योग को बर्बाद करने की साजिश में लगा हुआ है। आखिरकार सरकार को यह कदम उठाना पड़ा। स्वाभाविक तौर पर सरकार के इस फैसले से भारतीय उद्योगों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार को भी यह भरोसा है कि ऐसी सख्ती से भारतीय उद्योगों को मदद मिलेगी। इससे वे चीन से आने वाले सस्ते आयात से मुकाबला कर पाएंगे। भारत ने पहले ही चीन सहित विभिन्न देशों से सस्ते आयात से निपटने के लिए कई उत्पादों पर डंपिंग रोधी शुल्क लगाया है। इन सब तथ्यों से इतना तो साफ होता है कि चीन की नीयत में खोट है। वह भारत से मिलने वाली तमाम रियायतों और सुविधाओं को दरकिनार कर उसी का नुकसान पहुंचाने की जुगत में लगी रहती है। हो सकता है इस कदम के बाद चीन इस बात की संवेदनशीलता को समझेगा। ऐसे भी भारत के बाजार पर चीन के सामानों की बहुतायत है। कोई भी त्योहार मसलन दीपावली हो या होली; चीन किफायती कीमत के उत्पाद भारत में भेजता है। उसके इस कदम से भारत में काम कर रहीं कंपनियों की सेहत पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। निश्चित तौर पर केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार के फैसले की सराहना की जानी चाहिए। घरेलू उद्योगों को जीवनदान देने के लिए यह एहतियाती कदम उठाना लाजिमी था। इस बात में कोई शक नहीं कि चीन सिर्फ अपना फायदा देखता है। उसके शब्दकोष में न तो संवेदना की जगह है और न नैतिकता की। इस नाते मोदी सरकार की यह पहल ऐतिहासिक मानी जाएगी।

बिहार में कांग्रेस एकला चलो की राह चलेगी ?

हालिया हरियाणा व दिल्ली चुनाव कांग्रेस ने अकेला लड़ा पर हार के बाद भी उसका जोश कम नहीं हुआ है । अब जल्द ही बिहार के चुनाव होने है । यक्ष प्रश्न है कि हाल के चुनाओं में हार के बाद भी वह बिहार में अकेला लड़ना चाहेगी या इंडिया गठबंधन के साथ उसका जुडाव कायम रहेगा । यह प्रश्न इस कारण भी उठ रहा है कि कांग्रेस बिहार में अपना कुनबा बढ़ाने में लगी है । जैसा कि तकरीबन होता है कांग्रेस में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी से मुलाकात के दौरान उनकी कुछ बातों ने काफी आकर्षित किया। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा है कि हमने 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने खुद भी यह स्वीकार किया है कि यह लक्ष्य आसान नहीं है लेकिन साथ ही यह भी कहा है कि ये नामुमकिन भी नहीं। अखिलेश प्रसाद ने दावा किया कि बिहार कांग्रेस के पक्ष में इस बार चौंकाने वाले नतीजे आएंगे।मिशन 50 के नारे, चौंकाने वाले नतीजों के दावे... इनके लिए कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले अधिक सीटों पर चुनाव लड़ना होगा। 2020 के चुनाव नतीजों में 70 सीटों पर चुनाव लड़कर महज 27 फीसदी स्ट्राइक रेट के साथ 19 सीटें ही जीत पाई पार्टी को राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) इस बार अधिक सीटें देने का खतरा मोल लेगी? खासकर तब, जब महागठबंधन 110 सीटें जीतकर बहुमत के लिए जरूरी 122 के जादुई आंकड़े से महज 12 सीट पीछे रह गया था और विपक्षी गठबंधन की मात के लिए कांग्रेस के प्रदर्शन को कसूरवार ठहराया गया था। मिशन 50 का नारा देने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता भी यह समझ रहे हैं कि सीट शेयरिंग की टेबल पर अपनी डिमांड मनवाने की राह में पिछले चुनाव का प्रदर्शन उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा रहने वाला है। यही वजह है कि पार्टी ने इस बार खास रणनीति बनाई है- प्लान 45. दरअसल, कांग्रेस ने 2015 के विधानसभा चुनाव में 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 27 सीटें जीतने में सफल रही थी जो 1995 में 29 सीटों पर जीत के बाद बिहार चुनाव में पार्टी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। कांग्रेस को इतनी सीटें लड़ने के लिए तब मिली थीं जब महागठबंधन में जेडीयू भी थी। 2020 के चुनाव से पहले कांग्रेस नेतृत्व अधिक सीटों की डिमांड पर अड़ गया। हां-ना, हां-ना का दौर अंतिम वक्त तक चलता रहा और बात बनी तेजस्वी यादव की राहुल गांधी के साथ हुई बात के बाद। लालू यादव की पार्टी ने आखिरकार कांग्रेस को 70 सीटें देने पर हामी भर दी जो 2015 चुनाव के मुकाबले 29 ज्यादा थीं। सीटों की संख्या में कांग्रेस की चल गई लेकिन जब माइक्रो लेवल पर सीटों का आवंटन शुरू हुआ, ग्रैंड ओल्ड पार्टी के साथ यहीं पर खेल हो गया। कांग्रेस को जो सीटें दी गईं, उनमें से 45 ऐसी थीं जहां पार्टी पिछले चार चुनाव से जीत नहीं पाई थी। 70 में से 67 सीटों पर 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने लीड किया था।आरजेडी ने कांग्रेस की 70 सीटों की डिमांड मान तो ली थी लेकिन ऐसी सीटें दे दी थीं जहां एनडीए का प्रभाव अधिक था। इससे सीट शेयरिंग में कांग्रेस भले ही आरजेडी के बाद दूसरे सबसे बड़े घटक का टैग हासिल करने में सफल रही हो, नतीजे आए तो पार्टी विलेन बन गई। इसके उलट, लेफ्ट पार्टियों ने 29 सीटों पर चुनाव लड़ा और 16 सीटें जीतने में सफल रही थीं। सीट शेयरिंग में लेफ्ट के हिस्से आई कई सीटें ऐसी थीं जहां परंपरागत रूप से कांग्रेस मजबूत रही है। कांग्रेस के नेता भी जानते हैं कि इस बार आरजेडी 2020 चुनाव के स्ट्राइक रेट को आधार बनाकर पार्टी को कम से कम सीटें देना चाहेगी। लालू यादव की पार्टी के ऐसे किसी भी दांव से निपटने के लिए कांग्रेस पहले से ही होमवर्क में जुट गई है। इसके लिए पार्टी ने प्लान-45 बनाया है। कांग्रेस का फोकस इस बार सीटों के नंबर पर अधिक जोर लगाने से ज्यादा ऐसी सीटें पाने पर है जहां पार्टी की जमीन अपेक्षाकृत मजबूत है और जीत की संभावनाएं बन सकती हैं।कांग्रेस का नेतृत्व बिहार चुनाव के लिए मैदान में उतर आया है। बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह नेताओं के साथ चंपारण की जमीन पर उतर गए हैं। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा वैशाली में हैं। बिहार कांग्रेस के प्रभारी शाहनवाज आलम सीमांचल के पूर्णिया, अररिया और बेगूसराय में हैं। चुनाव में अभी काफी समय बचा है लेकिन पार्टी ने वार रूम के पुनर्गठन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इन सारी कवायदों को कांग्रेस चुनावी तैयारी से जोड़ रही है। ऐसा ही है भी लेकिन सुस्त इमेज वाली पार्टी का इतना पहले एक्टिव मोड में आ जाना सीट शेयरिंग की टेबल पर जाने से पहले होमवर्क से जुड़ा भी बताया जा रहा है। कांग्रेस नेतृत्व की कोशिश है कि जमीनी आधार पर जीतने योग्य सीटें चिह्नित की जाएं और फिर उन्हें हासिल करने के लिए जोर लगाया जाए। बाकी, लालू यादव की अगुवाई वाली आरजेडी इस बार कांग्रेस को कितनी और कौन सी सीटें देती है, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस अब गठबंधन में मजबूरी का हिस्सा बनने की बजाय मजबूत साझेदार की भूमिका निभाना चाहती है। पार्टी का मुख्य उद्देश्य अपनी पसंद की सीटें हासिल करना है, जिनकी उसे पिछली बार कमी रही थी। सूत्रों के अनुसार, यदि इस बार कांग्रेस को अपनी पसंद की सीटें मिलती हैं, तो वह कुछ सीटों पर समझौता करने के लिए तैयार हो सकती है। कांग्रेस अब आरजेडी पर दबाव बनाने के लिए अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है ताकि सीट बंटवारे में उसे पूरी तरह से सम्मान मिल सके।

रंजन श्रीवास्तव
(लेखक, स्वतंत्र पत्रकार)

चिंतन-मनन

प्रकाशस्रोत परमात्मा

परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चन्द्र तथा नक्षत्रों जैसी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाशस्रोत हैं। वैदिक साहित्य बताता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चन्द्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां परमेश्वर का तेज विद्यमान है।भौतिक जगत में ब्रम्हज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतः हमें सूर्य, चन्द्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। वैदिक साहित्य में स्पष्ट है कि भगवान आध्यात्मिक जगत (वैकुंठ लोक) में स्थित हैं।श्वेतातर उपनिषद में कहा गया है- आदित्यवर्ण तमसः परस्तात अर्थात वे सूर्य की भांति अत्यन्त तेजोमय हैं, लेकिन भौतिक जगत के अन्धकार से बहुत दूर हैं। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रम्ह घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ जाने का इच्छुक है, उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है। एक वैदिक मंत्र है तं ह देवम आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुवै शरणामहं प्रपद्ये। अर्थात मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहां तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का सम्बन्ध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है-तमेव विदित्वाति मृत्युमेति यानी उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। वे प्रत्येक हृदय में परम नियन्ता के रूप में स्थित हैं। परमेश्वर के हाथ-पैर सर्वत्र फैले हैं लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतः मानना ही पड़ेगा कि कार्यक्षेत्र जानने वाले दो ज्ञाता हैं- एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ-पैर किसी एक स्थान तक सीमित हैं जबकि कृष्ण के हाथ-पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेतातर उपनिषद में इस प्रकार हुई है। सर्वस्थ प्रभुमीशानं सर्वस्य शरणं बृहत यानी वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है। वह उन सबका चरम आश्रय है। अतः इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा भिन्न हैं।

एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट

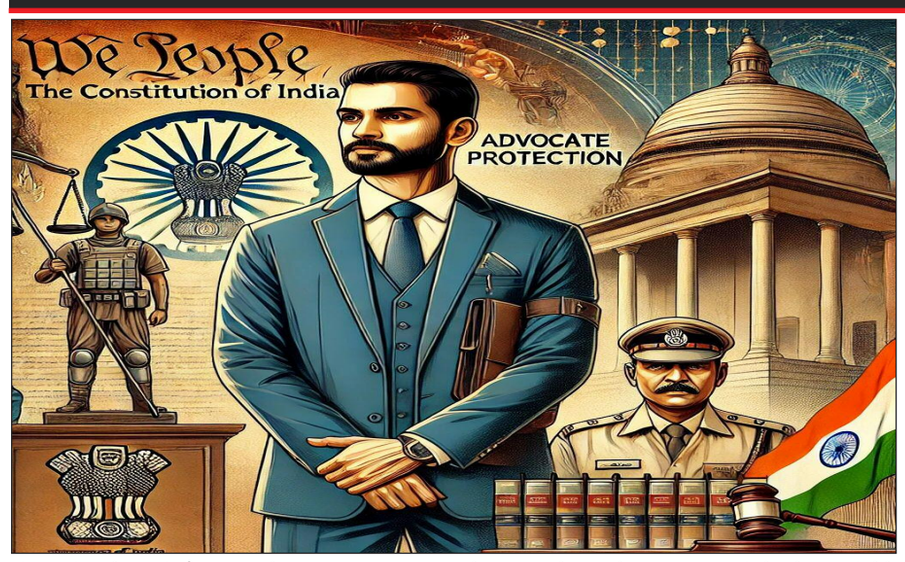

राजेश श्रीवास्तव

अधिवक्ता किसी भी लोकतांत्रिक न्याय प्रणाली की रीढ़ होते हैं। वे न केवल अपने मुवक्किलों को न्याय दिलाने में सहायता करते हैं, बल्कि संपूर्ण विधि व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने में भी योगदान देते हैं। हालांकि, हाल के वर्षों में अधिवक्ताओं पर बढ़ते हमलों, धमकियों और उत्पीड़न की घटनाओं ने उनकी सुरक्षा, स्वतंत्रता और गरिमा को गंभीर खतरे में डाल दिया है। ऐसे में, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता स्पष्ट रूप से महसूस की जा रही है। यह अधिनियम न केवल अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनके आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को भी सुदृढ़ बनाएगा। भारत में अधिवक्ताओं की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है। हाल ही के वर्षों में उनके खिलाफ हिंसा के मामले तेजी से बढ़े हैं। 2024 में ही देशभर में 200 से अधिक वकीलों पर हमलों की घटनाएँ दर्ज हुईं। इनमें कुछ वकीलों को जान से मारने की धमकी दी गई, कुछ पर शारीरिक हमले हुए, और कुछ मामलों में अधिवक्ताओं की हत्या भी कर दी गई। यह प्रवृत्ति न्याय प्रणाली की स्वतंत्रता और निष्पक्षता के लिए एक गंभीर खतरा उत्पन्न करती है। यदि अधिवक्ताओं को डराया-धमकाया जाएगा या उन पर हिंसक हमले होंगे, तो वे अपने कार्य को निष्पक्षता से नहीं कर पाएँगे। विकसित देशों में अधिवक्ताओं की सुरक्षा और कल्याण के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। अमेरिका में वकीलों को बार एसोसिएशन द्वारा स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और सुरक्षा प्रदान की जाती है। यूनाइटेड किंगडम में सभी अधिवक्ताओं को सरकारी पेंशन और बीमा अनिवार्य रूप से दिया जाता है। फ्रांस और जर्मनी में अधिवक्ताओं को विशेष पुलिस सुरक्षा दी जाती है, और उन्हें बीमा योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है। कनाडा में अधिवक्ताओं के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ, बीमा, और सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराए जाते हैं। भारत में इस तरह की कोई व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रणाली मौजूद नहीं है, जिससे यहाँ के अधिवक्ताओं की स्थिति और भी दयनीय हो जाती है। भारत में लगभग 27 लाख अधिवक्ता कार्यरत हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति अत्यधिक असमान है। अधिकांश युवा वकील अपने करियर के शुरूआती वर्षों में आर्थिक संकट का सामना करते हैं। एक अध्ययन के अनुसार, 80% युवा वकील अपने करियर के पहले पाँच वर्षों में 10,000 रुपये प्रति माह से भी कम कमाते हैं। वहीं, केवल 5% शीर्ष वकील ही करोड़ों रुपये की कमाई करते हैं। जिला स्तर और छोटे शहरों में कार्यरत वकील अत्यधिक आर्थिक कठिनाइयों से जूझते हैं। कई वकील इस पेशे में टिक नहीं पाते और वैकल्पिक करियर की ओर रुख कर लेते हैं। भारत में अधिवक्ताओं के लिए कोई अनिवार्य बीमा योजना या पेंशन योजना मौजूद नहीं है। यदि किसी वकील की असामयिक मृत्यु हो जाए या वह किसी दुर्घटना का शिकार हो जाए, तो उसके परिवार को कोई वित्तीय सुरक्षा नहीं मिलती। इसके विपरीत, अमेरिका और यूरोपीय देशों में वकीलों को अनिवार्य बीमा योजनाएँ और पेंशन लाभ प्रदान किए जाते हैं, जिससे वे आर्थिक रूप से सुरक्षित रहते हैं। भारत में भी इस तरह की योजनाओं को लागू करने की सख्त जरूरत है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए जाने चाहिए। सबसे पहले, अधिवक्ताओं पर किसी भी प्रकार के हमले को गैर-जमानती अपराध घोषित किया जाना चाहिए। कोर्ट परिसरों में पुलिस सुरक्षा और सीसीटीवी निगरानी अनिवार्य की जानी चाहिए, ताकि वकीलों पर होने वाली हिंसा को रोका जा सके। इसके अलावा, वकीलों को धमकी देने या डराने-धमकाने के मामलों में कठोर सजा के प्रावधान किए जाने चाहिए। संवेदनशील मामलों की पैरवी करने वाले अधिवक्ताओं को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहिए। कई बार अपराधी, राजनीतिक दबाव समूह, या बाहुबली तत्व वकीलों को धमकाने की कोशिश करते हैं, जिससे वे मुकदमे से हट जाएँ या मनचाहा निर्णय दिलाने में सहयोग करें। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के तहत ऐसे मामलों में अधिवक्ताओं को पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। अधिवक्ताओं की वित्तीय सुरक्षा के लिए भी ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। प्रत्येक अधिवक्ता के लिए कम से कम 50 लाख रुपये तक का बीमा कवर अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा, वरिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए पेंशन योजना लागू की जानी चाहिए, जिससे वे वृद्धावस्था में आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकें। युवा अधिवक्ताओं के लिए स्टाइपेंड योजना लागू की जानी चाहिए, जिससे उन्हें अपने करियर के शुरूआती वर्षों में वित्तीय सहायता मिल सके। महिला अधिवक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी इस कानून का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकने के लिए विशेष प्रकोष्ठ गठित किए जाने चाहिए और महिला वकीलों के लिए सुरक्षित कार्यस्थल सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्हें मातृत्व लाभ और चाइल्ड केयर सुविधाएँ भी प्रदान की जानी चाहिए, ताकि वे बिना किसी दबाव के अपने पेशेवर कर्तव्यों का पालन कर सकें। वकीलों के लिए डिजिटलीकरण और आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी आवश्यक है। कोर्ट प्रक्रियाओं को ऑनलाइन किया जाना चाहिए, जिससे वकीलों को अनावश्यक लंबित मामलों और न्यायिक देरी से राहत मिले। वकीलों के लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी सपोर्ट की व्यवस्था की जानी चाहिए, ताकि वे आधुनिक कानूनी चुनौतियों का सामना प्रभावी ढंग से कर सकें। भारत सरकार को वकीलों के कल्याण और सुरक्षा के लिए एक विशेष आपातकालीन सहायता कोष स्थापित करना चाहिए। इस कोष के माध्यम से किसी भी वकील को आपातकालीन परिस्थितियों में आर्थिक सहायता दी जा सकती है। यह कोष विशेष रूप से उन वकीलों के लिए फायदेमंद होगा जो गंभीर दुर्घटना, बीमारी या किसी अन्य संकट से जूझ रहे हैं। छोटे शहरों और जिला न्यायालयों में कार्यरत वकीलों के लिए सस्ते लॉ चैंबर और आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कई बार वकीलों को किराये के दफ्तर तक के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यदि सरकार विशेष सहायता प्रदान करे, तो इससे वकीलों को पेशेवर रूप से कार्य करने में मदद मिलेगी। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने में कुछ चुनौतियाँ भी आ सकती हैं। सबसे बड़ी चुनौती होगी राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना और इस कानून को समान रूप से लागू करना। इसके अलावा, सरकार को इस कानून के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने पर भी ध्यान देना होगा। सरकार को इस कानून को जल्द लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। इसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, राज्य बार काउंसिल और न्यायपालिका को मिलकर काम करना होगा। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू होने से अधिवक्ताओं को सुरक्षा मिलेगी, जिससे वे स्वतंत्र रूप से अपने कर्तव्यों का पालन कर पाएँगे। यदि अधिवक्ता सुरक्षित रहेंगे और उन्हें आर्थिक व सामाजिक स्थिरता प्राप्त होगी, तो न्यायिक प्रणाली अधिक प्रभावी और निष्पक्ष बनी रहेगी। इससे आम नागरिकों को भी लाभ मिलेगा, क्योंकि वे बिना किसी भय के न्याय पाने के लिए आगे आ सकेंगे। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट केवल वकीलों की सुरक्षा का विषय नहीं है, बल्कि यह न्यायिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र की मजबूती से भी जुड़ा हुआ है। जब अधिवक्ता निर्भीक होकर कार्य करेंगे, तभी न्यायपालिका निष्पक्ष और प्रभावी बनी रहेगी। सरकार को इस कानून को प्राथमिकता देते हुए जल्द लागू करना चाहिए, ताकि भारत की न्यायिक प्रणाली अधिक संगठित और न्यायसंगत बन सके।

पुलिस ने शातिर वाहन चोरों को दबोचा

नई दिल्ली (एजेंसी)। पूर्वी दिल्ली के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वायड (एएटीएस) ने दो वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपित संभल उप्र से दिल्ली आकर लग्जरी वाहन चोरी करते थे। पकड़े गए आरोपितों की पहचान दीपा सराय, मोहल्ला गैरतपुर, संभल, उप्र निवासी फरजान (32) और दीपा सराय, इमामबाड़ा के पास, संभल, उप्र निवासी अहतेशाम (29) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपितों के पास से चोरी की दो लग्जरी गाड़ियां फॉरच्यूनर और महिंद्रा थार बरामद की हैं। इनकी 70 लाख रुपये कीमत बताई जा रही है। आरोपित नकली चाबी की मदद से चंद की मिनटों में गाड़ियां चोरी कर लेते थे। पुलिस को इनके बाकी साथियों की तलाश है। आरोपितों से पूछताछ कर पुलिस इनके बाकी साथियों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पूर्वी जिले के डीसीपी अभिषेक धानिया ने मंगलवार को बताया कि जिले की एएटीएस लगातार वाहन चोरों पर नजर रखता है। इस बीच टीम को सूचना मिली कि वाहन चोरी में शामिल दो बदमाश पेपर मार्केट गाजीपुर में चोरी की गाड़ी में सवार होकर आने वाले हैं। सूचना को पुख्ता कर टीम ने मौके पर जाल बिछा दिया। इस बीच काले रंगे की थार गाड़ी में दो बदमाश वहां पहुंचे। उनको जांच के लिए रोका गया। जांच के दौरान गाड़ी 19 मार्च को न्यू फ्रेंड्स कालोनी एरिया से चोरी पाई गई। उसके बाद दोनों गिरफ्तार किया गया।

दिल्ली पुलिस में कई अधिकारियों का हुआ ट्रांसफर

नई दिल्ली (एजेंसी)। गृह मंत्रालय ने दिल्ली में कानून व्यवस्थाष को दुरुस्त करने की दिशा में महत्व2पूर्ण कदम उठाया है। मंगलवार को दिल्ली सरकार के बजट वाले दिन ही ताबड़तोड़ 28 पुलिस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। तबादले में आईपीएस व दानिक्स अधिकारी भी हैं। कुछ अधिकारियों की पदोन्नति भी हुई है। गृह मंत्रालय के उप सचिव कुलविंदर सिंह ने स्थानांतरण सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होगा। जिन अधिकारियों का तबादला हुआ है उसमें 2001 बैच के आईपीएस बी शंकर जायसवाल, आईपीएस परमादित्य, विक्रमजीत सिंह, पुष्पेंद्र कुमार, नुपूर प्रसाद के साथ ही 2008 बैच के आईएएस शरत कुमार सिन्हा भी हैं। जानकारी के अनुसार आईपीएस बी शंकर जायसवाल को सेंट्रल रेंज का जॉइंट सीपी बनाया गया है। आईपीएस परमादित्य सेंट्रल रेंज से स्पेशल ब्रांच में जॉइंट सीपी होंगे। सिक्योरिटी जॉइंट सीपी का पदभार संभाल रहे 2006 बैच के आईपीएस पुष्पेंद्र कुमार अब ईस्टर्न रेंज के जॉइंट सीपी होंगे। नुपूर प्रसाद को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से लाइसेंसिंग का जॉइंट सीपी बनाया गया है। इसी क्रम में आईपीएस विक्रमजीत सिंह को सिक्योरिटी में भेजा गया है। एडिशनल ज्वाइंट सीपी क्राइम 2010 बैच के आईपीएस संजय भाटिया अब एडिशनल सीपी हेडक्वार्टर होंगे। 2014 बैच की आईपीएस अकांक्षा यादव को डीसीपी सिक्योरिटी बनाया गया है।

ड्रग्स तस्करी के मामले में वांछित बदमाश गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने ड्रग्स तस्करी के मामले में वांछित शिव शंकर उर्फ गेला को गिरफ्तार किया है। क्राइम ब्रांच की डीसीपी अपूर्वा गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि पकड़ा गया शिव शंकर काफी कुख्यात है। इसने हाल ही में एक नाबालिग को भी चाकू मारा था। जांच में पता चला है कि आरोपित दुष्कर्म, हत्या के प्रयास, ड्रग्स तस्करी समेत छह से ज्यादा मामलों में शामिल रहा है। डीसीपी के अनुसार क्राइम ब्रांच की टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि ड्रग्स तस्करी के मामले में वांछित बदमाश बुराड़ी इलाके में आने वाला है। सूचना को पुख्ता कर पुलिस टीम ने बुराड़ी के कमल विहार इलाके में जाल बिछाकर आरोपित को धर दबोचा।

दो कुख्यात झपटमार गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ टीम ने दो कुख्यात झपटमारों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के छह महंगे मोबाइल फोन और वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल बरामद हुई है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान बवाना निवासी लाल बाबू के रूप में हुई है, जो झपटमारी, वाहन चोरी, डकैती, आर्म्स एक्ट और एक्साइज एक्ट के 37 से ज्यादा मामलों में शामिल रहा है और बवाना थाने का बीसी है। इसके अलावा दूसरे आरोपी की पहचान वजीराबाद निवासी अजहरुद्दीन उर्फ लेफ्टी के रूप में हुई है, जो पहले कश्मीरी गेट थाने में चोरी के एक मामले में शामिल रहा है। दोनों की गिरफ्तारी से पुलिस ने झपटमारी और चोरी के 19 मामले सुलझाने का दावा किया है। डिप्टी कमिश्नर एम हर्षवर्धन के अनुसार, 16 मार्च को अजमल खां रोड से मोबाइल फोन छीनने के संबंध में डीबीजी रोड थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी। इंस्पेक्टर रोहित कुमार के नेतृत्व में टीम ने कई सीसीटीवी कैमरों को बारीकी से खंगाला और करीब 40 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए कई इलाकों में संदिग्धों की गतिविधियों का पता लगाया। 21 मार्च को टीम ने गाजियाबाद लोनी के कासिम विहार से लाल बाबू को गिरफ्तार किया और बाद में उसके साथी अजहरुद्दीन को वजीराबाद से पकड़ा। उनके कब्जे से छह महंगे छीने गए मोबाइल फोन, अपराध में इस्तेमाल की गई एक सफेद केटीएम ड्यूक मोटरसाइकिल बरामद की गई। उनकी सूचना पर अलाउद्दीन को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

गृह मंत्रालय का अफसर बताकर ठगी करने वाला गिरफ्तार

नई दिल्ली (एजेंसी)। खुद को गृह मंत्रालय का अफसर बताकर ठगी करने वाले एक शख्स को द्वारका जिला साइबर थाना पुलिस ने 23 मार्च को गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है। आरोपी राजेश कुमार लोगों से उनका खोया हुआ मोबाइल दिलाने या फिर सरकार और पुलिस से जुड़े काम कराने के बहाने ठगी करता था। पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि साइबर थाना पुलिस को एक शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उसका मोबाइल खो गया था। इसकी गुमशुदगी उसने जनकपुरी थाने में दर्ज कराई थी। उसने फेसबुक पर एक पोस्ट कर मोबाइल वापस पाने के संबंध में पूछताछ की थी। जिसके बाद उसके पास एक अंजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने खुद का नाम अनुराग मिश्रा बताया।

सीएम रेखा गुप्ता ने केजरीवाल द्वारा बनाए गए 'शीशमहल' पर टिप्पणी की -सीएम ने कहा कि आपने शीशमहल बनाया, हम गरीबों के लिए घर बनाएंगे

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर कटाक्ष किया। उन्होंने केजरीवाल द्वारा बनाए गए %शीशमहल% पर टिप्पणी की। सीएम ने कहा कि यह बजट सिर्फ सड़क, पुल और लिफ्ट कॉरिडोर बनाने के लिए नहीं है बल्कि यह पूरी दिल्ली की हालत सुधारने का बजट है। सीएम ने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने शीशमहल बनाया, हम गरीबों के लिए घर बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार और हमारे बजट में बहुत अंतर है, पिछली सरकार सिर्फ घोषणाएं करती थी और हम वादे पूरे करते हैं। हाथ की सफाई तो आप जानते ही हैं, हम कूड़ा साफ करवाएंगे। उन्होंने कहा कि आपने अपने लिए लाखों रुपये का शौचालय बनवाया, हम झुग्गी वालों के लिए शौचालय बनवाएंगे। उन्होंने विपक्षी सदस्यों की ओर इशारा करते हुए कहा कि आपने सिर्फ बातें कीं और हम दिल्ली बनाएंगे।

सीएम ने आगे कहा कि दिल्ली में उद्योगपति और व्यापारी परेशान थे, कोई भी अधिकारी जाकर उन्हें धमका देता था और वे परेशान हो जाते थे, दिल्ली का उद्योग पटरी से उतर चुका था, दिल्ली में व्यापार और निवेश ठप हो गया था, लेकिन अब प्रधानमंत्री की सोच के तहत दिल्ली में व्यापार और निवेश के दरवाजे खुलेंगे। उल्लेखनीय है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया। इस बजट में सीएम ने दिल्ली के लोगों को कई तोहफे दिए। दिल्ली के किसानों को अब 6000 रुपये की जगह 9000 रुपये मिलेंगे। इसके लिए दिल्ली के बजट में पीएम किसान सम्मान निधि के लिए 5 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को 2000 रुपये की तीन किस्तों में सालाना 6000 रुपये दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष के लिए दिल्ली सरकार का बजट 1 लाख करोड़ रुपये होगा, जो आम आदमी पार्टी सरकार के पिछले बजट से 31.5 प्रतिशत अधिक है।

विकसित दिल्ली की दिशा में यह बजट एक मील का पत्थर : खंडेलवाल

नई दिल्ली (एजेंसी)। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) के राष्ट्रीणय महामंत्री और चांदनी चौक क्षेत्र से सांसद प्रवीन खंडेलवाल ने दिल्ली सरकार के वित्त वर्ष 2025-26 के बजट को संतुलित, जनहितकारी और विकासोन्मुखी बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट सर्वस्पर्शी है, जिसमें दिल्ली के सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। विकसित दिल्ली की दिशा में यह बजट एक मील का पत्थर है।

कैट के महामंत्री खंडेलवाल मंगलवार को दिल्लीक सरकार के वित्ता वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये के प्रस्तुमत बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे। उन्होंने एक बयान में कहा कि यह बजट दिल्ली की आर्थिक प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक सिद्ध होगा। उन्होंबने कहा कि दिल्ली की रेखा गुप्तो की सरकार ने व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे और सामाजिक कल्याण को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित बजट प्रस्तुत किया है। सांसद खंडेलवाल ने कहा कि बजट में व्यापार और उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए नए प्रावधान किए गए हैं, जिससे दिल्ली के व्यापारियों और उद्यमियों को लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने व्यापार एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीतियां बनाने और ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के गठन की घोषणा की है। इससे दिल्ली में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा तथा व्यापार करना आसान होगा। उन्होंने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़ा आवंटन, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार के लिए ठोस कदम तथा परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नई परियोजनाएं दिल्ली में विकास को गति देगी। सांसद खंडेलवाल ने यमुना की सफाई के लिए धन आवंटन करने को यमुना को साफ करने के संकल्प को पूरा करने की दिशा में सही कदम बताया।

उल्लेशखनीय है कि दिल्लीर की मुख्यसमंत्री एवं वित्त मंत्री रेखा गुप्ता ने आज वित्त वर्ष 2025-26 के लिए एक लाख करोड़ रुपये का बजट विधानसभा में पेश किया, जो पिछले वित्त वर्ष 2024-25 के बजट की तुलना में 31.5 फीसदी अधिक है।

'विपदा' सरकार ने दिल्ली को दिया हवा-हवाई बजट', आतिशी का बीजेपी पर तंज, काम कम, जुमले ज़्यादा

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार के बजट को लेकर आम आदमी पार्टी भाजपा पर हमलावर हो गई है। पूर्व सीएम और विपक्ष की नेता आतिशी ने एक्स पोस्ट में लिखा कि भाजपा की विपदा सरकार ने दिल्ली को हवा-हवाई बजट दिया। उन्होंने लिखा कि 1 लाख करोड़ के बजट का कोई आर्थिक आधार नहीं है, वरना Economic Survey छुपाने की जरूरत क्यों पड़ती? मैं रेखा गुप्ता जी को चैलेंज देती हूं– Economic Survey के आंकड़े सार्वजनिक करें। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।

आप नेता ने आगे कहा कि इस बजट ने बीजेपी की नीयत भी सामने ला दी है। 1. सरकारी स्कूलों को ठप करना - 10 साल में पहली बार हुआ है, जब शिक्षा का बजट 20त से भी कम कर दिया, ताकि सरकारी स्कूल बर्बाद हो जाए। 2. मुफ्त इलाज बंद करना - 10 साल में पहली बार स्वास्थ्य का बजट घटकर 13त तक कर दिया गया, ताकि गरीबों का फ्री इलाज बंद हो जाए। 3. सफ़ाई व्यवस्था को ठप करना- पहली बार हुआ है जब MCD का बजट घटा है। MCD का बजट जो साल 2024-25 में ?8423 करोड़ था। उसे रू.1526 करोड़ घटाकर इस बार रू.6897 करोड़ कर दिया है।

उन्होंने कहा आज रेखा गुप्ता जी ने अपने 2 घंटे के भाषण में 1.5 घंटे सिर्फ AAP और अरविंद केजरीवाल जी को गालियाँ देने में बिता दिए। शायद उन्हें अब तक एहसास ही नहीं हुआ है कि चुनाव खत्म हो चुके हैं, उनकी सरकार बन चुकी है। अब गाली देने का नहीं, काम करने का समय है। लेकिन आज भी उन्होंने एक बार फिर अपना असली एजेंडा साफ कर दिया– काम कम, जुमले ज़्यादा; 5 साल सिर्फ गाली-गलौच का इरादा..।

आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बीजेपी ने दिल्ली की जनता से जो वादे किए हैं, उन्हें इस बजट में पूरा किया जाना चाहिए। अगर इस बजट में उनके आवंटन को देखा जाए, तो इसका मतलब है कि सरकार इस साल उन वादों को पूरा करेगी। अगर बीजेपी अपने वादों के लिए पैसे आवंटित करती है, तो वह उन वादों के लिए काम भी करेगी। अगर वे ये आवंटन नहीं करते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके दिमाग में चोर है।

दिल्ली वालों को साफ पानी देने के लिए भाजपा सरकार ने खोला खजाना, टैंकर पर भी बड़ा ऐलान

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली की नई भाजपा सरकार ने आज साल 2025 का बजट पेश किया है। इसमें दिल्लावालों को साफ पानी देने के लिए भाजपा सरकार ने अपने खजाने खोल दिए हैं। रेखा सरकार ने पानी के लिए 9000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। सीएम रेखा गुप्ता ने टैंकर पर भी बड़ा ऐलान किया है। जानिए बजट में क्या है प्रावधान।

सीएम रेखा गुप्ता ने बताया कि हमारी सरकार वाटर टैंकर में जीपीएस लगाएगी। ये सभी मोबाइल से जुड़े होंगे। इनकी निगरानी आरडब्ल्यूए के द्वारा की जाएगी। पानी की पाइपलान को ठीक करने के लिए 10 करोड़ रुपये अलॉट करने की बात कही गई है। इसमें सबसे बड़ी बात पानी के लिए कुल 9000 करोड़ रुपये देने की बात कही गई है।

रेखा गुप्ता ने अपने बजट भाषण में कहा कि स्वच्छता, शुद्ध पानी, स्वच्छ यमुना का अभियान बनेगा दिल्ली की पहचान। रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में क्लीन पानी और स्वच्छ सेनिटेशन उपलब्ध कराना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। रेखा गुप्ता ने कहा कि इस हेड में हमने दिल्ली के लिए ऐतिहासिक बजट रखा है, 9000 करोड़ रुपये का। रेखा गुप्ता ने दावा करते हुए कहा कि ये पुरानी की सरकारों का तिगुना है।

रेखा गुप्ता ने कहा कि जब गर्मी होती है तो टैंकर घोटाले सामने आते हैं। इस बार हमने दिल्ली में इस टैंकर घोटाले को समाप्त करने के लिए वाटर टैंकर में जीपीएस सिस्टम लगाने की व्यवस्था की है। सीएम ने बताया कि ये एन्ड्रायड मोबाइल एप से जुड़ा होगा। इस तरह इन टैंकर की मॉनीटरिंग सभी लोग कर सकेंगे। पाइपलाइन को ठीक करने के लिए हमने प्लानिग की है। इसलिए जल क्षेत्र योजनाओं के परामर्श के लिए 10 करोड़ रुपये देने का प्रावधान किया है।

दिल्ली के बजट में कुल व्यय 31.5 प्रतिशत बढ़ा, पूंजीगत व्यय दोगुना होकर 28,000 करोड़ रुपये हुआ

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता द्वारा पेश किए गए अब तक के सबसे बड़े बजट में कुल व्यय में 31.5 प्रतिशत की भारी वृद्धि की है। इसी के साथ राज्य सरकार का पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) दोगुना होकर 28,000 करोड़ रुपये हो गया है।

विधानसभा सत्र के दूसरे दिन बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, ÷इस बार 2025-26 के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का ऐतिहासिक बजट पेश किया जा रहा है, जो पिछले बजट से 31.5 प्रतिशत अधिक है। यह एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक बजट है।÷ दिल्ली सरकार के बजट में गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि एक स्वास्थ्य योजना है, के लिए 2,144 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए भाजपा के चुनावी घोषणापत्र के हिस्से के रूप में, बजट में 'महिला सम्मान योजना' के लिए पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये प्रति माह देने के लिए 5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बजट में दिल्ली-एनसीआर में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। गरीबों के उत्थान के उद्देश्य से, झुग्गी बस्तियों में विकास के लिए 696 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी में 100 अटल कैंटीन स्थापित करने के लिए वित्त वर्ष 2026 में 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा बढ़ाने के लिए बजट में दिल्ली में 50,000 सीसीटीवी कैमरे लगाने का लक्ष्य रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने सदन में 'मोदी-मोदी' के नारों के बीच दिल्ली का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि यह बजट न केवल सरकार की वित्तीय सेहत से जुड़ा है, बल्कि दिल्ली के लोगों के सपनों और आकांक्षाओं को लेकर भी अहम है। उन्होंने सड़कों की मरम्मत न होने, ड्रेनेज सिस्टम और प्रदूषण का उदाहरण देते हुए पिछली आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ÷यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली विकास के हर पहलू में पिछड़ती चली गई।÷

उन्होंने कहा, ÷भ्रष्टाचार और अक्षमता के दिन अब खत्म हो गए हैं। पिछली सरकार दिल्ली की अर्थव्यवस्था के लिए दीमक की तरह रही। दिल्ली जल बोर्ड, डीटीसी और कई दूसरे सरकारी संस्थान घाटे में चल रहे हैं।÷ सीएम रेखा गुप्ता ने स्थिति को नई सरकार के लिए चुनौती बताया।

शेयर बाजार में निवेश के नाम पर बीटेक छात्र से ठगे 12 लाख

नई दिल्ली (एजेंसी)। आउटर नार्थ साइबर पुलिस स्टेशन ने टेलीग्राम ऐप के माध्यम से बीटेक छात्र से निवेश के नाम पर 12 लाख की ठगी में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से वारदात में प्रयुक्त फोन बरामद किए हैं। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि एनआईटी के बीटेक छात्र ने 12.61 लाख रुपये की ठगी की शिकायत दी थी। पीड़ित ने पुलिस को बताया कि उसे टेलीग्राम ऐप के एक चैनल से जोड़ा गया जहां शेयर बाजार में निवेश के तरीके सिखाए जा रहे थे। फिर चैनल में लोगों के कहने पर उसने अलग-अलग शेयर में ऐप के माध्यम से निवेश किया। इस दौरान उसे शेयर बाजार में लाभ से जुड़ी कई तरह की रील भी दिखाई गई। पीड़ित ने बताया कि जब उसके रुपये वापस नहीं हुए तो ठगे जाने का अहसास हुआ। डीसीपी निधिन वाल्सन ने बताया कि शिकायत के बाद साइबर पुलिस स्टेशन के एसएचओ रमन कुमार सिंह की टीम ने जांच शुरू की। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के आधार पर 20 मार्च को चित्तौड़गढ़ से सुरेश और राहुल को नोटिस दिया। जब दोनों ने जांच में सहयोग नहीं किया, तो पुलिस ने गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की। पुलिस अधिकारी ने बताया कि दोनों ने टेलीग्राम चैनल पर 10 हजार लोगों को जोड़ा था। उन्होंने बताया कि गिरोह के सदस्य चैनल में संभावित शिकार को फंसाने के लिए आकर्षक योजनाओं से लाभ का झांसा देकर लुभाते थे।

दिल्ली बजट 2025: शिक्षा: सीएमश्री स्कूल, मुफ्त लैपटॉप और भाषा लैब संवारेंगे छात्रों का भविष्य

– कुल बजट का 19 फीसद शिक्षा पर खर्च करेगी सरकार 60 नए सीएमश्री स्कूल खोलने के लिए 100 करोड़ का बजट

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री रेखा गुप्ता द्वारा विधानसभा में पेश किया गया बजट शिक्षा के लिए खास है। पहली बार राजधानी के छात्रों के लिए पीएमश्री की तर्ज पर सीएमश्री स्कूल, 10वीं की पढ़ाई पूरी कर चुके 1200 छात्रों को 11वीं में मुफ्त लैपटॉप, भाषाई दिक्कत को देखते हुए छात्रों के लिए भाषा लैब बनाने बनाने सहित कई घोषणाएं इस बार बजट में की गई हैं। भाजपा सरकार ने कुल बजट का 19 फीसदी बजट शिक्षा के लिए रखा है। इसके लिए 19,291 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। विधानसभा में बजट प्रस्तुत करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सभी बच्चों को उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि से परे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, हम आगामी सत्र 2025-26 से 60 नए सीएमश्री स्कूल खोलने की घोषणा करते हैं। यह स्कूल राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूर्ण अनुपालन करेंगे और इनमें नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 लागू किया जाएगा। ये स्कूल पीएमश्री स्कूलों की तर्ज पर ही खोले जाएंगे। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 100 करोड़ की बजट राशि रखी गई है। जबकि लैपटॉप के लिए 7.5 करोड़ रुपए की राशि बजट में निर्धारित की गई है।

जेईई नीट मार्गदर्शन के लिए भी बजट

राजधानी में गरीब या सामान्य बच्चों के लिए भी कोचिंग की सुविधा मंहगी है। इसकी जरूरत को देखते हुए दिल्ली सरकार पहली बार महामना पं. मदनमोहन मालवीय विद्या शक्ति मिशन की भी शुरुआत करने जा रही है। इस पहल के तहत जेईई, नीट, क्लैट, सीए और सीयूईटी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को प्रोफेशनल मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 21 करोड़ की बजट राशि रखी गई है।

राष्ट्रनीति के तहत मंत्री,प्रशासकों से सीधा संवाद कर सकेंगे छात्र– राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पहली बार राजधानी में 'राष्ट्रनीति' की शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए 1.5 करोड़ का विशेष बजट आवंटन किया जा रहा है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय के 12वीं कक्षा तक के छात्रों को शामिल करने वाला यह कार्यक्रम शासन, लोकतंत्र, सक्रिय नागरिकता और नीति निर्माण का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करेगा। इसमें युवा संसद, मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ सीधा संवाद, डिजिटल शासन, भारत के ग्रामीण और दूरदराज के इलाव वर्चुअल दौरा और सामुदायिक जुड़ाव भी शामिल होगा, जिस सुनिश्चित होगा कि छात्र जिम्मेदार, जागरूक और सक्रिय नागरिक बन सकें।

स्थापित की जाएंगी भाषा लैब

दिल्ली के 100 सरकारी स्कूलों में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम भाषा प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। इन प्रयोगशालाओं में आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन और स्पेनिश जैसी कई भाषाएं सिखाई जाएंगी। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 21 करोड़ की राशि प्रस्तावित हैं। इसके अलावा केजी से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए साइंस ऑफ लिविंग कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में इस योजना के लिए 1.5 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

बेरोजगारी के खिलाफ युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय युवा कांग्रेस ने बेरोजगारी और अमेरिका के भारतीयों को हथकड़ियां पहनाकर भेजने के मुद्दे पर मंगलवार दिन में जंतर-मंतर पर प्रदर्शन किया। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि अब केन्द्र सरकार की नाकामियों के खिलाफ देश भर में 'नौकरी दो-जंजीरें नहीं अभियान चलाया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान संसद का घेराव करने के लिए बढ़ रहे युवा कांग्रेस के नेताओं को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया। इससे पूर्व, युवा कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जंतर-मंतर पर जुटे। यहां पर हुई सभा में चिब ने कहा कि अमेरिका से भारतीय नागरिकों को जिस अमानवीय तरीके से हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी पहनाकर भेजा गया, वह काफी शर्मनाक है। यह विश्वपटल पर भारतीयों का अपमान है। केन्द्र सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिर वह इस मामले पर चुप क्यों है। चिब ने कहा कि युवा कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक देश के नागरिकों के हक और सम्मान के लिए इसी प्रकार से लड़ती रहेगी।

'नवरात्रि के दौरान बंद रहनी चाहिए मीट की दुकानें', दिल्ली में बीजेपी विधायक की मांग, सांसद का भी मिला साथ

नई दिल्ली (एजेंसी)। पटपड़गंज से भाजपा विधायक रविंदर सिंह नेगी ने आगामी नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने की मांग की है। उन्होंने कहा कि भले ही यह निर्देश पूरी दिल्ली में लागू न हो, लेकिन वह अपने निर्वाचन क्षेत्र में दुकानें बंद रखने का प्रयास करेंगे। नेगी ने कहा कि मैंने अपने क्षेत्र में मंदिरों के सामने मंगलवार को खुलने वाली मीट की दुकानों के लिए अभियान चलाया था, और अब दुकानें मंगलवार को बंद रहती हैं। नवरात्रि साल में दो बार आती है, मैं सभी व्यापारियों से अनुरोध करता हूं कि वे मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रखें।

नेगी ने आगे कहा कि यह अनुरोध है कि नवरात्रि पर कोई भी मांस की दुकान नहीं खोली जानी चाहिए, खासकर मंदिरों के सामने वाली दुकानें। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में डीएम को भी पत्र लिखूंगा। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में मंगलवार को मीट की दुकानें बंद रखने की पूरी कोशिश करूंगा। भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा कि देश के करोड़ों लोग नवरात्रि में पूजा करते हैं, 9 दिनों तक वे अन्न ग्रहण नहीं करते और फलाहार पर जीवित रहते हैं। इस दौरान अगर आस-पास मीट की दुकानें हैं तो इससे पवित्रता भंग होगी।

भाजपा सांसद ने कहा कि 9 दिनों की बात है, मीट की दुकानें और शराब की दुकानें बंद होनी चाहिए। जब ??साल में दो बार ईद आती है तो दोनों ईद अलग-अलग तरीके से मनाई जाती हैं, इसलिए नवरात्रि के दौरान दिल्ली में मीट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए। अन्य राज्यों में भी नेताओं ने मंदिरों और धार्मिक स्थलों के पास स्थित मांस और शराब की दुकानों को बंद कराने की पहल की। पिछले वर्ष मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि नर्मदा नदी की पवित्रता और आशीर्वाद को बनाए रखने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं तथा राज्य भर के धार्मिक शहरों में शराब और मांस की दुकानों पर प्रतिबंध लगाने की योजना है।

शराब प्रेमियों की मौज! एक के साथ एक फ्री ऑफर ने मचाई हलचल

ठेकों पर टूट पड़े लोग

नॉएडा/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में शराब के ठेकों पर इन दिनों जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है. शराब की दुकानों पर एक बोतल के साथ एक फ्री का ऑफर दिया जा रहा है. जैसे ही शराब प्रेमियों को इस ऑफर की जानकारी मिली. वे बड़ी संख्या में ठेकों पर पहुंच गए. ठेकों के बाहर इतनी भीड़ हो गई कि कई जगह अफरातफरी मच गई.भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया है. अधिकारियों का कहना है कि अगर स्थिति बेकाबू हुई तो सख्त कदम उठाए जा सकते हैं. दरअसल, शहर के प्रेमनगर, इज्जतनगर, बा-

रादरी और कोतवाली क्षेत्रों में स्थित शराब के ठेकों पर ग्राहकों की लंबी कतारें लगी हुई हैं. लोग अपनी पसंदीदा शराब खरीदने के लिए लाइन में खड़े हैं. और जल्दी से जल्दी स्टॉक लेने की होड़ मची हुई है. ठेकों पर भीड़ इतनी अधिक हो गई कि कई जगह लोग एक-दूसरे के ऊपर चढ़े नजर आए. कई ग्राहकों का कहना है कि ऐसा ऑफर दोबारा शायद ही मिले. इसलिए वे ज्यादा से ज्यादा शराब खरीदने की कोशिश कर रहे हैं. यह ऑफर चड्ढा ग्रुप ने दिया है. शराब की दुकानों पर यह ऑफर 31 मार्च तक के स्टॉक को खत्म करने के लिए दिया जा रहा है. दुकानदार अपने बचे हुए स्टॉक को जल्द से जल्द निपटाना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने ग्राहकों को लुभाने के लिए यह स्कीम शुरू की है. ठेकों के बाहर खड़े लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि ज्यादातर लोग ज्यादा से ज्यादा शराब स्टॉक करने के इरादे से आए हैं. कुछ लोगों ने तो घर में रखने के लिए 4-5 बोतलें खरीद ली हैं. शराब प्रेमी इस ऑफर का फायदा उठाने के लिए अपने रोजमर्रा के काम छोड़कर ठेकों की तरफ भाग रहे हैं. कुछ लोगों ने ऑफिस से छुट्टी ले ली, तो कुछ ने अपने जरूरी काम भी टाल दिए. ठेकों के बाहर लोगों की भारी भीड़ को देखते हुए कुछ स्थानों पर पुलिस भी तैनात करनी पड़ी. कुछ शराब प्रेमियों का कहना है कि उन्हें यह ऑफर बेहद खास लग रहा है. उनका कहना है कि आमतौर पर शराब महंगी मिलती है, लेकिन इस ऑफर के चलते उन्हें दोगुनी मात्रा में शराब मिल रही है. इस वजह से कई लोग पार्टी करने की भी योजना बना रहे हैं. भीड़ के कारण कई जगह ठेकों के बाहर अफरा-तफरी मच गई. कुछ ठेकों पर तो ग्राहकों के बीच बहस और धक्का-मुक्की भी देखने को मिली. दुकानदार भीड़ को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी भीड़ में स्थिति काबू में रखना मुश्किल हो रहा है. शहर में इस तरह की भीड़ को देखते हुए प्रशासन भी सतर्क हो गया है. अधिकारियों का कहना है कि अगर स्थिति बेकाबू हुई तो सख्त कदम उठाए जा सकते हैं. हालांकि, फिलहाल प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और जरूरत पड़ने पर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है.

दिवंगत सपा नेता के घर पहुंचे पूर्व विधायक संतोष पांडे

लंभुआ/सुलतानपुर/ भव्य खबर। सड़क दुर्घटना में हुई मौत पर दिवंगत सपा नेता के घर पूर्व विधायक, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी शकील अहमद तथा जिला अध्यक्ष पहुंचकर शोक संतृप्त परिवार से मिले और श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए पीड़ित परिवार को एक लाख की आर्थिक सहायता दी, तथा आगे भी परिवार की हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।लंभुआ तहसील क्षेत्र के राजवाड़े रामपुर निवासी विधानसभा सचिव व सेक्टर प्रभारी सपा नेता अमरजीत यादव का 22 मार्च को घरवासपुर गांव के निकट लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था। परिवार के लिए सहारा बने सपा नेता श्री यादव की भी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मंगलवार को पूर्व विधायक संतोष पांडे तथा जिला अध्यक्ष रघुवीर यादव शोक संतृप्त परिजनों के बीच पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार को एक लाख रुपए की आर्थिक मदद दी और आगे भी हर संभव मदद करने का भरोसा दिलाया।

5000 के लिए पुलिस ने महिला को दिया जिंदगीभर का दर्द, बेटे की लाश को सीने से लगाकर बोली- लखनऊ ले जाएंगे तो देखना बोलने लगेगा

लखनऊ/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव। **'अभी बोल रहा था...अब बोल नहीं रहा, हम लखनऊ ले जाएंगे तो देखना बोलने लगेगा'** यह एक अभागी मां की उम्मीद है, अपने सीने से बेजान बेटे को चिपकाए वो तड़प-तड़पकर बस यही आस लगा रही है. उसका बेटा अभी उठ जाएगा, उससे बात करेगा. लेकिन उसे नहीं मालूम उसके जिगर का टुकड़ा जिंदगी भर के लिए खामोश हो गया है. उत्तर प्रदेश के बस्ती में पुलिस की क्रूरता ने एक मां से उसके बेटे को छीन लिया. उसे इतना पीटा कि उसकी जान चली गई. शायद जान बच जाती! अगर उसके पास 5 हजार रुपये का इंतजाम होता. मां का कहना है कि उसके बेटे को छोड़ने के लिए पुलिसवालों ने उससे 5 हजार रुपये की डिमांड की थी.मामला बस्ती जिले के दुबौलिया थाने के उभाई गांव का है. यहां के 17 वर्षीय आदर्श उपाध्याय को थाने ले जाकर पुलिस ने बेरहमी से इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई. आदर्श कोई अपराधी नही था. गांव का सीधा-सादा लड़का. गाय चराता और परिवार के काम में हाथ बटाता था. उसका कुसूर सिर्फ इतना था कि उसने गांव के एक सेठ से तंबाकू मांग ली. यह उस सेठ को नागवार गुजरी. विवाद हुआ और सेठ ने पुलिस बुला ली. उसके बाद पुलिस ने जो किया उससे एक मां का बेटा उससे छीन लिया.

रात भर पीटा, फिर सुबह भी की पिटाई

घटना के मुताबिक, सोमवार को दुबौलिया थाने की पुलिस आदर्श को गांव से उठाकर ले गई. उसे रात भर पीटा. परिजनों के मुताबिक, पुलिस ने आदर्श को थर्ड डिग्री दी. पुलिसवालों का मन इससे नहीं भरा, उसे मंगलवार की सुबह फिर से पीटा गया. बिलखती मां ने रोते हुए बताया कि उसके बेटे को छोड़ने के लिए पुलिसवालों ने 5000 रुपये मांगे. गरीब परिवार पैसे नहीं दे पाया तो पुलिस ने आदर्श को जानवरों की तरह पीटा, उसे इतना मारा कि उसके मुंह से खून आने लगा. हालत बिगड़ते देख पुलिसवालों ने उसे उसके घर ले जाकर छोड़ दिया.

अस्पताल में तोड़ दिया दम

परिवारवालों ने जब आदर्श की बिगडती तबीयत देखी तो वह घबरा गए. वह उसे आनन-फानन में सीएचसी हरैया ले जाया गया. डॉक्टर ने आदर्श की गंभीर हालत देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया. लेकिन, वह उसे जिला अस्पताल ले जाते उससे पहले ही आदर्श ने रास्ते में दम तोड़ दिया. आदर्श की मौत से परिजनों में चीख-पुकार मच गई. गांव में मातम छा गया. आदर्श को बुरी तरह पीटने वाले पुलिसवालों की

हैवानियत से परिजन और ग्रामीणों में गुस्सा पनप गया.

बेटे की छोड़ने के लिए मांगे 5000 रुपये

मृतक आदर्श की मां ने बताया कि पुलिसवाले उसके बेटे को उठाकर ले गए. उसे रात-दिन पीटा. पुलिसवालों ने गांव में फोन किया. प्रधान को फोन कर उन्हें बताया. पुलिसवालों ने उनसे कहा कि जल्दी थाने आओ. वह मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे अपने छोटे बेटे के साथ थाने पहुंची. वहां पुलिस ने उनसे कहा कि 5000 रुपये देकर अपने बेटे को ले जाओ, वरना पता नहीं लगेगा उसका.पुलिसवालों ने कागज पर उसके छोटे बेटे से कुछ जबरन लिखवाया.

मां ने बताया कि उसे थाने से आदर्श को दिया तो उसकी तबीयत खराब थी. वह गांव से पैदल थाने पहुंची थी. बेटे की तबीयत बिगड़ रही थी. उसके मुंह से खून आ रहा था.

उसने पुलिसवालों से विनती की लेकिन उन्होंने नहीं सुनी. वह खुद एंबुलेंस के जरिए बेटे को लेकर अस्पताल पहुंची.

ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, कार्रवाई की मांग

घटना के बाद परिजन और ग्रामीणों ने दोषी पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर मुकदमा दर्ज करने की मांग पर अड़ गए. उन्होंने आदर्श के शव के साथ प्रदर्शन किया. जानकरी मिलते ही पुलिस के अफसर मौके पर पहुंचे.

सीओ सिटी ने परिजनों के मान मनव्वल किया. रात में कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद परिजन बेटे के शव के पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए.

मेरठ में नौचंदी मेले को लेकर खड़ा हो गया बवाल? मंत्री की दखल के बाद हटाना पड़ गया नोडल अफसर

मेरठ/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के मेरठ में नौचंदी मेले के नोडल अफसर को बदल दिया गया है। आईएएस अफसर नुपुर गोयल को अब ये जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। दरअसल, भाजपा के कुछ पार्षदों ने इस बात पर विरोध जताया था। उनका कहना था कि जिला प्रशासन ने मेरठ के मेयर हरिकांत अहलुवालिया का इंतजार नहीं किया और मेले का उद्घाटन कर दिया।मेयर अहलुवालिया ने इस बारे में कहा, ये मेला मेरठ नगर निगम (एमएमसी) और जिला पंचायत मिलकर आयोजित करते हैं। इस बार एमएमसी की जिम्मेदारी थी, लेकिन डीएम ने सीडीओ को नोडल अफसर बना दिया, जबकि ये जिम्मेदारी नगर आयुक्त को मिलनी चाहिए थी। मैं उद्घाटन में सिर्फ 10-12 मिनट लेट पहुंचा था, लेकिन उन्होंने मेरा इंतजार नहीं किया। मुझे समझ नहीं आता कि डीएम और सीडीओ ने किसी भाजपा एमएलए या संसद सदस्य के बिना ही मेला क्यों शुरू कर दिया? एमएमसी के अधिकारियों ने उनसे इंतजार करने को कहा था, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्होंने किसी भी प्रतिनिधि को जानकारी तक नहीं दी। इस घटना के बाद बीजेपी पार्षदों ने विरोध प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन तब हुआ जब राज्य के पशुपालन मंत्री धर्मपाल सिंह शहर में आए। उन्होंने कहा, ये मामला मेरे सामने लाया गया। उनकी परेशानी को दूर करने के लिए सीडीओ को हटा दिया गया है। अब नगर आयुक्त नौचंदी मेले के नए नोडल अफसर होंगे। बता दें नौचंदी मेला बहुत पुराना है। ये लगभग 400 साल से लग रहा है। ये मेला हजरत बाले मियां की दरगाह और चंडी देवी मंदिर के पास लगता है। इतिहास में लिखा है कि हजरत बाले मियां को एक शुक्रवार की रात को मार दिया गया था। वो रात नए चांद की रात थी, इसलिए उसे 'नया चांद रात' भी कहा जाता है। ये घटना 12 अप्रैल, 1034 को हुई थी। बाले मियां की मजार के ठीक सामने एक मंदिर है, जिसे चंडी देवी मंदिर कहते हैं। वो मंदिर आज भी वहीं है। इस मेले में हिंदू और मुस्लिम दोनों ही समुदाय के लोग आते हैं।

कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे... मेरठ में कथा के बीच अचानक ऐसा क्यों बोले बाबा बागेश्नर?

मेरठ/ भव्य खबर। उत्तर प्रदेश के मेरठ में मंगलवार को बागेश्वर धाम वाले पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पहुंचे. यहां वह 29 मार्च तक रहेंगे. यहां वह पांच दिवसीय कथा के लिए पहुंचे हैं. मंगलवार को हनुमंत कथा का आयोजन किया गया. 150 सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के लिए लगाए गए. भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे. हनुमंत कथा के दौरान कथा के साथ बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने और भी बातें लोगों से कीं. धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि हम दिल्ली-मेरठ ब्रजवासियों के घर-घर जाएंगे. उन्हें शपथ दिलाएंगे. गांव-गांव जाकर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की अलख जगाएंगे. उन्होंने मुसलमानों के लिए आगे कहा कि हम मुसलमानों के विरोधी नहीं है. भारत को आजादी दिलाने में मुसलमानों का भी योगदान है. लेकिन कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे. बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने कथा के पहले दिन ये बात कहीं. बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि हम दिल्ली से वृंदावन तक पदयात्रा निकालेंगे. इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कई लोग कहते हैं कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, हम उनसे कहना चाहेंगे कि ये देश संविधान से चलेगा. ये देश हनुमान से चलेगा. यही नहीं उन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि इस देश में संतों के एक हाथ में संविधान हो और एक हाथ में पुराण हो. अब हिंदू मिट न जाए. हिंदुओं पर धावा न बोला जाए. उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हुए कहा कि बाबर और अकबर को महान न बताया जाए. भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए. जागृति विहार एक्सटेंशन में आयोजित की जा रही हनुमंत कथा सुनने के लिए उत्तर प्रदेश के साथ-साथ हरियाणा, दिल्ली समेत कई राज्यों से श्रद्धालु कथा शुरू होने से भी एक दिन पहले ही कथा स्थल पर पहुंच गए थे. अब भी लोग बाबा धीरेंद्र शास्त्री की कथा सुनने के लिए आ रहे हैं. इसलिए कथा का बड़े स्तर पर आयोजन किया गया. क्योंकि आयोजकों ने कथा में 5 लाख लोगों के पहुंचने की उम्मीद जताई है.

योगी सरकारः 8 साल बेमिसाल

यूपी में लिंगानुपात में हुआ ऐतिहासिक सुधार, 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं, सुरक्षित मातृत्व के लिए योगी सरकार की योजनाओं ने किया कमाल, मातृ और शिशु मृत्यु दर में अभूतपूर्व गिरावट

लखनऊ/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश में बीते आठ वर्षों में महिला सशक्तीकरण को लेकर जो परिवर्तन हुए हैं, वे ऐतिहासिक और प्रेरणादायक हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता देते हुए ऐसी योजनाओं को लागू किया, जिन्होंने न केवल महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा किया, बल्कि पूरे समाज को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाने का कार्य किया। योगी सरकार के सतत प्रयासों और जागरूकता अभियानों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में महिला-पुरुष लिंगानुपात में ऐतिहासिक सुधार दर्ज किया गया है। आंकड़ों के अनुसार, अब प्रति 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं, जो दशार्ता है कि कन्या भ्रूणहत्या जैसी कुप्रथाओं पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है। सरकार की योजनाओं और "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" जैसे अभियानों ने लोगों की मानसिकता को बदला है और बेटियों को समान अवसर प्रदान करने की दिशा में प्रदेश ने उल्लेखनीय प्रगति की है। योगी सरकार द्वारा महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाएं समाज में बड़ा बदलाव ला रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में ह्यबेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई कन्या जन्मोत्सव पहल ने पूरे देश में एक मिसाल कायम की है। इस पहल का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म को उत्सव की तरह मनाना और समाज में लड़कियों के प्रति सकारात्मक सोच विकसित करना है। प्रदेश में अब तक 3,822 कार्यक्रम आयोजित कर 35,489 बालिकाओं के जन्म का उत्सव मनाया जा चुका है।

बालिका सशक्तीकरण की दिशा में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना महत्वपूर्ण

बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए योगी सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं। इनमें मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एक अहम योजना है, जिसके तहत अब तक 23 लाख से अधिक लाभार्थियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस योजना के तहत बालिका के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा तक आर्थिक सहायता दी जाती है। महिला एवं बाल विकास विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत - बालिका के जन्म पर 5,000 रुपये व एक वर्ष तक के पूर्ण टीकाकरण पर 2,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा कक्षा 1 और 6 में प्रवेश पर 3,000-3,000 रुपये दिए जाते हैं। इसके अलावा कक्षा 9 में प्रवेश पर 5,000 रुपये और 10वीं या 12वीं पास करने के बाद स्नातक या डिप्लोमा में प्रवेश पर 7,000 रुपये दिए जा रहे हैं। इस तरह, एक लाभार्थी को कुल 25,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है, जिससे उसकी शिक्षा और भविष्य सुरक्षित हो सके।

'कन्या जन्मोत्सव' सामाजिक मानसिकता में बदलाव की अनूठी पहल

उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को समाप्त करने और समाज में लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए कन्या जन्मोत्सव की शुरूआत की। इस कार्यक्रम के तहत नवजात बालिकाओं के जन्म को उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कार्यक्रम में पिता, भाई, परिवार के अन्य सदस्य, जनप्रतिनिधि और समाज के गणमान्य लोग शामिल होते हैं, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि बालिका के जन्म को सकारात्मक रूप से देखा जाए। प्रदेश में इस पहल के तहत हर महीने के पहले और तीसरे सोमवार को जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, ताकि समाज में लड़कियों के महत्व को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सके।

सामाजिक भागीदारी से बढ़ी कार्यक्रम की प्रभावशीलता

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कन्या जन्मोत्सव को केवल सरकारी योजना तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे सामाजिक आंदोलन में बदला है। इस पहल में महिला एवं बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज और स्थानीय प्रशासन को एकीकृत किया गया है, जिससे इसका प्रभाव व्यापक हो सके। इस कार्यक्रम में समुदाय की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जाता है। पिता, भाई, दादा-दादी, गांव के प्रधान और अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इस पहल का हिस्सा बनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य पितृसत्तात्मक मानसिकता को समाप्त करना और समाज में लैंगिक समानता की भावना विकसित करना है।

लैंगिक समानता की दिशा में योगी सरकार का बड़ा कदम

कन्या जन्मोत्सव केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि समाज में एक सतत सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। यह पहल लैंगिक भेदभाव और पूर्वाग्रहों को चुनौती देती है तथा समावेशिता और समानता को प्रोत्साहित करती है। सरकार के प्रयासों से उत्तर प्रदेश में लड़कियों की जन्म दर में वृद्धि दर्ज की गई है और समाज में सकारात्मक बदलाव देखा जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया है, जहां लड़कियों का जन्म खुशी और गर्व का विषय बने। वहीं, लिंगानुपात यानी प्रति एक हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या बढ़ी है। शहरी क्षेत्र में जहां यह प्रति 1000 पुरुष पर 985 महिला हैं वहीं ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का लिंगानुपात 1000 पुरुषों के मुकाबले 1037 है। यानि प्रदेश की महिलाओं की संख्या प्रति हजार पुरुष के सापेक्ष बढ़कर 1020 हो गई हैं। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के सख्त उपाय और परिवार नियोजन के प्रति बढ़ी जागरुकता का यह नतीजा है।

मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में अभूतपूर्व गिरावट

महिला और शिशु स्वास्थ्य की दिशा में किए गए प्रयासों के चलते प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सरकार द्वारा चलाई गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जननी सुरक्षा योजना, मिशन इंद्रधनुष और विभिन्न स्वास्थ्य अभियानों ने गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के जीवन को सुरक्षित बनाया है। योगी सरकार ने अत्यंत गरीब और कुपोषण से ग्रसित महिलाओं और बच्चों के लिए अनुपूरक पुष्टाहार योजना के तहत दो लाख से अधिक लाभार्थियों को पुष्टाहार उपलब्ध कराया है। खासकर गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों के लिए इस योजना ने पोषण स्तर में सुधार लाकर उनके जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाया वहीं किशोरी बालिकाओं के लिए चलाई जा रही योजना के अंतर्गत प्रदेश के आठ आकांक्षात्मक जिलों के 2 लाख 10 हजार से अधिक किशोरी बालिकाओं को चिन्हित कर उनका सर्वांगीण विकास किया जा रहा है।

संक्षिप्त डायरी

कांग्रेस-सपा ने मुस्लिम को सिखाया नफरत,एनडीए सरकार में 51 बच्चे बने आईएएस-ओपी राजभर

सुलतानपुर/ भव्य खबर। वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में दिल्ली के जंतर-मंतर पर मुस्लिम समुदाय द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा। ओवेसी और इमरान मसूद जैसे नेता इसको लेकर सरकार के विरोध में बयान दे रहे। जिस पर मंगलवार को सुल्तानपुर में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर ने हंसते हुए बड़ा खुलासा किया। 'उन्होंने कहा कि एक बार लखनऊ मीटिंग में आए थे हमने पूछा तो कहे ये कुल नेतागिरी है वोट सोट का बात है हो रहा है। ओपी राजभर ने ये भी कहा कि कुछ मुसलमान जो मजबूत हैं वो मुसलमानों का हक लूट रहे हैं। वक्फ बोर्ड की जमीनो को बेचना खरीदना बिला वजह का पैसा कमा रहे। सरकार की मंशा है जो गरीब मुसलमान है, महिलाएं हैं, नवजवान है उनको भी वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति का लाभ मिले। ये इनकी नियमावली है, कि कहेंगे जमीन हमारी है। जाएगे डीएम को दरखास्त देंगे खाली कराओ। सरकार कह रही है कागज दो आपके पास खसरा खतौनी है नहीं तो 1359 की फसली हो तो ले आओ दो कौन सा बुरा बात कह रही है। 2016-17 से पहले जो अपराधी सुट्टा सांड की तरह घूमते थे आज उन अपराधियों और माफियओं पर पूर्ण रूप से अंकुश लगा है। प्रदेश में जो दंगे और कर्फ्यू लगते थे आज उस पर भी विराम लगा है। अखिलेश के यूपी बर्बाद के बयान पर उन्होंने कहा, कांग्रेस, सपा नफरत फैलाते हैं। आजादी के बाद पहली बार एनडीए सरकार में मुस्लिम बच्चे जिनको वो नफरत पढ़ाते हैं आईएएस पास किए हैं। कल वो एसडीएम बनेगा, सीडीओ बनेगा वो डीएम बनेगा। इन लोगों को चिंता इस बात की है कि जब ये कुर्सी पर होगा तो वो सबका साथ सबका विकास का नारा लगाएगा। अपनी काम्युनिटी में वो नफरत को खत्म करने का प्रयास करने का काम करेगा इसको ही लेकर चिंतित है।

ईद पर यूपी के मुस्लिमों को मिलेगी 'सौगात-ए-मोदी' किट

लखनऊ/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव। मुस्लिमों के बीच पैठ बढ़ाने के लिए भाजपा ईद पर 'सौगात-ए-मोदी किट बांटेगी। किट में गरीब मुस्लिमों के लिए ईद पर इस्तेमाल होने वाला सामान होगा, जिससे वे भी त्योहार को ढंग से मना सकें। इसकी जिम्मेदारी भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे ने संभाली है। पूरे देश में 32 लाख गरीब मुस्लिमों तक यह किट पहुंचाने की योजना है। यूपी में 5 से 7 लाख मुस्लिमों को यह सौगात दी जाएगी। शुरूआत मंगलवार को पुराने लखनऊ से की गई। करीब 100 मुस्लिमों को यह किट सौपी गई। भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा इस बार ईद के मौके पर 32 लाख गरीब मुसलमानों को सौगात-ए-मोदी नाम से एक-एक किट देगा। इस किट में सेवई, चीनी और मेवे के साथ-साथ कपड़े भी होंगे। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने मंगलवार को बताया कि मोर्चा इस बार ईद के मौके पर देशभर के 32 लाख गरीब मुसलमानों को त्योहार के लिए जरूरी सामान की एक किट देगा जिसका नाम ह्यसौगात-ए-मोदीह्ल होगा। उन्होंने बताया कि इस किट में सेवई के साथ-साथ चीनी, मेवे और महिलाओं के कपड़े भी होंगे। अली ने बताया कि यह अभियान मंगलवार को शुरू किया गया जिसके तहत भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के पदाधिकारी 32 हजार मस्जिदों में जायेंगे और वहां से जानकारी प्राप्त करके संबंधित इलाके के 100-100 गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर ह्यसौगात-ए-मोदीह्ल किट उपलब्ध करवाएंगे। उन्होंने बताया कि इस पहल का मकसद गरीब मुस्लिम परिवारों को भी ईद की खुशियां मनाने का मौका देना है तथा यह भाजपा की अंत्योदय की भावना के अनुरूप है। अली ने कहा कि पार्टी ने हमेशा 'सबका साथ, सबका विकास' की भावना से काम किया है और यह पहल भी उसी दिशा में उठाया गया एक कदम है।

बलिया में स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडेय के वंशजों की किस्मत चमकी, कच्चे तेल के लिए ओएनजीसी ने शुरू की खोदाई

वाराणसी/ भव्य खबर। बलिया में कच्चे तेल और गैस का बड़ा भंडार मिलने की उम्मीद जगी है। ऑइल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) ने तेल निकालने के लिए खोदाई शुरू कराई है। यह खोदाई देश में सबसे पहले बलिया को आजाद करवाने वाले स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडेय के वारिसों की जमीन सागरपाली में हो रही है। यहां तीन हजार मीटर गहरा कुआं खोदा जा रहा है। यहां से पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद गंगा बेसिन में कई स्थानों पर खोदाई की जाएगी। ओएनजीसी ने तीन साल लगातार तक बलिया से लेकर प्रयागराज तक गंगा बेसिन में सैटलाइट, भू-रासायनिक, गुरुत्वार्षण-चुंबकीय और मैग्नेटो-टेल्यूरिक (एमटी) सर्वेक्षण करवाया था। सर्वे रिपोर्ट में बेसिन की गहराई में बड़े तेल व गैस भंडार होने का पता चला था। रिपोर्ट के मुताबिक इस भंडार की बदौलत देश दशकों तक कच्चे तेल और गैस के मामले में आत्मनिर्भर हो सकता है। सर्वे के आधार पर अब ओएनजीसी ने केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से एनओसी यानी अनुमति हासिल कर सागरपाली में खोदाई शुरू करवाई है। इसके लिए क्रेन एवं बड़ी मशीनें और अत्याधुनिक उपकरण मंगाए गए हैं। खोदाई के लिए करीब आठ एकड़ एरिया को बाड़ लगाकर घेर दिया गया है। तीन हजार मीटर गहरी बोरिंग के लिए रोजाना 25,000 लीटर पानी का इस्तेमाल हो रहा है। उम्मीद है कि अप्रैल के आखिर तक तेल भंडार की सतह तक बोरिंग का काम पूरा हो जाएगा। ओएनजीसी ने स्वतंत्रता सेनानी चितू पांडेय के वारिसों की करीब साढ़े छह एकड़ जमीन सालाना दस लाख रुपये के भुगतान पर पट्टे पर ली है। अभी पट्टा तीन साल के लिए हुआ है। यदि सबकुछ ठीक रहा तो तेल निकालने का प्लांट लगाने के लिए इस जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। जमीन के स्वामी नील पांडेय ने बताया कि अगर खोदाई में तेल मिल जाता है तो आसपास की जमीनों का भी ओएनजीसी अधिग्रहण करेगी। ऐसे में किसानों को बहुत फायदा होगा। ओएनजीसी द्वारा कराए गए सर्वे के मुताविक कच्चे तेल और गैस का अकूत भंडार वलिया के सागरपाली गांव से प्रयागराज फाफामऊ तक करीव 300 किलोमीटर में फैला है। इस भंडार के मिलने पर भारत की तेल के मामले में अरव व अन्य देशों पर निर्भरता कम जाएगी। इस विशाल भंडार से कई दशकों तक तेल और प्राकृतिक गैस मिलती रहेगी।

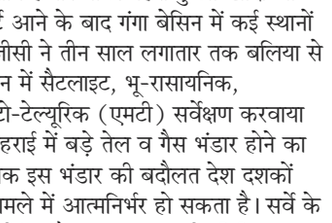

राहुल गांधी के साथ बिहार कांग्रेस के नेताओं की बैठक

दिल्ली में MP-विधायक और पार्टी के बड़े नेता होंगे शामिल, विधानसभा चुनाव पर होगी चर्चा

पटना। दिल्ली में आज बिहार कांग्रेस के नेताओं की बड़ी बैठक बुलाई गई है। इसे लेकर पार्टी के सभी सांसदों, विधायकों और विधान पार्षदों को दिल्ली बुलाया गया है। बैठक में बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और प्रभारी कृष्णा अल्लावरू भी शामिल होंगे। बैठक 2 बजे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के सीनियर लीडर राहुल गांधी के नेतृत्व में होगी। ये बैठक अचानक बुलाई गई है। बिहार कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बैठक के एजेंडे पर फिलहाल कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उन्हें दिल्ली बुलाया गया है और वे जा रहे हैं। वहां किस मुद्दे पर बातचीत होगी, इसकी कोई जानकारी नहीं है। इससे पहले कांग्रेस संगठन की एक बड़ी बैठक सोमवार को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में हुई थी। इसमें प्रदेश प्रभारी कृष्ण अल्लावरू ने विधायकों और जिलाध्यक्षों से संगठन में फेरबदल को लेकर चर्चा की थी। प्रदेश कांग्रेस में हुए फेरबदल और अखिलेश सिंह की छुट्टी के बाद ये पहली बैठक बुलाई गई है। सूत्रों की मानें तो इसमें राहुल गांधी संगठन को एक्टिव करने और विधानसभा चुनाव में गठबंधन के अलग-अलग मुद्दों पर बात कर सकते हैं।

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, ये समीक्षा बैठक 12 मार्च को ही होनी थी, लेकिन तब अचानक बैठक को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह की छुट्टी कर उनकी जगह राजेश राम के हाथ में प्रदेश कांग्रेस की कमान दी। इस फेरबदल के बाद अब ये बैठक बुलाई गई है। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस के भीतर हो रहे बदलाव को सीट शेयरिंग से जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा कर कांग्रेस गठबंधन में राजद पर दबाव बनाना चाहती है। इस बार भी कांग्रेस हर हाल में पिछली बार की तरह 70 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस की प्रेशर पॉलिटिक्स को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। दरअसल पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 70 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 19 सीट पर जीत हासिल की थी। इसके बाद तेजस्वी यादव ने कांग्रेस पर हार का ठीकरा फोड़ा था। तेजस्वी ने कहा था कि अगर कांग्रेस को कम सीटें दी जाती तो राज्य में महागठबंधन की सरकार बन जाती। एक दिन पहले राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इस आयोजन में कांग्रेस की एकमात्र विधायक प्रतिमा दास शामिल हुई थीं। जबकि पार्टी के नवनियुक्त अध्यक्ष राजेश राम से लेकर प्रदेश प्रभारी कृष्ण अल्लावरू तक सभी शाम तक पटना में ही थे, लेकिन इफ्तार पार्टी में नहीं पहुंचे। इसके बाद कृष्ण अल्लावरू देर शाम दिल्ली के लिए रवाना हुआ थे। विधायकों ने सदन के बजट सत्र में हिस्सा भी लिया था। इसके बाद भी इन्होंने लालू के कार्यक्रम से दूरी बनाई। कांग्रेस नए प्रदेश प्रभारी की घोषणा हुए लगभग एक महीने का वक्त बीत चुका है। इस दौरान ज्यादातर समय वे बिहार में ही बीता रहे हैं। इसके बाद भी कृष्ण अल्लावरू की राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और गठबंधन दल के नेता तेजस्वी यादव से किसी प्रकार की कोई मुलाकात नहीं हुई है। वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस नेता कन्हैया बिहार में पलायन रोको रोजगार दो यात्रा पर हैं। वे 9 दिन में लगभग 8 जिले की यात्रा पूरी कर चुके हैं। बैठक में इस यात्रा के इंपैक्टर पर भी चर्चा हो सकती है।

बच्चे को बचाने में गिरा बाइक सवार

जमुई। के गिद्धौर में रविवार रात एक बाइक सवार युवक सड़क पर अचानक आए बच्चे को बचाने के प्रयास में संतुलन खो बैठा और वह सड़क किनारे गिर गया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बादस्थानीय लोगों ने उसे दिग्विजय सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घायल की पहचान गिद्धौर थाना क्षेत्र के छतरपुर गांव निवासी मंटु यादव(18) के रूप में हुई है। जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी सामने आई। अस्पताल में स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं था। परिजनों को मजबूरन घायल को गोद में उठाकर इमरजेंसी वार्ड ले

जाना पड़ा।घायल के भाई मुरारी यादव ने बताया कि उनका भाई सामान्य गति से बाइक चला रहा था। गिद्धौर पोस्ट ऑफिस के पास अचानक एक बच्चा सामने आ गया। बच्चे को बचाने के प्रयास में वह गिर गया। सिर में आई गंभीर चोट डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद सिर में गंभीर चोट के कारण युवक को सदर अस्पताल जमुई रेफर कर दिया।

सीएम नीतीश पर तंज, 'तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके

पटना। में विधानसभा चुनाव से पहले आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। चुनावी बयानबाजी के साथ-साथ पोस्टर वार भी शुरू हो गया है। पटना में एक बार फिर राबड़ी देवी के आवास के बाहर पोस्टर लगाया गया है। इसमें NRC और वक्फ संशोधन बिल को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। पोस्टर पर मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ लिखा, 'तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके....। NRC पर हम तुम्हारे साथ

नहीं। WAQF पर तो बिल्कुल भी साथ नहीं। वोट लेंगे तुम्हारा लेकिन साथ नहीं देंगे।' पोस्टर आरजेडी नेता और जहानाबाद मखदुमपुर से पूर्व जिला पार्षद संजू कोहली की ओर से लगाया है। इससे पहले 23 मार्च को राबड़ी देवी के आवास के बाहर मुख्यमंत्री को लेकर एक पोस्टर लगाया गया था। इसमें नीतीश कुमार को नॉन सीरियस सीएम बताया गया था। पोस्टर पर मुख्यमंत्री की तस्वीर के साथ लिखा, 'द नॉन सीरियस चीफ मिनिस्टर, जन गण मन अधिनायक जय हे नहीं, कुर्सी कुर्सी कुर्सी कुर्सी जय हे।' हालांकि ये पोस्टर किस संगठन की ओर से लगाया था। इसका कोई जिक्र नहीं किया था। किसी राजनीतिक दल या संगठन का नाम इस पर नहीं लिखा गया था।22 मार्च को भी राबड़ी देवी के आवास के बाहर एक पोस्टर लगाया था। जिसमें नीतीश कुमार को 'खलनायक' बताया गया था। पोस्टर पर लिखा था, 'नायक नहीं, जी हां मैं हूं खलनायक। हां, मैंने किया है महिलाओं का अपमान। गांधी जी का किया है अपमान। अब हो गया है राष्ट्रगान का अपमान। जी हां, मैं हूं खलनायक।'

शराब मामले में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला

बगहा। के सेमरा थाना स्थित दढ़िया गांव में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर ग्रामिणों ने हमला कर दिया। जिसमें दो पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। बताया गया कि छापेमारी में सुपनेखा नाम की एक लड़की की नाक बुरी तरह कट गई, जिसे लेकर इलाके में गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही ग्रामीणों ने नाक से बहते खून का फव्वारा देखा, उन्होंने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और गाड़ियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। जानिए क्या है पूरा मामला? बगहा उत्पाद विभाग के इंस्पेक्टर प्रभुनाथ सिंह ने बताया कि उन्हें गांव में अवैध शराब बनाने की

सूचना मिली थी। इसी के आधार पर पुलिस की एक टीम गठित कर छापेमारी के लिए भेजी गई। लेकिन जैसे ही पुलिस गांव में पहुंची, ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस झड़प में दो पुलिसकर्मी जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सुपनेखा की मां कोशीला देवी ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उनकी बेटी की बेरहमी से पिटाई की गई। जिसमें उसकी नाक बुरी तरह कट गई। उन्होंने कहा, मेरे पति पुलिस की रात में छापेमारी का विरोध कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर हमला कर दिया। जब मेरी बेटी उन्हें बचाने गई, तो पुलिस ने उसे भी पीट दिया, जिससे उसकी नाक से खून बहने लगा। जैसे ही गांववालों ने सुपनेखा की कटी हुई नाक और खून से सनी हालत देखी, उनका गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने पुलिस टीम को घेर लिया और जमकर पथराव किया। इस दौरान पुलिस की गाड़ियां भी तोड़ी गईं। हमला करने वालों पर होगी कार्रवाई इंस्पेक्टर प्रभुनाथ सिंह ने कहा कि छापेमारी के दौरान पुलिस पर हमला हुआ, जिसमें उनके दो जवान घायल हो गए।

गया को केंद्र सरकार की सौगात, मिला 'कला ग्राम

गया। प्रदेश के ऐतिहासिक और धार्मिक राजधानी शहर गया को केंद्र सरकार से बड़ी सौगात मिली है। संस्कृति मंत्रालय ने यहां 'कला ग्राम' स्थापित करने की अपनी मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में यह योजना बिहार की सांस्कृतिक विरासत को और सशक्त बनाएगी। इसके तहत गया और पटना में कला ग्राम विकसित किए जाएंगे। इससे कला क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय कलाकारों को राष्ट्रीय फलक पर अपनी मुकम्मल पहचान बनाने के भी अवसर मिलेंगे। संस्कृति मंत्रालय के सचिव अरुनीश चावला ने राज्य

<ठङ्खली>सरकार को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि गया और पटना में कला ग्राम के लिए 5 से 10 एकड़ जमीन उपलब्ध कराई जाए। यह जमीन फ्रीहोल्ड या लीजहोल्ड किसी भी रूप में हो सकती है, लेकिन इसे पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखकर ही चुना जाना चाहिए। जमीन मिलते ही केंद्र सरकार इसके निर्माण, रखरखाव और संचालन का पूरा खर्च उठाएगी।

1 अप्रैल से स्कूलों में ऑटो, ई-रिक्शा बैन

पटना। बिहार पुलिस मुख्यालय के यातायात प्रभाग ने सभी जिले के ररढ और रढ को स्कूलों में चल रहे ऑटो, ई-रिक्शा पर सख्ती से कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। ऐसे में जिन स्कूलों में अभी भी बच्चे ऑटो, ई-रिक्शा से आते जाते दिखेंगे, वैसे वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई होगी। यह आदेश अगले 1 अप्रैल 2025 से पूरे राज्य के सभी स्कूलों के लिए प्रभावी होगा। बच्चों के हित में उठाया गया कदम पुलिस मुख्यालय के यातायात प्रभाग ने बच्चों के हित में यह कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय के यातायात प्रभाग को सूचना मिली थी कि अभी भी स्कूली वाहन के तौर पर नियमों की अनदेखी करते हुए धड़ल्ले से ऑटो, ई रिक्शा का इस्तेमाल किया

जा रहा है। जिससे सड़क दुर्घटना होने की संभावना अधिक है। इसलिए इसे प्रतिबंधित कर दिया गया है। मुख्यालय की ओर से कहा गया है कि किस तरह से इस दिशा में कार्रवाई की जा रही है, अब तक क्या कार्रवाई हुई, इससे संबंधित जानकारी भी कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। लोगों, स्कूलों, अभिभावकों को जागरूक करने के लिए मुख्यालय की ओर से प्रचार कर कराने का भी निर्देश दिया गया

घर से चोरी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, गहने बरामद

मुंगेर। से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। जहां एक महिला के दूसरे पति ने उसके जेवरात और नकदी लेकर फरार होने के बाद पीड़िता को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना कोतवाली थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। पीड़िता ने बताया कि वह पहले घरों में काम करती थी। जहां उसकी पहली शादी मुकेश यादव नाम के व्यक्ति से हुई थी। इस शादी से उनके चार बच्चे भी हैं। मुकेश शराब तस्करी में लिप्त था, जिस कारण पुलिस अक्सर घर पर छापेमारी करती थी। पुलिस की धमकियों से परेशान होकर महिला ने पति को छोड़ दिया। 6 महीने

पहले दिल्ली से लौटे थे दोनों जनवरी 2024 में सफियाबाद के महम्मदपुर सिंघिया निवासी मोहम्मद इफान (32) ने महिला को प्रेम जाल में फंसाया। महिला ने मंदिर में इफान से दूसरी शादी कर ली। छह महीने पहले इफान पीड़िता को दिल्ली ले गया। वहां कुछ दिन रहने के बाद दोनों मुंगेर लौट आए। यहां वे कासिम बाजार थाना क्षेत्र के अंबे चौक के पास किराए के कमरे में रहने लगे।पीड़िता ने बताया कि पिछले 10 दिनों से उसका पति कमरे पर नहीं आया। जांच में पता चला कि वह महिला के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गया है। महिला को जब अपने पति पर शक हुआ तो वह लगातार उसे फोन करने लगी। सोमवार की शाम उसके पति ने महिला को कोतवाली थाना क्षेत्र के नीलम चौक के पास मिलने के लिए बुलाया। जब महिला नीलम चौक के पास अपने पति के पास मिलने के लिए आई और उसे जब जेवरात के बारे में पूछ रहा था करने लगे तभी पति-पत्नी के बीच नोक झोंक हुई और वह मौके पर से भागना चाह रहा था जिसके बाद पत्नी ने उसे पकड़ लिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद और सभा को शुभ स्थानीय लोग मौके पर जुटे लेकिन मुस्लिम एरिया होने के कारण स्थानीय मुस्लिम समाज के लोगों ने उसके पति को वहां से भगा दिया तभी सूचना पर पहुंची कोतवाली थाना की पुलिस मौके पर पहुंच कर उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। अस्पताल की सूचना पर कोतवाली थाने की पुलिस सदर अस्पताल पहुंचकर मामले की जांच में जुटी हुई है।

'इस बेचारी का क्या है, पति हटा तो सी.एम बनाया

पटना। बिहार विधानमंडल में आरक्षण के मुद्दे को लेकर आज मंगलवार को हंगामा हुआ। राजद के विधायक और MLC ग्रीन कलर की टीशर्ट पहनकर पहुंचे हैं। टीशर्ट पर लिखा है- 'तेजस्वी सरकार के समय बिहार में बढ़ी 65 फीसदी आरक्षण को नौवीं अनुसूची में शामिल करो।' 'आरक्षण चोर BJP-NDA जवाब दो।' विधान परिषद में विपक्षी सदस्यों के टीशर्ट को देखकर मुख्यमंत्री भड़क गए। उन्होंने टीशर्ट पर लिखे स्लोगन को पढ़ते हुए राबड़ी देवी से बैठने को कहा। सीएम ने कहा- 'आपका क्या है, सब आपके हसबैंड का किया हुआ है। इस बेचारी को कुछ पता है। मैं तो यही पूछ रहा हूं कि क्यों इसे (स्लोगन वाले टीशर्ट) पहन कर आए हैं।' इस दौरान राबड़ी देवी बीच-बीच में उनके बयान का विरोध करती रहीं। नीतीश कुमार ने राबड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा-

इसका कोई मतलब है। कोई मतलब नहीं है। कोई काम नहीं करते थे ये लोग। विधान परिषद में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि 'जो मांग विपक्ष कर रहा है, उसे हम लोगों ने पारित किया है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट को फैसला लेने दीजिए।'सदन के बाहर पोर्टिको में विपक्ष के विधायक नारेबाजी कर रहे हैं। आरक्षण चोर के नारे लगा रहे हैं। आरक्षण के बढ़े दायरे को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर राजद विधायकों ने विधानसभा परिसर में मार्च किया। वहीं लालू के इफ्तार से कांग्रेस की दूरी पर आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र बोले- 'इंडिया गठबंधन पूरे देश के लिए है। बिहार में महागठबंधन में है। हम एक दूसरे के पूरक है। कांग्रेस और महागठबंधन के नेता तय कर चुके हैं कि तेजस्वी को सीएम बनाना है। ये सब सोचना फालतू है। कांग्रेस में राहुल और सोनिया गांधी बड़े नेता हैं। उसके बाद डायरेक्शन देने के लिए कौन बचता है पार्टी है।' डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सदन में कैग रिपोर्ट पेश की। कैग रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि कई जगह बेवजह पुल बना दिए गए। आबादी और जमीन की कमी के बावजूद पुल बनाए गए। इस निर्माण पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए। पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल में एक तरफ सड़क और पुल दोनों बने। वही दूसरी ओर न जमीन थी और न गांव थे। बाढ़ के घोषवरी प्रखंड के लक्ष्मीपुर गांव से कुम्हरा गांव तक सड़क बनाने के लिए 8.03 करोड़ रुपए खर्च किए गए। PMGS के तहत सड़क बनाई गई। नीरा उत्पादन में भारी गड़बड़ी का खुलासा भी कैग रिपोर्ट में हुआ है। नीरा परियोजना बिना तैयारी के शुरू की गई। बिना व्यावहारिकता ज्ञान के योजना शुरू होने से 11.68 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है। नीरा गुड़ उत्पादन पर 2.03 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बिहार विधानसभा में सोमवार को बिहार विनियोग विधेयक और मांग अनुदान पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार और इखढ पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूछा- 'मुख्यमंत्री को हाईजैक करके घर में क्यों रखा है।' तेजस्वी के बयान पर डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने हमला बोला। उन्होंने कहा- 'मैंने लालू जी के साथ भी काम किया। उनके पास कोई विचारधारा नहीं है। तेजस्वी मुझसे पूछते हैं, कभी संघ कार्यालय गए थे। मैं पूछता हूं, आपके पिताजी जब इखढ के साथ थे तो कितनी बार संघ कार्यालय गए थे।'

नागपुर के संघ कार्यालय जाएंगे तो आपकी किस्मत खुल जाएगी। वहां जाएंगे तो आपको घुसते से दिखेगा यादव निवास। फ्रर कार्यालय में यादव निवास भी बना हुआ है।

संक्षिप्त डायरी

प्रेग्नेंट पत्नी को मारकर घर से 3 किमी दूर दफनाया

नालंदा। 22 मार्च को पति ने अपनी 7 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी की हत्या कर दी। इसके बाद घर से 3 किलोमीटर दूर शव को दफना दिया। फिर साले को फोन पर कहा-तुम्हारी बहन को मारकर फेंक दिया है। घटना अस्थावां थाना क्षेत्र के तेलिया खंधा की है। मायके वालों ने बेटी को फोन करना शुरू किया तो संपर्क नहीं हो पाया। 23 मार्च को वो लेग महिला के ससुराल पहुंचे तो घर पर कोई नहीं था। ताला लगा था। फिर पुलिस को घटना की सूचना दी। परिजन और पुलिस महिला की खोजबीन कर रहे थे। इसी दौरान 24 मार्च को आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में शव को गड्ढे से बरामद किया। शव मिलने के बाद मायके वालों ने थाने में आवेदन दिया, जिसके आधार पर FIR दर्ज की गई। मृतका के भाई नीतीश कुमार पासवान ने 6 लोगों पर दहेज के लिए गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। वहीं, दूसरी तरफ मृतका के अवैध संबंध की भी चर्चा है। पुलिस सभी एंगल पर जांच कर रही है। मृतका की पहचान रूपेश पासवान की (28) वर्षीया पत्नी सोनी देवी के रूप में की गई है। दोनों की यह दूसरी शादी थी। 2018 में दोनों का विवाह हुआ था। 2 बेटियां भी है। एक की उम्र 2 और दूसरी 5 साल की है। बताया गया कि रूपेश की पहली पत्नी की मौत हो गई थी। कब हुई, किस कारण हुई, ये क्लियर नहीं है। होली के एक दिन बाद ससुराल गई थी बेटी वहीं, मृतका के पिता अरुण के बताया कि 'होली में बेटी अपने मायके आई हुई थी। त्योहार के एक दिन बाद सोनी ससुराल लौट थी।' 'जिस प्रखंड में सोनी रहती थी, उसी प्रखंड में उसकी बहन भी रहती है। जब दामाद रूपेश ने मेरे बेटे से कहा कि तुम्हारी बहन को मारकर फेंक दिए है तो हमने अपनी दूसरी बेटी से स्थिति के बारे में पता करने को कहा। तब उसने कहा था कि सब कुछ ठीक है।'

बिजली खंभे से टकराकर बाइक सवार घायल

दरभंगा। में तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। किसी ने डायल-112 पर एंबुलेंस को घटनास्थल पर भेजने के लिए कहा। एंबुलेंस को पहुंचने में आधा घंटे का समय लगा। देरी होने पर

आक्रोशित भीड़ ने चालक और ईएमटी के साथ बदसलूकी की। पब्लिक मूवमेंट को देखते हुए दोनों कर्मी वहां से निकल गए। जिसके बाद ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को लोगों ने लाठी-डंडे, ईंट-पत्थर क्षतिग्रस्त कर दिया। बताया जाता है कि घायल सीतामढ़ी जिला के बोखरा थाना क्षेत्र के सौरया निवासी मो. युनुस के बेटे मो. सुहैल गंभीर रूप से घायल हो गए। जाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉ. एनसी विश्वास ने बताया कि हालत नाजुक होने के कारण डीएमसीएच रेफर किया गया है। मरीज के सिर में गंभीर चोट लगी है। सिटी स्कैन करवाने की भी जरूरत है। ड्रेसर ने कहा कि प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को रेफर किया गया। घटना जाले थाना क्षेत्र के लतरहा गांव की है।एंबुलेंस कर्मियों ने जाले थाने में दिया आवेदन एंबुलेंस चालक और टेक्नीशियन ने बताया कि सड़क जाम के कारण घटनास्थल पर पहुंचने में आधा घंटा लग गया। मौके पर कुछ जागरूक नागरिकों ने कहा कि ऐसी स्थिति में लोगों को समझदारी दिखानी चाहिए। निजी वाहन का इस्तेमाल कर मरीज को जल्द अस्पताल पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकारी संपत्ति हमारी अपनी संपत्ति है, इसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। एंबुलेंस कर्मियों के साथ मारपीट गलत है। स्वास्थ्य सेवाओं में इनका अहम योगदान होता है। वहीं एम्बुलेंस चालक संजीव कुमार मिश्रा और ईएमटी शिव नारायण साह ने जाले थाना में आवेदन देकर कहा है कि घटनास्थल पर पहुंचते लोगों ने हमलोगों के साथ मारपीट, गाली-गलौज की। जबकि हमलोग सूचना मिलते ही पहुंच गए। सरकारी एम्बुलेंस को पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। ऐसे उग्र लोगों को चिह्नित कर उचित कानूनी कार्रवाई करने का आग्रह किया। डायल 112 की टीम घटनास्थल से क्षतिग्रस्त एंबुलेंस को जब्त कर थाने ले आई।

1.50 लाख का गहना लेकर बाबा फरार

समस्तीपुर। में गरीबी और कष्ट दूर करने के नाम पर गहने लेकर भागने का मामला सामने आया है। गांव में यज्ञ का पोस्टर चिपकाने आए दो बाबा ने घटना को अंजाम दिया है। ठगी होने के बाद पीड़ित महिला ने स्थानीय थाना में जाकर शिकायत दर्ज कराई है। आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। जिसमें महिला के घर के पास लगे सीसीटीवी में दोनों ठगों की तस्वीर कैद हो गई है। जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार, ठगों ने महिला को झांसा देने के बाद बहला-फुसलाकर डेढ़ लाख रुपए का जेवर लेकर फरार हो गया। घटना सोमवार के दिन जिले के वारिसनगर थाना क्षेत्र के गोही गांव का है। जहां माला देवी (24) के साथ ठगी हुई है।पीड़िता पीड़ित महिला ने बताया कि मेरे घर के बाहर दो बाबा आए और बोले कि हमें यज्ञ का पोस्टर चिपकाना है ,मैंने कहा कि चिपका लीजिए तभी वो मेरे घर के अंदर आए और बोले कि प्यास लगा है पानी पिला दीजिए। मैं उन्हें लोटा में पानी पीने के लिए दी। इस दौरान दूसरे वाले ने मुझसे मेरे घर परिवार और गहना के बारे में पूछा। मैं उन्हें सारी बातें बताई जिसके बाद वो बोले तुम्हारे ऊपर बहुत कष्ट है लो ये पानी पी लो। जब मैं पानी पी ली तो उसने कहा कि अपने सारे जेवर एक पन्नी में डाल कर रख दो और बचा हुआ पानी गांव के पोखर में फेंककर आ जाओ। वारिसनगर थाना अध्यक्ष निरंजन कुमार ने बताया कि पीड़ित महिला ने दो लोगों के खिलाफ आवेदन दिया गया है कि उसने करीब डेढ़ लाख रूपए के गहने की ठगी कर ली है। आवेदन के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। घर के पास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है। एक बाइक पर दो बाबा दिखाई पड़े हैं। पूरे मामले की जांच की जा रही है।

हरियाणा में खनन माफिया बना रहे रोड, अरावली पर्वत को काटकर 6 किलोमीटर बना डाली सड़क; देख अधिकारी हुए हैरान

नूंह जिले में अवैध खनन जैसी गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा : विश्राम कुमार मीणा

नूंह/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव। हरियाणा और राजस्थान के खनन माफिया अरावली पर्वत में जमकर खनन कर रहे हैं. मंगलवार को हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंफोर्समेंट ब्यूरो, वन और खनन विभाग के अधिकारियों की टीम ने यह सारा नजारा अपनी आंखों से देखा. जहां पर अरावली पर्वत को काटकर अवैध खनन करने वाले खनन माफियाओं ने छह किलोमीटर की सड़क बना डाली.

नूंह जिले के फिरोजपुर झिरका विधानसभा के वसई मेव गांव अरावली पर्वत के बीच में है, जहां दोनों तरफ राजस्थान की सीमाएं लगती हैं. खनन माफिया इसी का फायदा उठाते हैं और जमकर अवैध रूप से खनन करते हैं. उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि जिले में अवैध खनन जैसी गतिविधियों को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इसके लिए संबंधित विभाग निरंतर मॉनीटरिंग करे और जो भी व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए.उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि विभिन्न विभाग के अधिकारी फिरोजपुर झिरका के गांव रवां स्थित अरावली पहाड़ पर अवैध खनन संबंधी गतिविधियों का निरीक्षण कर रहे थे. अवैध खनन संबंधी गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के लिए खनन, इंफोर्समेंट ब्यूरो व वन विभाग के अधिकारियों को सख्त आदेश दिए गए हैं कि अगर कहीं पर भी उनके संज्ञान में अवैध खनन संबंधी मामलों का पता चलता है तो वे तुरंत उनके खिलाफ त्वरित कानूनी कार्रवाई अमल में लाएं. उन्होंने कहा कि सभी संभावित रास्तों, सड़क मार्गों पर भी वाहनों की चेकिंग की जाए. इसके लिए स्थानीय निवासियों का भी सहयोग लिया जा सकता है. पुलिस द्वारा भी इन स्थानों पर कड़ी निगरानी रखी जाए.

इस दौरान हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंफोर्समेंट ब्यूरो, वन व खनन विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे. उन्होंने गत दिनों राजस्थान सीमा में गिराए गए पहाड़ का मौके का भी निरीक्षण किया.

बताया कि गांव रवां के पास राजस्थान की सीमा से लगते अरावली पहाड़ के क्षेत्र में अवैध खनन की गतिविधियों की शिकायतें मिल रही हैं. इस क्षेत्र में अवैध खनन संबंधी गतिविधियों के लिए हरसेक से सर्वे करवाया जा रहा है, जिसकी तथ्यात्मक रिपोर्ट सरकार को भेजी जाएगी.

सरकार के निदेर्शानुसार ही आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. इस अवसर पर एस-डीएम फिरोजपुर झिरका लक्ष्मीनारायण, ड-ीएसपी अजायब सिंह, खनन विभाग के अधिकारी अनिल सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे.

जब इस बारे में फिरोजपुर झिरका के एस-डीएम लक्ष्मी नारायण से बात की तो उन्होंने भी बताया कि फिरोजपुर झिरका के राजस्थान बॉर्डर से लगाते हुए गांव में अवैध रूप से खनन किया जा रहा था.

इसके अलावा वहां पर वन विभाग के पेड़ों को काटकर और पहाड़ को काटकर अवैध रूप से सड़क भी बना दी गई, जिसका मौके पर निरीक्षण के लिए एक टीम चंडीगढ़ से भी पहुंची.

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति की अवधि को वर्ष 2026 तक बढ़ाया

चंडीगढ़/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में "हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022-25" की सफलता तथा राज्य भर के उद्यमियों से प्राप्त जबरदस्त प्रतिक्रिया के मद्देनजर इस योजना तथा इसके बाद की योजनाओं की संचालन अवधि को एक वर्ष बढ़ाकर 18 दिसंबर, 2026 तक करने का निर्णय लिया है।इसके अतिरिक्त, बैठक में सरकार ने वस्त्र इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना के तहत मामलों की संख्या पर लगी सीमा को हटाने का निर्णय लिया है। "हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022-25" को तीन वर्ष की अवधि के लिए 4000 करोड़ रुपये के लक्षित निवेश तथा 20,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ अधिसूचित किया गया था। इस वस्त्र नीति का उद्देश्य आधुनिक बुनियादी ढांचे के विकास, अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाने और कुशल और टिकाऊ उत्पादन प्रथाओं को बढ़ावा देने के माध्यम से उद्यमशीलता की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाकर कपड़ा क्षेत्र को मजबूत करना है। कपड़ा नीति भारत सरकार के 5एफ विजन - फार्म टू फाइबर टू फैक्ट्री टू फैशन टू फॉरेन के अनुरूप है।"हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022-25" के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए 8 प्रोत्साहन योजनाएं तैयार की गईं थी। इनमें कपड़ा इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी योजना, नेट एसजीएसटी के बदले निवेश सब्सिडी, हरित और टिकाऊ उत्पादन योजना को बढ़ावा देना, कौशल प्रशिक्षण योजना, अग्नि बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए सहायता, कपड़ा क्लस्टर विकास योजना और टेक्सटाइल पार्क योजना शामिल हैं। हरियाणा आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2022-25 राज्य के उद्यमियों के बीच अत्यधिक सफल रही है और इसने कपड़ा क्षेत्र में कई अनूठी परियोजनाओं में निवेश आकर्षित किया है। अधिसूचना के समय से अब तक सभी योजनाओं में 354 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 367.51 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता वाले 108 आवेदन पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। इस नीति के तहत एक प्रमुख योजना, जिसमें आवेदनों की भारी आमद हुई है, वह है 'वस्त्र इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना'। इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में जंबो बैग, ग्राउंड टर्फ, एंटीबैक्टीरियल तौलिए, ऐक्रेलिक सुपर सॉफ्ट कंबल, पेट टू फाइबर आदि जैसे अनूठे उत्पादों वाली कपड़ा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये परियोजनाएं कपड़ा क्षेत्र के विकास को दशार्ती हैं और तकनीकी कपड़ा इकाइयों/आयात प्रतिस्थापन/पिछड़ा एकीकरण, ओपन एंड स्पिनिंग और अपशिष्ट से फाइबर श्रेणी और कपड़ा उद्यमों की सभी श्रेणियों सहित कई श्रेणियों को शामिल करती हैं। उन्नत प्रौद्योगिकी, रणनीतिक उत्पादन और निर्यात अभिविन्यास के इस संयोजन ने हरियाणा को कपड़ा उद्योग में एक प्रमुख केंद्र के रूप में मजबूती से स्थापित किया है। कपड़ा इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना के दिशा-निदेर्शों के अनुसार, नीति की परिचालन अवधि के दौरान अधिकतम 86 मामले (व्यक्तिगत श्रेणी के लिए 84 और एंकर इकाइयों के लिए 02) वित्तीय प्रोत्साहन के लिए पात्र हैं। हालाँकि, आज तक, कुल 85 परियोजनाओं (84 व्यक्तिगत श्रेणी की परियोजनाएँ और 1 एंकर परियोजना) को पहले ही 352.56 करोड़ रुपये की अनुदान सहायता के साथ मंजूरी दी जा चुकी है। इन स्वीकृत परियोजनाओं से राज्य में 1574.51 करोड़ रुपये का निवेश आने का अनुमान है और अनुमानित रूप से 10,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। कपड़ा इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना को राज्य भर के उद्यमियों से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। आवेदन जमा करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बंद होने के बावजूद लगभग 50 नए आवेदन पाइपलाइन में हैं। यहां यह उल्लेख करना भी वाजिब होगा कि इस योजना ने प्रभावी रूप से निवेश आकर्षित किया है। इसके अतिरिक्त, कई संभावित उद्योगपतियों ने राज्य भर में कपड़ा इकाइयाँ स्थापित करने में गहरी रुचि दिखाई है, जो इस क्षेत्र के लिए बढ़ते उत्साह का संकेत है। इसके अलावा, कई प्रमुख उद्योग संघों ने इस योजना के तहत नए आवेदनों पर विचार करने का आग्रह करते हुए प्रतिनिधित्व प्रस्तुत किया है, जो राज्य के कपड़ा उद्योग के भीतर व्यापक अपील और विकास की क्षमता को दशार्ता है। कपड़ा इकाइयों के लिए पूंजी निवेश सब्सिडी योजना के तहत प्रोत्साहन के लिए पात्र मामलों की संख्या पर सीमा को हटाने से 4,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने और 20,000 व्यक्तियों के लिए रोजगार पैदा करने के प्रमुख उद्देश्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने छोटे करदाताओं के लिए योजना को और सरल बनाने हेतु 'हरियाणा बकाया राशि की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना 2025' में संशोधन को दी मंजूरी

चंडीगढ़/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव। चंडीगढ़/ भव्य खबर/ रमण श्रीवास्तव । हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आज चंडीगढ़ में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों के मद्देनजर ह्यहरियाणा बकाया राशि की वसूली के लिए एकमुश्त निपटान योजना 2025ह्न में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की गई।भाजपा के संकल्प पत्र के अनुरूप संशोधित योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे करदाताओं को लाभ पहुंचाना है। इस योजना के तहत, जिस आवेदक पर किसी संबंधित अधिनियम के तहत सभी वर्षों में, 10 लाख रुपये तक का कर बकाया है, उसे एक लाख रुपये की छूट मिलेगी। उल्लेखनीय है कि छोटे व्यापारियों के बकाए का प्रतिशत काफी अधिक है, जो 10 लाख रुपये से कम है और वे इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

आवेदक नियत तिथि से 180 दिनों के भीतर इस योजना का विकल्प चुन सकता है। संबंधित अधिनियम की किसी भी धारा के तहत लगाए जाने वाले ब्याज के साथ-साथ जुमार्ना भी संबंधित अधिनियम के तहत उस विशेष वर्ष के लिए माफ कर दिया जाएगा, जिसके लिए आवेदक ने आवेदन किया है। इसके अलावा, योजना के तहत वसूल की जाने वाली बकाया राशि को, योजना के लिए आवेदन की तिथि तक बकाया राशि के आधार पर निर्धारित की जाएगी।जीएसटी व्यवस्था में बकाया राशि, मुकदमेबाजी के बोझ को कम करने तथा बकाया राशि की वसूली में तेजी लाने के उद्देश्य से सरकार ने इस निपटान योजना को शुरू करके करदाताओं की मात्रात्मक बकाया राशि का निपटान करने का निर्णय लिया है। वसूली संबंधी चुनौतियों और विभिन्न स्तरों पर विवादित मांगों के कारण, लंबे समय से बड़ी मात्रा में बकाया राशि लंबित पड़ी हुई है।

पंजाब के स्कुल व कोचिंग सेंटरों में सरेआम चल रहा ये खेल, सीबीएसई बेखबर

लुधियाना : डमी एडमिशन करने वाले स्कूलों पर सख्ती बरतने के संकेत देते हुए बेशक केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने यह साफ कर दिया था कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ एक्शन जारी रहेगा लेकिन इसके बावजूद कई स्कूल ऐसे हैं जिन पर न तो केंद्र सरकार की सख्ती का कोई असर है और न सी.बी.एस.ई. द्वारा पिछले दिनों ऐसे स्कूलों की हुई चैकिंग की कोई परवाह। यही वजह है कि जिले के कई स्कूल अभी भी धड़ल्ले से डमी एडमिशन कर रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि कोचिंग सैंटर संचालकों की सैटिंग के साथ ही स्कूल इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं जिससे बोर्ड की सख्ती पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

दरअसल 10वीं की परीक्षाएं खत्म होने के बाद अब मैडीकल व नॉन-मैडीकल क्षेत्र में अपना करियर बनाने वाले विद्यार्थी क्रमशः नीट व जे.ई.ई. की तैयारी को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। इस शृंखला में जब कोई छात्र किसी भी कोचिंग सैंटर में उक्त एंट्रैंस एग्जाम की तैयारी के लिए जाता है तो उसे स्कूल में डमी एडमिशन करवाने की गारंटी भी सैंटर से दी जा रही है। बाकायदा कोचिंग सैंटर की ओर से ही छात्र को स्कूल का नाम व फीस अलग से बताया जाता है जिसकी एवज में छात्र को पहले उक्त कोचिंग सैंटर में ही एडमिशन लेनी होगी। सूत्र बताते हैं कि इनमें एक-दो नामी स्कूल भी हैं जो इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं जबकि एक स्कूल तो डमी एडमिशनों के सहारे ही चल रहा है। इसके साथ ही ग्रामीण इलाकों में बने कई स्कूल भी डमी एडमिशन को बढ़ावा दे रहे हैं लेकिन सी.बी.एस.ई. की टीमों का ध्यान इन स्कूलों पर नहीं है।

मैडीकल-नॉन मैडीकल एंट्रैंस एग्जाम की तैयारी ने खत्म किया क्लास कल्चर

दरअसल मैडीकल-नॉन मैडीकल के एंट्रैंस एग्जाम की तैयारी ने क्लास कल्चर को खत्म कर दिया है। कई सी.बी.एस.ई. स्कूलों ने डमी एडमिशन को भरपूर प्रोत्साहन दिया है। पिछले कई वर्ष से कुछ स्कूल तो सिर्फ एग्जामिनेशन सैंटर बनकर रह गए हैं। हालात ये हैं कि इन स्कूलों में डमी एडमिशन लेने वाले 11वीं-12वीं के विद्यार्थियों की कोई क्लास नहीं लगती। हालांकि जिले के अधिकांश स्कूल सीनियर सैकेंडरी तक हैं लेकिन इनमें से कइयों में तो 10वीं के बाद रैगुलर फैकल्टी तक नहीं है। कोचिंग सैंटर अपने करार वाले स्कूलों में खुलेआम 11वीं-12वीं के बच्चों को डमी एडमिशन दिलाते हैं जबकि स्कूल बच्चे की अटैंडैंस पूरी करने की एवज में कथित तौर पर अलग से रकम वसूल रहे हैं।सी.बी.एस.ई. का नियमः नियमित स्कूल आना लाजिमी सी.बी.एस.ई. के नियमों के मुताबिक बोर्ड एग्जाम के लिए नियमित स्कूल आना और न्यूनतम हाजिरी की शर्त पूरा करना जरूरी है। ऐसे ही मामले में सी.बी.एस.ई. ने गत दिनों बहुत से स्कूलों के 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं में रजिस्ट्रेशन और कैंडिडेट लिस्ट के डाटा का विश्लेषण किया। जांच के आधार पर स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। पिछले वर्ष सितम्बर में 27 स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की गई। 21 स्कूलों की तो एफीलिएशन खत्म कर दी गई और 6 स्कूलों को डाऊनग्रेड कर दिया गया। मौजूदा समय में स्कूलों में डमी एडमिशन चल रही हैं जिसमें दाखिला लेने वाले विद्यार्थी पूरा दिन अपने एंट्रैंस एग्जाम की तैयारी के लिए कोचिंग सैंटर में ही मिलेंगे। रैगुलर के लिए 20 तो डमी एडमिशन वाले छात्र के लिए 60 हजार तक है फीस

कई ऐसे स्कूल हैं जो डमी एडमिशन के नाम पर हर साल मोटे रुपए बटोर रहे हैं। डमी एडमिशन करने वाले इन स्कूलों की रैगुलर छात्रों के लिए एडमिशन फीस भले ही 20 से 25 हजार रुपए है लेकिन डमी एडमिशन के नाम पर 55 से 65 हजार रुपए तक अलग से वसूल रहे हैं।

खबर एक्सप्रेस

नशे के खिलाफ एक्शन में पंजाब पुलिस, डीआईजी स्वपन शर्मा ने किया इस थाने का दौरा

अबोहर : डी.आई.जी. फिरोजपुर रेंज स्वपन शर्मा आई.पी.एस. ने आज अबोहर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने यहां के सदर थाने का निरीक्षण किया और स्टाफ के साथ बैठक कर विभाग की कार्यप्रणाली की समीक्षा की। इस अवसर पर फाजिल्का के एस.एस.पी. वरिंदर सिंह बराड़ विशेष रूप से उनके साथ उपस्थित थे। इस मौके पर स्वपन शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार के दिशा-निदेर्शों के अनुसार डी.जी.पी. गौरव यादव आई.पी.एस. के नेतृत्व में पुलिस द्वारा नशे के खिलाफ युद्ध अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी में संलिप्त प्रत्येक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है तथा समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए बड़ी मुहिम शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा सप्लाई चेन को तोड़ा जा रहा है तथा इस कार्य में जनता का भी प्रमुख योगदान मिल रहा है। इस मौके पर एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पुलिस गश्त और बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थ तस्करों पर पुलिस की कार्रवाई के परिणामस्वरूप अधिक लोग इलाज के लिए नशा मुक्ती केंद्रों में आ रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने पुलिस थाने की कार्यप्रणाली की समीक्षा की तथा कहा कि यहां काम के लिए आने वाले लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्यकुशलता बढ़ाई जा रही है ताकि लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।

पंजाब शिक्षा विभाग का सख्त एक्शन, इस बड़े अधिकारी को किया सस्पेंड

लुधियाना : पंजाब शिक्षा विभाग की ओर से पंकज अंगी डिप्टी जिला शिक्षा अधिकारी (सै.सि.) फाजिल्का, पी.ई.एस. ग्रुप-ए को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के कारण पंजाब सिविल सेवाएं (सजा और अपील) नियमांवाली 1970 के नियम 4 (1) अनुसार सरकारी सवाओं से तुरंत प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है। संस्पेशन के दौरान उसका हेड क्वार्टर दफ्तर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन (सैकेंडरी) पंजाब नियुक्त किया जाता है। सस्पेंशन के दौरान अधिकारियों को नियमों अनुसार गुजारा भत्ता मिलेगा। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे।

पंजाब में युवक ऑन डिमांड पर कर रहा था यह काम, चढ़ा पुलिस के हत्थे

लुधियाना : थाना डिवीजन नंबर 3 की पुलिस ने सूचना के आधार पर कश्मीर नगर चौंक के निकट एक नशा तस्कर को 26 ग्राम चिटटे सहित काबू किया है। आरोपी तस्कर की पहचान अंकेश कुमार निवासी शीतल कालोनी ताजपुर रोड के रुप में हुई है। 24 वर्षीय आरोपी तस्कर आरोपी मोटरसाइकिल पर ऑन डिमांड चिटटा बेचता है। जांच अधिकारी गुरमेल सिंह ने बताया कि पुलिस ने सूचना के आधार पर नाकाबंदी की हुई थी। आरोपी मोटरसाइकिल पर कश्मीर नगर चौंक की तरफ आ रहा था जोकि पुलिस को देख पीछे मुड़ भागने लगा जिसे पुलिस ने धर दबोचा। तलाशी दौरान आरोपी से 26 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ है। आरोपी पर एन.डी.पी.एस. एक्ट का पहला केस दर्ज हुआ है। जबकि आरोपी करीब 4 महीने से मोटरसाइकिल पर ऑन डिमांड चिट्टा बेच रहा था। जांच अधिकारी ए.एस.आई गुरमेल सिंह ने बताया कि आरोपी पहले चिट्टे का सेवन करता था परंतु डाक्टरी उपचार के बाद उसने चिट्टा छोड़ दिया परंतु जल्द अमीर बनने के चक्कर में वह ऑन डिमांड घूम-घूम कर चिट्टा बेचने लगा। जिसे पुलिस ने सूचना के आधार पर काबू कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एन.डी.पी.एस. एक्ट के अधीन केस दर्ज कर लिया है जिसे अदालत समक्ष पेश कर रिमांड हासिल किया है।

देह व्यापार के आरोप में पकड़ी गई महिला का कारनामा, पुलिस के उड़े होश

लुधियाना : देह व्यापार के आरोप में पकड़ी गई महिलाओं में से एक सिविल अस्पताल में मेडिकल करवाने के दौरान बाथरूम का बहाना बनाकर पुलिस मुलाजिम के धक्का देकर फरार हो गई। उसे पकड़ने के लिए पुलिस मुलाजिम उसके पीछे भागे मगर भीड़ का फायदा उठाते हुए आरोपी महिला भाग गई। इस मामले में थाना डिवीजन नंबर-2 की पुलिस ने कांस्टेबल जसप्रीत सिंह की शिकायत पर आरोपी महिला परमजीत कौर के खिलाफ केस दर्ज किया है। जसप्रीत सिंह के मुताबिक परमजीत कौर सहित छह महिलाओं को देह व्यापारी के आरोप में पकड़ा था। आरोपी महिलाओं को लेकर वह मेडिकल करवाने के लिए सिविल अस्पताल गए थे। जहां पर डाक्टर ने महिलाओं को यू.पी.टी. टैस्ट करवाने के लिए कहा था। आरोपी परमजीत कौर टेस्ट के लिए महिला पुलिस कर्मचारी के साथ बाथरूम गई थी। जहां पर उसने महिला पुलिस कर्मचारी को धक्का दिया और भीड़ का फायदा उठाकर भाग निकली।

कनाडा में पंजाबी युवक के साथ अनहोनी, परिवार में मचा कोहराम

मजीठा : ब्लाक मजीठा के गांव तरगढ़ रामपुरा का युवक नवजोत सिंह (24) जो कुछ समय पहले रोजी-रोटी की तलाश में कनाडा गया था, वहां गोली लगने से उसकी मौत हो गई। खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया। नवजोत सिंह के पिता कुलदीप सिंह ने बताया कि गोली लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है कि गोली उन्हें कैसे लगी।

विदेश से आई बेहद दुखद खबर, जिंदा जल गए 2 पंजाबी युवक

पंजाब : हॉलैंड के प्रसिद्ध शहर एम्सटर्डम से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक मोटरवे पर कल सुबह 4 बजे एक रेफ्रिजरेटेड ट्रक के एक अन्य वाहन से टकरा जाने से दो पंजाबी युवकों की मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार, भारी वाहन को पवनजीत सिंह (27) होशियारपुर बड़ी तेज रफ्तार से चला रहा था, जबकि एक युवक पुनीत कुमार उसके बगल वाली सीट पर बैठा था। यह दुर्घटना पवनजीत की लापरवाही के कारण हुई, जिससे वह हाईवे पर आगे चल रहे एक रेफ्रिजरेटर ट्रक से पीछे से टकरा गया। दुर्घटना के कारण वाहनों में आग लग गई और दोनों युवक जलकर मर गए। इस बीच, कैंटर का चालक अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष कर रहा है।

बढ़ रही है इमेज कंसल्टैंट सेवाओं की मांग

भारत में लगातार बढ़ती जा रही प्रतिस्पर्धा की वजह से अपनी इमेज मैनेज करना भी एक अहम जरूरत बन चुकी है। अधिक से अधिक लोग अब इस जरूरत को महसूस कर रहे हैं जिस वजह से देश में इमेज कंसल्टैंट की सेवाओं की मांग में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है।

इमेज कंसल्टिंग के तहत लोगों को अपने भीतर छुपी क्षमताओं को निखारने और साथ ही साथ उन क्षमताओं को सभी के समक्ष प्रदर्शित करने के लिए अपनी अपीयरैंस (दिखावट) के प्रबंधन हेतु मार्गदर्शन किया जाता है। इमेज कंसल्टिंग के तहत लोगों को परिधान पहनने व तैयार होने के ढंग, बॉडी लैंग्वेज, शिष्टाचार एवं सॉफ्ट स्किल्स के बारे में शिक्षित किया जाता है। इमेज कंसल्टैंट व्यक्तिगत रूप से तथा समूह में कोचिंग प्रदान करते हैं। वे किसी एक व्यक्ति अथवा कम्पनियों को अपनी सेवाएं देते हैं। वे लोगों के लिए मुक्त कार्यशाला भी आयोजित करते हैं। इस क्षेत्र से जुड़े कार्यों में पर्सनल शॉपिंग, यूनिफॉर्म डिजाइन, इमेज मैनेजमैंट, पॉलिसी डिजाइन, स्टाइलिंग आदि भी शामिल हैं। भारत में लगातार बढ़ती जा रही प्रतिस्पर्धा की वजह से अपनी इमेज मैनेज करना भी एक अहम जरूरत बन चुकी है। अधिक से अधिक लोग अब इस जरूरत को महसूस कर रहे हैं जिस वजह से देश में इमेज कंसल्टैंट की सेवाओं की मांग में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है।

यह ऐसा करियर है, जिसमें व्यक्ति अन्य लोगों के विकास का मुख्य सहयोगी बनता है तथा अन्य लोगों को और अधिक सफल बनाने से उसे सफलता मिलती है। यह क्षेत्र उन महिलाओं को करियर बनाने का दूसरा मौका देता है जिन्होंने कुछ समय के लिए अपने पहले करियर को छोड़ रखा हो। इमेज कंसल्टिंग बिजनैस इंस्टीच्यूट भारत में इमेज कंसल्टैंसी की शिक्षा तथा प्रशिक्षण देने वाला अग्रणी संस्थान होने के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर भी एक प्रतिष्ठित संस्थान है। यह संस्थान इमेज कंसल्टिंग एवं बिजनैस प्रोग्राम संबंधी अनोखे पेशेवर कोर्स करवाता है। इस संस्थान की डायरैक्टर सुमन अग्रवाल भारतीय उपमहाद्वीप की वरिष्ठतम इमेज कंसल्टैंट मानी जाती हैं। उनकी कहानी भी एक उत्तम प्रेरणा स्रोत है। उन्हें कॉलेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देनी पड़ी थी परंतु आज वह एक सफल उद्यमी तथा इस संस्थान की डायरैक्टर हैं। यूनाइटेड किंगडम स्थित फैडरेशन ऑफ इमेज प्रोफैशनल इंटरनैशनल द्वारा उन्हें इमेज मास्टर अवार्ड से नवाजा गया जिससे वह भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वाधिक वरिष्ठ इमेज कंसल्टैंट बन गईं। इमेज कंसल्टिंग में पहनावे के महत्व पर वह कहती हैं, ''80 प्रतिशत से अधिक संवाद दृश्य होता है और पहनावा इसका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी आप किसी से मिलते हैं तो व्यक्ति का सबसे अधिक ध्यान सामने वाले के पहनावे पर ही जाता है। हालांकि यह बताना जरूरी है कि पहनावे के संबंध में कौशल एक इमेज कंसल्टैंट के पास होता है, वह सर्वश्रेष्ठ फैशन डिजाइनर समेत किसी अन्य पेशेवर के पास नहीं हो सकता है। महत्व बढ़िया परिधानों का नहीं होता, बल्कि उस संदेश का होता है जो आप अपने पहनावे से सामने वाले को देना चाहते हैं। सही पहनावे को सुनिश्चित बनाने के लिए व्यक्ति को अपने काम, लक्ष्यों एवं मौके का ध्यान रखने के अलावा आकर्षक दिखने के लिए अपने शारीरिक ढांचे, रंग-रूप, चेहरे के आकार आदि पर भी गौर करना पड़ता है।'' उनके अनुसार इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए यह एक उत्तम एवं बेहद लाभदायक करियर साबित हो सकता है।

कॉस्मेटिक समस्याओं का निदान करते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट

मेडिसिन में स्पेशलाइजेशन के लिए उपलब्ध विकल्पों में 'डर्मेटोलॉजी' काफी लोकप्रिय हो गया है। मौजूदा वक्त में 'फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन' कहावत को इतनी गंभीरता से लिया जा रहा है कि व्यक्ति के रूप को व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण अंग माना जाने लगा है। इस कारण लोगों में अपने रूप और व्यक्तित्व को लेकर चिंता का स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। यहां तक कि कॉलेज जाने वाले छात्र भी खुद को आकर्षक दिखाने की गरज से काफी रुपये खर्च कर रहे हैं। अपने रूप को लेकर लोगों में गंभीरता का स्तर इस कदर बढ़ गया है कि वह चेहरे पर छोटा-सा मुंहासा हो जाने भर से परेशान हो उठते हैं। कई बार वह ऐसी परेशानियों को इस कदर अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि घर से बाहर निकलना भी छोड़ देते हैं। ऐसे माहौल में रूप निखारने का दावा करने वाली फेयरनेस क्रीमों की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। खुजली और घमौरियों (रैशेज) जैसे त्वचा संबंधी रोग आम हो चुके हैं। गर्मी और बरसात के मौसम में इनकी अधिकता काफी बढ़ जाती है। इनके सही उपचार के लिए डॉक्टर का परामर्श जरूरी होता है। कई बार उपचार के लिए डॉक्टर के पास कुछ दिनों या हफ्तों के अंतराल पर बार-बार जाने की जरूरत होती है। ऐसे में लोग अपनी त्वचा के लिए ज्यादा खर्च करने में जरा भी नहीं हिचकते। त्वचा और रूप के प्रति लोगों के बढ़ती सजगता के कारण डर्मेटोलॉजिस्ट की मांग में इजाफा हो रहा है। डर्मेटोलॉजी मेडिसिन की एक शाखा है, जिसमें त्वचा और उससे संबंधित रोगों के निदान का अध्ययन किया जाता है। यह एक स्पेशलाइज्ड विषय है, जिसकी पढ़ाई एमबीबीएस के बाद होती है। डर्मेटोलॉजिस्ट रोगों के उपचार के अलावा त्वचा, बाल और नाखूनों से संबंधित कॉस्मेटिक समस्याओं का भी निदान करते हैं।

डर्मेटोलॉजिस्ट का काम

इनका मुख्य कार्य लोगों की उन बीमारियों का उपचार करना होता है, जो त्वचा, बाल, नाखूनों और मुंह पर दुष्प्रभाव डालती हैं। एलर्जी से प्रभावित त्वचा, त्वचा संबंधी दागों, सूर्य की रोशनी में झुलसे या अन्य तरह के विकारों से ग्रसित त्वचा को पूर्व अवस्था में लाने में ये रोगियों की मदद करते हैं। इसके लिए वह दवाओं या सर्जरी का इस्तेमाल करते हैं। त्वचा कैंसर और उसी तरह की बीमारियों से जूझ रहे रोगियों के उपचार में भी वह सहयोग करते हैं। क्लिनिक या अस्पताल में वह सबसे पहले मरीजों के रोग प्रभावित अंग का निरीक्षण करते हैं। जरूरी होने पर वह रोग की गंभीरता जांचने के लिए संबंधित अंग से रक्त, त्वचा या टिश्यू का नमूना भी लेते हैं। इन नमूनों के रासायनिक और जैविक परीक्षणों से वह पता लगाते हैं कि रोग की वजह क्या है। रोग का पता लगने के बाद उपचार शुरू कर देते हैं। इस कार्य में वह दवाओं, सर्जरी, सुपरफिशियल रेडियोथेरेपी या अन्य उपलब्ध उपचार विधियों का उपयोग करते हैं।

करते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी

चेहरे और अन्य अंगों को आकर्षक बनाने के लिए डर्मेटोलॉजिस्ट कॉस्टमेटिक सर्जरी भी करते हैं। त्वचा की झुर्रियों और दाग-धब्बों को खत्म करने के लिए वह डर्माब्रेशन जैसी तकनीक और बोटोक्स इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इन तकनीकों के अलावा वह लेजर थेरेपी का भी उपचार में उपयोग करते हैं। इस तकनीक की मदद से वह झुर्रियों और त्वचा पर होने वाले सफेद दाग का ईलाज करते हैं।

योग्यता - फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ बारहवीं पास करके एमबीबीएस डिग्री प्राप्त करना डर्मेटोलॉजिस्ट बनने की पहली शर्त है। इसके बाद डर्मेटोलॉजी, वेनेरियोलॉजी और लेप्रोलॉजी में तीन वर्षीय एमडी या दो वर्षीय डिप्लोमा की पढ़ाई की जा सकती है।

लोगों में प्रतिभा तो होती है परंतु उसे समझने और निखारने की आवश्यकता होती है. उन्हें प्रशिक्षण मुहैया कराने के लिए कई संस्थानों में संबंधित कोर्स संचालित किए जा रहे हैं.

करियर को दिशा देती है सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग

सॉफ्ट स्किल की क्षमता आपके करियर को नई दिशा देती है. अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग तकनीकी रूप से बड़े प्रतिभावान होते हैं. साथ ही, वे अपने क्षेत्र में निपुण भी होते हैं किंतु एक निश्चित बिंदु पर उनके करियर में ठहराव-सा आ जाता है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें नेतृत्व क्षमता, समूह में काम करना, सामाजिक सम्प्रेषण और संबंध निर्माण आदि कौशल का अभाव होता है. सॉफ्ट स्किल व्यापक क्षेत्र है, जिसमें सम्प्रेषण कौशल, श्रवण कौशल, टीम कौशल, नेतृत्व के गुण, सृजनात्मकता और तर्कसंगत, समस्या निवारण, कौशल और परिवर्तनशीलता आदि सम्मिलित हैं. सॉफ्ट स्किल के गुण किताबों से नहीं सीखे जाते, बल्कि इसके लिए प्रशिक्षण कारगर होते हैं. यदि आप सही अर्थों में अपने व्यक्तित्व में सॉफ्ट स्किल्स जोड़ना चाहते हैं तो आपको एक अच्छा, मेहनती और सीखने वाला बनकर उन सब बातों को, जो कुछ भी आपने व्यावहारिक रूप से ग्रहण किया है, व्यवहार में लाना होगा. कुछ ऐसे सॉफ्ट स्किल्स भी हैं जो आपकी रोजगार की संभावनाओं और व्यक्तित्व में सुधार कर स्थायी और अच्छी सैलरी पर नौकरी प्राप्त करने में सहयोग करता है.

प्रभावी सम्प्रेषण

कौशल प्रभावी सम्प्रेषण कौशल में सार्वजनिक भाषणों, प्रस्तुतीकरण, बातचीत, संघर्ष समाधान ज्ञानिवतरण आदि के लिए मौखिक कौशल, अनुदेश मैनुअल तैयार करना, ज्ञापन, सूचनाएं लिखना, कार्यालयीन पत्र व्यवहार आदि के लिए लेखन कौशल शामिल हैं. इनमें मौखिक और गैर-मौखिक, दोनों ही शामिल है. चूंकि हमारा सम्प्रेषण का आधिकारिक माध्यम अंग्रेजी है, इसलिए इसमें कुछ हद तक अंग्रेजी में दक्षता होनी जरूरी है.

सामूहिक कार्य

कौशल अंतर्वैयक्तिक और सामूहिक कार्य कौशल उच्चतर उत्पादकता तथा बेहतर वातावरण के लिए योगदान करते हैं क्योंकि इनसे व्यक्ति संयुक्त लक्ष्य हासिल करने हेतु मिलकर कार्य करते हैं. यह सम्प्रेषण टीम सदस्यों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया की स्थापना, फीडबैक का आमंत्रण, उसे प्रदान करना तथा संघर्ष की स्थिति को हल करना अपेक्षित होता है.

ज्ञानात्मक कौशल

अपने रोजमर्रा के जीवन में अक्सर आपको ऐसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है जब आप सही फैसले करने में असमर्थ होते हैं. आपके सामने ऐसी स्थितियां उत्पन्न होने की ज्यादा संभावनाएं उस वक्त होती हैं जब आप किसी संगठन में कार्य करते हैं. ऐसी दबावपूर्ण स्थितियों का मुकाबला करने के लिए आपको कुछेक ऐसे कौशल विकसित करने की आवश्यकता है जो आपको निर्णय लेने, सृजनात्मक एवं अन्वेषणात्मक समाधान विकसित करने, व्यावहारिक हल ढूंढने, समस्याओं का स्वतंत्र रूप से पता लगाने, उनको हल करने और विभिन्न क्षेत्रों में समस्याओं के निदान में कार्य नीतियां लागू करने में मददगार हो सकते हैं.

नौकरियां

आजकल ज्यादातर संगठन अपने कर्मचारियों में उनके सकारात्मक, सम्प्रेषण, अंतर्वैयक्तिक और टीम कौशल, समस्या निदान, अनुकूलनशीलता और कार्य पद्धति में सुधार हेतु प्रशिक्षण प्रदान करते हैं. इससे एक तरफ जहां उनके व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी तरफ संगठन की उत्पादकता में भी वृद्धि होती है. अत- सॉफ्ट स्किल में पाठ्यक्रम पूरा करने के उपरांत कोई व्यक्ति किसी निजी या सार्वजनिक संगठन में सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षक के रूप में रोजगार प्राप्त कर सकता है. इसके अलावा, आप अपना स्वयं का ट्रेनिंग सेंटर भी खोल सकते हैं.

व्यक्तित्व संबंधी गुण

समय के साथ-साथ अब फोकस एक सामान्य व्यक्ति से सुशिक्षित और परिष्कृत व्यक्तित्व की ओर हो गया है. विभिन्न संगठनों, खासकर कंपनियों को ऐसे व्यक्तियों की तलाश रहती है जो कुशाग्र और सुशिक्षित होते हैं. उनमें ऐसे सम्प्रेषण कौशल होने चाहिए कि वे सबसे आगे रहें. इसके लिए वे अपने कर्मचारियों को भर्ती के उपरांत प्रशिक्षण प्रदान करते हैं लेकिन वे उन व्यक्तियों को वरीयता देते हैं जो पहले से अपने क्षेत्र में बेहतर होते हैं. चूंकि ज्यादातर लोग प्रतिभाओं के साथ जन्म लेते हैं, परंतु उन्हें परिष्कृत और शिक्षित करने की आवश्यकता होती है. उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बाजार में बहुत से संस्थान संचालित किए जा रहे हैं. ये संस्थान काफी धन अर्जन कर रहे हैं और इस तरह सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षकों को आकर्षक रोजगार का विकल्प प्रदान कर रहे हैं.

वेतन

इस सेक्टर में काफी अच्छा वेतन है. चूंकि यह कल्चर प्राइवेट कंपनियों और वैश्वीकरण के कारण तेजी फला-फूला है, इसलिए इसकी ग्रोथ भी ज्यादा है.

योग्यताएं

पहले इस फील्ड में पाठ्यक्रम नहीं चलाए जाते थे लेकिन अब सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षकों के लिए शिक्षण कार्य भी एक अच्छे विकल्प के रूप में उभरकर सामने आया है क्योंकि सभी इंजीनियरिंग और प्रबंध संस्थानों में तकनीकी कौशल एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल होता है. वहां पर छात्रों को साक्षात्कार और समूह चर्चा में बेहतर प्रदर्शन के लिए अपेक्षित अन्य वैयक्तिक कौशलों के साथ-साथ प्लेसमेंट और सम्प्रेषण कौशलों के लिए प्रशिक्षित और तैयार किया जाता है.

करियर उन्मुखी होते हैं पत्राचार पाठ्यक्रम

आज सभी विषयों में ग्रैजुएशन तथा मास्टर डिग्री कोर्स के अलावा अनेक सर्टीफिकेट कोर्स एवं डिप्लोमा भी पत्राचार माध्यम से दूरस्थ शिक्षा के रूप में उपलब्ध हैं। इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को सभी संबंधित विषयों का बुनियादी ज्ञान प्रदान करना होता है।

कुछ प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश एक चयन परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है। पत्राचार शिक्षा ने हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन ला दिया है। पत्राचार माध्यम से अध्ययन करने वाले छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न आधुनिक तकनीकों का सहारा भी दिया जा रहा है। उपग्रह संचार, लो पावर ट्रांसमीटर्स की सहायता एवं सूचना सुपर-हाइवेज के माध्यम से देश भर में शिक्षा का प्रसार हो रहा है। देश में अनेक मुक्त विश्वविद्यालय तथा उससे भी अधिक नियमित विश्वविद्यालय तथा कई अन्य संस्थाएं दूरस्थ अध्ययन कार्यक्रम चलाते हैं। दूरस्थ शिक्षा पद्धति कई श्रेणियों के शिक्षार्थियों, विशेष रूप से देरी से पढ़ाई शुरू करने वालों, जिन व्यक्तियों के घर के पास उच्चतम शिक्षा साधन नहीं है, सेवारत व्यक्तियों और अपनी शैक्षिक योग्यताएं बढ़ाने के इच्छुक व्यक्तियों को लाभ प्रदान कर रही है। मुक्त विश्वविद्यालय ऐसे लचीले पाठ्यक्रम विकल्प देते हैं जिन्हें वे छात्र ले सकते हैं जिनके पास कोई औपचारिक योग्यता नहीं है किन्तु अपेक्षित आयु (प्रथम डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए 18 वर्ष) के हो चुके हैं और लिखित प्रवेश परीक्षा भी उत्तीर्ण कर चुके हैं। ये पाठ्यक्रम छात्र अपनी सुविधानुसार भी ले सकते हैं। विश्वविद्यालयों के दूरस्थ शिक्षा केंद्र न्यूनतम पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को प्रवेश देते हैं। यह पात्रता नियमित पाठ्यक्रमों के समान ही होती है। पत्राचार शैक्षिक संस्थाएं छात्रों को पाठ्यक्रम सामग्री के साथ-साथ संपर्क कक्षाएं भी उपलब्ध कराती हैं और परीक्षाएं संचालित करती हैं। अधिकांश विश्वविद्यालय मुद्रित अध्ययन सामग्री के अलावा अपने स्थानीय केंद्रों पर मल्टीमीडिया साधनों से भी छात्रों को शिक्षित करते हैं। ये विश्वविद्यालय ग्रैजुएशन पाठ्यक्रम, मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम, एम.फिल पीएच.डी. तथा डिप्लोमा एवं सर्टीफिकेट पाठ्यक्रम भी चलाते हैं जिनमें से अधिकांश पाठ्यक्रम करियर उन्मुखी होते हैं।

पहली बार में क्रैक करना है आईआईटी जेईई तो अपनाएं ये आसान टिप्स

अगर आप आईआईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ जरूरी टिप्स को अपनाना बिल्कुल न भूलें। इनकी मदद से आप पहली बार में एग्जाम क्लियर कर पाएंगे

जेईई मेन्स जेईई मेन्स की परीक्षा में अच्छे पर्सेंटाइल लाने वाले कैंडिडेट्स जेईई एडवांस्ड की तैयारी में जुट चुके हैं। साल भर की मेहनत तो बेहतर रिजल्ट का कारण है ही साथ ही परीक्षा से पहले अंतिम दिनों की मेहनत भी अत्यधिक मायने रखती है। आज हम आपको यहां बता रहे हैं जेईई मेन्स परीक्षा को क्रैक करने और एडमिशन पाने की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए जरूरी टिप्स।

ऐसे करें एग्जाम की तैयारी

- अपनी सिली मिस्टेक्स पर काम करने का प्रयास करें क्योंकि इससे आपके ओवरऑल स्कोर में सुधार होगा।
- मॉक टेस्ट लेने और पिछले वर्ष के प्रश्नों को ऑनलाइन हल करने से आपको विभिन्न प्वाइंटस को एनलाइज करने में मदद मिलेगी।
- सब्जेक्ट वाइज फॉर्मूला शीटतैयार करें, ऐसा करके आप फॉर्मूले को रिवाइज करने करने के लिए हर समय अपने साथ रख सकते हैं।
- एक डेली टाइम टेबल तैयार करें और मुख्य रूप से रिवीजन और ऑनलाइन टेस्ट पर ध्यान केंद्रित करें क्योंकि ये टेस्ट आपके स्कोर को 40-50% तक सुधारने में मदद करते हैं।
- स्टडी के दौरान छोटे ब्रेक लें या संगीत सुनें क्योंकि यह कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाता है।
- सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परीक्षा नजदीक आने पर खुद को स्वस्थ और फिट रखें।

जेईई एडवांस्ड फिजिक्स को क्रैक करने के टिप्स

- **फॉर्मूले अच्छी तरह से सीखें :** जैसे ही आप फिजिक्स का रिवीजन करते हैं, सभी फॉर्मूले को नोट कर लें और उन्हें अच्छी तरह से याद रखें।
- **स्कोरिंग टॉपिक पर कंसंट्रेट करें :** एक बार आपके बेसिक चैपर को रिविजन करने के बाद, मॉर्डन फिजिक्स, वेव ऑप्टिक्स, अल्टरनेटिंग करंट, साउंड वेव्स जैसे स्कोरिंग टॉपिक्स पर ध्यान केंद्रित करें। थर्मोडायनामिक्स पर अतिरिक्त ध्यान दें क्योंकि यह फिजिक्स और केमेस्ट्री के लिए सामान्य है।
- **डेलिगेट प्रैक्टिस :** जेईई एडवांस पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना आवश्यक है। इन्हें सॉल्व समय फोकस्ड और कॉन्फिडेंट रहें।

जेईई एडवांस्ड केमिस्ट्री क्रैक करने के टिप्स

- **अपनी प्रिपरेशन को सिस्टमेटिक रूप से तैयार करें :** फिजिक्स और इनऑर्गेनिक केमेस्ट्री से फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना शुरू करें। अपने समय का एक बड़ा हिस्सा ऑर्गेनिक केमेस्ट्री की तैयारी में दे। लास्ट 5 दिनों के लिए क्वालिटेटिव एनालिसिस छोड़ दें क्योंकि इसमें मुख्य रूप से याद रखने की आवश्यकता होती है।
- ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल मैकनिज्म पहली बार में जटिल लग सकता है। कठिन टॉपिक के लिए ज्यादा गहराई में न जाएं क्योंकि अंतिम दिनों में समय की कमी होती है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए छोटे नोट्स बनाने की जरूरत होती है।
- **रिएक्शन की प्रैक्टिस करें :** सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स, इक्वेशन, मैकनिज्म और रिलेटेड प्रॉब्लमस का रेगुलर प्रैक्टिस करें।
- **रेगुलर रिवीजन :** केमिस्ट्री कई छात्रों को कंफ्यूज करने वाली लगती है। बेहतर रिटेंशन के लिए केमिस्ट्री का रेगुलर रिवीजन जरूरी है।

जेईई एडवांस मैथ्स को क्रैक करने के टिप्स

- **कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी :** पहले सभी चैप्टर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें। मैथ्स फॉर्मूला से भरा है। उन्हें अच्छी तरह से करने के लिए, फार्मूला के विभिन्न एप्लीकेशन की प्रैक्टिस करें।
- **मॉक टेस्ट दें :** फुल लेंथ वाले जेईई एडवांस मॉक टेस्ट देने से आपकी स्पीड और एक्यूरेसी में सुधार करने में मदद मिलती है।
- **प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करें :** प्रत्येक चैप्टर को रिवाइज करने के बाद जेईई एडवांस लेवल के प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करना आवश्यक है।
- **पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को सॉल्व करें :** जब आप जेईई एडवांस मैथ्स की तैयारी कर रहे हों तो जेईई एडवांस्ड पिछले साल के टेस्ट से प्रैक्टिस करना जरूरी है।

क्या भूत बंगला में अक्षय के साथ स्क्रीन शेयर करने वाले हैं राम चरण

अक्षय कुमार और मशहूर निर्देशक प्रियदर्शन की हॉरर कॉमेडी फिल्म भूत बंगला इन दिनों सुर्खियों में है। फिल्म की शूटिंग जोरों पर चल रही है। हाल ही में इसका एक शेड्यूल जयपुर मैनशन में पूरा हुआ है। इस लोकेशन पर फिल्म की कई अहम सीन फिल्माए गए हैं। इस बीच एक चौंकाने वाली खबर ने फैंस का ध्यान खींचा। साउथ के सुपरस्टार राम चरण की एक तस्वीर फिल्म के सेट से लीक हो गई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है।

लीक हुई राम चरण की तस्वीर

लीक हुई तस्वीर में राम चरण को प्रियदर्शन के साथ बातचीत करते देखा गया। दोनों के बीच गहरी चर्चा चल रही थी। कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद वे किसी सीन को लेकर बात कर रहे थे। वहीं, कुछ का मानना है कि यह महज एक संयोग हो सकता है। हो सकता है कि राम चरण पास में किसी दूसरी फिल्म की शूटिंग कर रहे हों और प्रियदर्शन से मिलने चले आए हों।

अक्षय-राम चरण साथ आएंगे नजर?

इस तस्वीर के बाद फैंस के मन में एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या अक्षय कुमार और राम चरण साथ में स्क्रीन शेयर करने वाले हैं? अगर ऐसा हुआ तो यह बड़े पर्दे पर बड़ा पैन-इंडिया धमाका होगा। हालांकि, अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि फिल्म के रिलीज के साथ कोई बड़ा सरप्राइज सामने आ सकता है।

ये सितारे भी हैं फिल्म में मौजूद

प्रियदर्शन के निर्देशन में बन रही भूत बंगला में अक्षय कुमार मुख्य भूमिका में हैं। उनके साथ इस फिल्म में परेश रावल, वामिका गब्बी, तब्बू, राजपाल यादव और जिशु सेनगुप्ता जैसे शानदार कलाकार भी नजर आएंगे। फिल्म में हॉरर के साथ कॉमेडी का तड़का भी देखने को मिलेगा। यह फिल्म 2 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।

वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में अक्षय कुमार को फिल्म स्काई फोर्स में देखा गया था। यह इस साल की पहली 100 करोड़ रुपये कमाने वाली हिंदी फिल्म थी। वहीं, राम चरण को गेम चेंजर नाम की फिल्म में देखा गया था। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा सकी थी।

सिंगिंग डेब्यू पर मन्नारा चोपड़ा बोलीं, संगीत मेरे दिल के करीब

अभिनेत्री, बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट मन्नारा चोपड़ा सिंगिंग में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। अजीब दास्तान में वह अपनी आवाज देती नजर आएंगी। गाने को आवाज देने के साथ ही मन्नारा ने म्यूजिक वीडियो के कुछ हिस्सों का निर्देशन भी किया है, जिसमें न्यूयॉर्क शहर की शानदार पृष्ठभूमि पर तैयार पुरानी दुनिया की धुनों के आकर्षण को खूबसूरती से दिखाया गया है। इस नए काम को लेकर उत्साहित मन्नारा ने कहा, संगीत हमेशा मेरे दिल के करीब रहा है। यह गीत इसलिए खास है, क्योंकि इसमें क्लासिक्स के प्रति मेरे प्यार को मेरे अपने कलात्मक स्पर्श के साथ मिलाया गया है। मैं कुछ ऐसा बनाना चाहती थी, जो व्यक्तिगत होने के साथ-साथ यूनिवर्सल भी लगे और मुझे उम्मीद है कि लोग इससे उसी तरह जुड़ेंगे, जैसे मैं जुड़ती आई हूं।

अजीब दास्तान है ये मूल रूप से 1960 की फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई से है, जिसमें मीना कुमारी, राजकुमार, जे. ओम प्रकाश, नादिरा, हेलेन और नाज ने अभिनय किया। इस गाने को दिवंगत गायिका लता मंगेशकर ने गाया है और इसे शैलेंद्र ने लिखा है। 33 वर्षीय अभिनेत्री मन्नारा का जन्म हरियाणा के अंबाला कैंटोनमेंट में हुआ था, उन्होंने 40 से अधिक विज्ञापनों में काम किया है। अभिनय की शुरुआत से पहले वह एक फैशन डिजाइनर और सहायक कोरियोग्राफर के रूप में भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने हिप हॉप और बेली डांसिंग जैसे नृत्य रूपों में प्रशिक्षण लिया। मन्नारा ने 2014 में अभिनय की दुनिया में कदम रखा और तेलुगू, तमिल, हिंदी और कन्नड़ जैसी विभिन्न भाषाओं की फिल्मों में काम किया। उन्होंने श्रीराम चंद्रा के साथ 2014 की तेलुगू फिल्म प्रेमा गीमा जंता नाई से अपने अभिनय की शुरुआत की।

उन्होंने अनुभव सिन्हा की जिद से हिंदी में शुरुआत की, जिसमें उनके साथ करणवीर शर्मा भी थे। 2015 में चोपड़ा ने दो तमिल फिल्मों के एक गाने में विशेष भूमिका निभाई थी। मन्नारा थिक्का में साई धरम तेज के साथ मुख्य भूमिका भी निभाई। मन्नारा 2017 में रॉग से कन्नड़ फिल्म में डेब्यू कर चुकी हैं। वह साल 2023 में सलमान खान के शो बिग बॉस के 17वें सीजन में शामिल हुई थीं।

हर इंडस्ट्री में मौजूद है जेंडर आधारित भेदभाव

एक्ट्रेस पूजा हेगड़े ने इंडस्ट्री में महिला कलाकारों के साथ होने वाली लैंगिक भेदभाव पर बात की है। पूजा ने अपने साथ हुए कुछ अनुभवों को भी शेयर किया है। एक इंटरव्यू में एक्ट्रेस से पूछा गया कि क्या उन्हें कभी भी किसी मेल को-एक्टर से परेशानी हुई है? जवाब में वो कहती हैं- 'यह सभी इंडस्ट्री में होता है लेकिन अलग-अलग स्तर पर। इनमें से कुछ बहुत ही खुले रूप में है और कुछ बहुत ही शटल तरीके में। छोटी-छोटी चीजें होती हैं। जैसे कि मेल एक्टर की वैनिटी वैन सेट के पास खड़ी होती है। जबकि हमें अपने लहंगे को उठाकर दूर तक चलाना पड़ता है।' मैं कभी-कभी सोचती हूं, हमारे बारे में भी सोचो। हमें इतनी भारी भरकम कपड़ों में अपने वैन तक पहुंचने के लिए खुद को घसीटना पड़ता है। ये एक शटल सेक्सिज्म है। यह भी हो सकता है कि आपका नाम पोस्टर में न हो। कभी-कभी आपको क्रेडिट तक नहीं दिया जाता, जबकि भले ही फिल्म लव स्टोरी ही क्यों न हो? हम सबको समझना होगा कि फिल्म बनाना एक कलेक्टिव एफर्ट है। पूजा आगे कहती हैं कि उन्होंने कई ऐसे मेल को-स्टार के साथ काम किया है, जिन्होंने दशकों की मेहनत से अपनी पहचान बनाई है। लेकिन जहां टेक्निकली वो बड़ी स्टार रही हैं, उन्हें वहां भी सेट पर दूसरे दर्जे का एहसास कराया गया है।

पूजा के काम की बात करें तो इन्होंने तमिल, तेलगु और हिंदी तीनों इंडस्ट्री में काम किया है। पूजा मिस यूनिवर्स इंडिया 2010 की रनर अप भी रह चुकी हैं। 2012 में तमिल फिल्म से अपने करियर की शुरुआत की थी। हाल में शाहिद कपूर के साथ इनकी फिल्म 'देवा' रिलीज हुई थी। इस फिल्म में एक्ट्रेस ने एक जर्नलिस्ट की भूमिका निभाई थी।

जिंदगी जीने के तरीके को लेकर तमन्ना भाटिया का बड़ा खुलासा

बॉलीवुड अभिनेत्री तमन्ना भाटिया अपनी खूबसूरती और बेबाकी के लिए जानी जाती हैं। अपने कथित बॉयफ्रेंड विजय वर्मा से ब्रेकअप की अफवाहों के बाद अब तमन्ना भाटिया ने अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर कुछ खुलासे किए हैं, जो उनके लिए काफी निजी तौर पर मायने रखते हैं। कथित तौर पर तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा के बारे में यही खबरें आ रही थीं कि वे कुछ समय तक एक-दूसरे के साथ रिश्ते में रहने के बाद अब अलग हो गए हैं। हालांकि, अभी तक दोनों में से किसी ने भी इस बात की पुष्टि नहीं की है। लोगों का कहना है कि तमन्ना शादी करना चाहती थीं, लेकिन विजय अपने करियर पर ध्यान देना चाहते थे। खबर के मुताबिक, तमन्ना ने हाल ही में अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वह अपनी निजी बातों को सबसे छुपाकर रखती हैं और केवल वही बताती हैं, जो उन्हें ठीक लगता है। जब उनसे पूछा गया कि वह अपनी निजी जिंदगी को कैसे छुपाती हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्हें लोगों से मिलना-जुलना पसंद है। वह एयरपोर्ट पर भी फैंस के साथ खुशी-खुशी तस्वीरें खिंचवातीं हैं। उनका कहना है कि उन्होंने यह काम चुना है और उन्हें लोगों के बीच रहना अच्छा लगता है। तमन्ना को अजनबियों से बात करना भी पसंद है। उनका मानना है कि इससे उन्हें गहरी बातचीत करने का मौका मिलता है। वह कहती हैं कि वह अपनी जिंदगी के बारे में जितना बताना चाहती हैं, उतना ही बताती हैं और उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है।

राहुल बोस ने खुद को बताया स्टारलेट

आपको 2003 में आई फिल्म 'चमेली' तो याद ही होगी। फिल्म में करीना कपूर के साथ राहुल बोस मुख्य भूमिका में नजर आए थे। हालांकि, राहुल बोस का ये मानना है कि उस फिल्म की प्रमुख स्टार करीना कपूर ही थीं। साथ ही अभिनेता ने ये भी बताया कि फिल्म की उनकी फीस करीना को मिली फीस का एक छोटा सा हिस्सा मात्र थी।

अभिनेता राहुल बोस ने बॉलीवुड में वित्तीय असमानता पर भी खुलकर बात की। अभिनेता ने कहा, पुरुष अभिनेताओं ने भी वर्षों से स्टारलेट की भूमिका निभाई है। मैं खुद इसका एक उदाहरण हूं। फिल्म 'चमेली' में मैं स्टारलेट था और करीना स्टार थीं। वो आज भी मुझसे ज्यादा लोगों को थिएटर में ला सकती हैं।

अभिनेता ने आगे कहा, फिल्म 'चमेली' में मुझे करीना के मुकाले कम पैसे मिले थे। जो कि तार्किक भी है। जो लोग ज्यादा लोगों को थिएटर में बुला सकते हैं, बेहतर होगा कि उनके अनुपात का ध्यान भी रखा जाए और ऐसा हुआ भी है। यह पैटर्न कायम रहा, क्योंकि मैं कभी भी ऐसा अभिनेता नहीं था जो दर्शकों को सिनेमाघरों तक ले आए।

राहुल बोस ने आगे पैसों के भुगतान के मामले पर बात करते हुए कहा, मुझे बॉलीवुड में पैसों के भुगतान का पैट्रेन सही लगता है। यहां कलाकार की कमाई उसके बॉक्स ऑफिस अपील पर टिकी होती है। जो जितने लोगों को थिएटर में ला सकता है, उसे उस हिसाब से भुगतान किया जाएगा। खुद दो फिल्मों का निर्माण करने के बाद अभिनेता ने ये महसूस किया है कि उन्होंने खुद को जितना भुगतान किया, उससे ज्यादा नहीं किया होता। लैंगिक वेतन असमानता पर बहस को खारिज करते हुए, उन्होंने कहा कि प्रणाली सीधी है, अगर कोई अभिनेता राजस्व लाता है, तो वे अधिक कमाते हैं, यदि नहीं, तो उनका वेतन इसे दर्शाता है।

कंटेंट वाली फिल्मों को लेकर एकता कपूर की खरी-खरी

ब्रिटिश वेब सीरीज एडोलसेंस इस समय काफी चर्चा में है। अनुराग कश्यप और हंसल मेहता सहित कई अभिनेताओं और फिल्म निर्माताओं ने इस सीरीज की प्रशंसा की है। निर्माता एकता कपूर ने अपने साथी फिल्म निर्माताओं के विचारों पर अपनी राय रखी। एकता ने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर एक सीरीज शेयर की। उन्होंने लिखा कि भारत में क्वालिटी कंटेंट क्यों संघर्ष करता है? उन्होंने सवाल किया कि क्या समस्या फिल्म निर्माताओं के साथ थी या दर्शकों के साथ? एकता ने लिखा, सुपरबॉयज ऑफ मालेगांव और मेरे प्यारे दोस्त हंसल मेहता की बकिंघम मर्डर्स सिनेमाघरों में नहीं चलती तो क्या हम असली दोषियों को दोष दे सकते हैं? एकता कपूर ने क्रिप्टिक पोस्ट लिखते हुए कहा कि भारतीय फिल्म निर्माताओं को जोखिम लेने और परियोजनाओं में अपना पैसा निवेश करने की जरूरत है। एकता कपूर ने क्रिएटर्स को कंटेंट वाली फिल्मों में अपना पैसा लगाने का आग्रह किया, उन्होंने कहा, क्रिएटर्स मैं आपसे सिस्टम से लड़ने का आग्रह करती हूं, ये पैसे के भूखे, कॉर्पोरेट स्टूडियो और ऐप्स केवल पैसे (मैं भी शामिल हूं) और नंबरों के बारे में सोचते हैं! मूवी मेकिंग, कंटेंट क्रिएशन कोई बिजनेस नहीं है। यह एक कला है और मैं कला का समर्थन करना चाहता हूं, इसलिए मैं क्रिएटर्स से अपना पैसा लगाने का आग्रह करता हूं।

पंजाबी फिल्म को बॉलीवुड से जोड़ने पर हिना खान ने की गिप्पी ग्रेवाल की तारीफ

अभिनेत्री हिना खान ने हाल ही में पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री और बॉलीवुड के बीच की खाई को पाटने के लिए अभिनेता और गायक गिप्पी ग्रेवाल की प्रशंसा करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया। गिप्पी की अपकमिंग एक्शन फिल्म 'अकाल' दुनिया भर के सिनेमाघरों में हिंदी में रिलीज होने वाली पहली पंजाबी फिल्म होगी। करण जौहर की धर्मा प्रोडक्शंस आगामी पंजाबी फिल्म का हिंदी वर्जन प्रस्तुत कर रही है। हिना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक भावुक नोट शेयर किया, जिसमें उन्होंने गिप्पी और उनके परिवार के साथ अपने हालिया मुलाकात की तस्वीरें शेयर कीं। कुछ तस्वीरों में अभिनेत्री गिप्पी के बेटे गुरफतेह सिंह ग्रेवाल (शिंदा) के साथ पोज देती नजर आईं।

हिना ने पोस्ट के साथ कैप्शन में लिखा, पिछली रात मैं अपने परिवार से मिली, जो हमेशा मेरे साथ रहे हैं... गिप्पी आप एक प्योर सोल हैं और आपका दिल गोल्डन है। इसके साथ ही हिना ने रवनीत के लिए खूबसूरत लाइन्स लिखी, उन्होंने कहा, रवनीत आपको जैसे ही मेरे इलाज के बारे में पता चला, आप तभी से मेरे बारे में पूछती रहीं और हालचाल लेती रहीं। आपने कभी भी मेरा हालचाल पूछना बंद नहीं किया और अपनी सर्जरी से ठीक पहले आपके द्वारा मेरे लिए रखे खास पथ और अरदास को मैं कभी नहीं भूल सकती।

अभिनेत्री ने कहा, मेरा इस परिवार के साथ एक बहुत ही खास रिश्ता है.. यह परिवार हमेशा प्यार और खुशी के साथ फलता-फूलता रहे। गिप्पी को पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को बॉलीवुड के साथ जोड़ने के लिए बहुत-बहुत बधाई और 'अकाल' के लिए शुभकामनाएं। तुसी तो छा गए, ढेर सारा प्यार हमेशा। बता दें, गिप्पी ग्रेवाल न केवल अकाल में अभिनय कर रहे हैं, बल्कि प्रोजेक्ट के निर्देशक और लेखक के रूप में भी हैं। फिल्म में निमरत खैरा, अपिंदरदीप सिंह, मीता वशिष्ठ, प्रिंस कंवलजीत सिंह, निकितिन धीर, गुरप्रीत घुग्गी, शिंदा ग्रेवाल, एकोम ग्रेवाल और जग्गी सिंह जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं।

'अकाल' 10 अप्रैल, 2025 को पंजाबी और हिंदी में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। करण जौहर 'अकाल' के साथ पंजाबी फिल्म में डेब्यू करने जा रहे हैं। रण जौहर ने इस प्रोजेक्ट से जुड़ने पर गर्व व्यक्त करते हुए एक भावुक नोट शेयर किया। उन्होंने लिखा, पंजाबी सिनेमा में शुरुआत के साथ टैलेंटेड गिप्पी ग्रेवाल संग जुड़ने पर गर्व है। अकाल न केवल पंजाब की संस्कृति और इतिहास का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि मुझे विश्वास है कि यह पूरे भारत और उससे परे के लोगों के साथ गहरे स्तर पर जुड़ सकेगा। यही वजह है कि हमें अकाल को दुनिया भर के सिनेमाघरों में हिंदी में रिलीज होने वाली पहली पंजाबी फिल्म के रूप में पेश करने पर और भी गर्व है...ताकि सिनेमा का जादू सीमाओं से परे भी जीतता रहे।

कॉमेडी फिल्म में साथ नजर आएंगे अक्षय कुमार-जॉन अब्राहम? क्या है सच

जॉन अब्राहम ने हाल ही में कॉमेडी फिल्म के लिए अपने अभिनेता अक्षय कुमार के साथ रियूनियन का संकेत दिया है। इससे पहले यह जोड़ी गरम मसाला और देसी बॉयज सहित कई प्रतिष्ठित कॉमेडी फिल्मों में स्क्रीन स्पेस साझा कर चुकी है। जॉन से दोनों फिल्मों के सीक्वल की संभावना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने उत्साह व्यक्त किया उन्होंने कहा- हां, हम इनमें से किसी एक या दोनों फिल्मों को बनाने को लेकर बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि वे मजेदार होंगी। जॉन ने अक्षय के साथ अपने रिश्ते के बारे में कहा- मुझे नहीं लगता कि अन्य दो अभिनेताओं के बीच अक्षय और मेरे बीच जैसी केमिस्ट्री है। उन्होंने यह भी दावा किया कि अक्षय के साथ काम करना छुट्टी मनाने जैसा लगता है, वह एक अच्छे इंसान हैं, इसलिए हम अच्छा समय बिताएंगे।

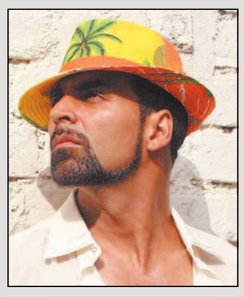

स्वामी, मुद्रक व प्रकाशक अमृता आर पंडित द्वारा साई प्रिंटिंग प्रेस, बी- 868, न्यू अशोक नगर दिल्ली 110096 से मुदित तथा ए-115, गली नंबर 13, नई अशोक नगर, दिल्ली 110096 से प्रकाशित।
संपादक - अमृता आर पंडित, मो 8587969284, Mail ID - live18newsnetworktv@gmail.com सभी विवादों के न्याय क्षेत्र दिल्ली न्यायालय में होगा।